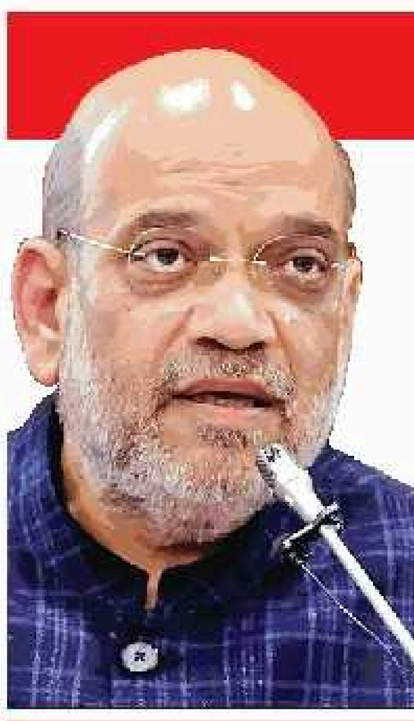

राष्ट्रीय संस्करण

आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते सिमी पर प्रतिबंध पांच साल और बढ़ा >>7

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 232

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, मंगलवार, 30 जनवरी, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

संपादकीय

संभव है एक साथ चुनाव: देश में एक साथ चुनाव दुष्कर अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। इस मामले में जर्मनी जैसे कुछ देशों की व्यवस्था का अनुसरण उपयोगी हो सकता है।

डा. एके वर्मा का आकलन।

साकार हो गांधी के राम राज्य का सपना: गांधी जी रामराज्य की बात इसीलिए करते थे, क्योंकि उनके लिए राम मानव जीवन के उच्चतम आदर्श थे। **राधेश्याम प्रसाद तिवारी** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

भारतीय राजनीति में एग्म और पीएम: बिहार में रविवार को जदयू औपचारिक रूप से राजग में शामिल हो गया है। नीतीश और उनके नेताओं ने आगामी चुनावों में जीत के लिए भाजपा का सहयोग आवश्यक समझा, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अभी तक यह नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे विश्लेषित कर रहे हैं, ओमप्रकाश तिवारी।

ममता की शर्तों के जाल में उलझी कांग्रेस: बंगाल में आइएनडीआइए का मामला काफी उलझा हुआ है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को माकपा या तृणमूल में से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य कर दिया है, जिसे रेखांकित कर रही जयकृष्ण वाजपेयी की डायरी। ● पेज-9

सप्तरंग

अंतस और अध्यात्म का

संकल्प से सिद्धि की ओर

आध्यात्मिक योद्धा बनकर भीतर के कौरवों से युद्ध

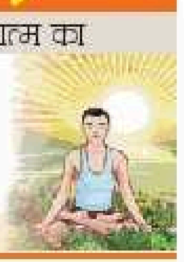

● पेज-13

जागरण विशेष

जहरीली गैस को निष्क्रिय करेगा ये पाउडर

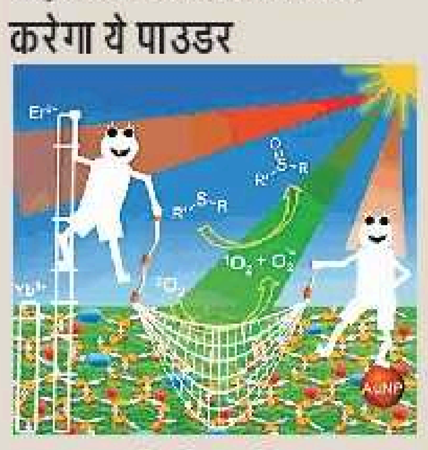

भोपाल: भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के विज्ञानियों ने बेहद जहरीली मस्टर्ड गैस को निष्क्रिय करने की स्वदेशी विधि विकसित की है। ● पेज-14

न्यूज गैलरी

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

अगले वित्त वर्ष भी सात प्रतिशत रह सकती है विकास दर

नई दिल्ली: दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं जहां दो प्रतिशत की विकास दर हासिल करने को संघर्ष कर रही हैं वहीं भारत ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भी सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

भारतीय युद्धपोत ने अपहृत जहाज और चालक दल को छुड़वाया

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने ईरान के झंडे वाले एक जहाज की ओर से मिली अपहरण की सूचना पर कार्रवाई कर अपहृत जहाज और उसके चालक दल के सभी 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़वा लिया।

छात्र खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरों से नहीं : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छात्रों से कहा कि हमें परीक्षा ही नहीं बल्कि किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। अपने आपको ऐसे किसी भी दबाव को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनना चाहिए। 'परीक्षा पे चर्चा' के सातवें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरों से नहीं। उन्होंने छात्रों को परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने, तकनीक का उपयोग और दोस्तों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखने सहित मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करने की सीख दी।

पीएम मोदी सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे। करीब दो घंटे चले सत्र में पीएम ने छात्रों के सभी सवालों का न सिर्फ खुलकर जवाब दिया, बल्कि उन्हें संतुष्ट करने की भी कोशिश की। उन्होंने छात्रों से परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव से बचने के लिए, छोटी-छोटी गलतियों से बचने की सलाह दी। जैसे परीक्षा में नए कपड़े पहनने से बचें। नई पेन से बचें। परीक्षा शुरू होने तक किताबों से चिपके न रहें। परीक्षा में ऐसा कुछ भी न खाएं, जिससे दिक्कत हो। परीक्षा शुरू होने से पहले मन को शांति दें। परीक्षा कक्ष में शांति से बैठें। दोस्तों के बीच हंसी-ठहाके लगाएं। गहरी सांसें लें। आठ-दस मिनट ऐसा करें। फिर देखेंगे कि जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो आपको तनाव नहीं होगा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। देश के युवा उनके इस सपने को पूरा करेंगे। पीएम मोदी का छात्रों के साथ चर्चा का यह सातवां संस्करण था। इसके लिए, देश-दुनिया के 2.27 करोड़ से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

(मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं: पेज-3)

(छात्रा ने कोटा में दी जान: पेज-6)

- 'परीक्षा पे चर्चा' में पीएम ने छात्रों को परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन के दिए मंत्र
- कहा, किसी भी तरह का दबाव झेलने के लिए खुद को बनाएं सामर्थ्यवान
- तकनीक का इस्तेमाल और दोस्तों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखने की भी दी सलाह

नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में सोमवार को 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान देशभर के बच्चों को टिप्स देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न बनाएं माता-पिता

प्रधानमंत्री मोदी ने माता-पिता को अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड मानने के प्रति आगाह किया। कहा कि बच्चों को दबाव से निपटने में मदद करने के लिए उनमें लचीलापन पैदा करना महत्वपूर्ण है। माता-पिता और शिक्षकों को सामूहिक रूप से उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि अभिभावक अपने बच्चों पर भरोसा रखें। उनकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें। मोदी ने कहा कि माता-पिता और बच्चों के बीच विश्वास की कमी एक गंभीर मुद्दा है और इससे पैदा हुई दूरी बच्चों को अवसाद में धकेल सकती है।

पीएम का छात्रों को सुझाव

- अपने स्वास्थ्य को लेकर उसी तरह सतर्क रहें, जैसे मोबाइल की बैटरी को लेकर रहते हैं। रोज कुछ घंटे अपने शरीर की फिटनेस के लिए जरूर दें। मोबाइल की बैटरी की तरह शरीर को भी चार्जिंग की जरूरत होती है।
- परीक्षा की तैयारी के दौरान रोज लिखने का जरूर अभ्यास करें। इससे विषय अच्छे तरीके से तैयार होंगे।
- मोबाइल फोन का घंटों तक इस्तेमाल से बचें। रात-रात भर रील्स देखने से नींद कम आती है। यदि स्वस्थ रहना और दिमाग को भी स्वस्थ रखना है, तो अच्छी और पर्याप्त नींद जरूर लें।
- विषयों के चयन में खुद पर भरोसा रखें। माता-पिता के अपने प्रति भरोसे को कमजोर न होने दें।

शिक्षकों से कहा, बच्चों के साथ जुड़ाव रखें

- पीएम ने शिक्षकों से कहा, कक्षाओं में सभी बच्चों के साथ एक समान जुड़ाव रखें।
- जुड़ाव सिर्फ सिलेबस तक नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे बढ़कर भी बनाना चाहिए।
- इससे छात्र खुलकर अपनी बात शिक्षक के सामने रख सकेंगे और शिक्षक भी छात्र की कमजोरी को पहचान सकेंगे।

'सौर पैनल लगवाने वाले सभी घरों का बिजली बिल आएगा जीरो'

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली सौर नीति 2024 की घोषणा करते हुए इसे जनता से लिए बड़ी राहत बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि नई नीति लागू होने पर सौर पैनल लगवाने पर दिल्ली के अंदर आवासीय एरिया में रहने वाले सभी घरों का बिजली बिल जीरो आएगा। साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा। यही नहीं उन्हें 700 से 900 रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। (पेज-2)

एलएसी पर हालात स्थिर, लेकिन संवेदनशील : सेना प्रमुख

नई दिल्ली: थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हालात स्थिर, लेकिन संवेदनशील है। पिछले एक वर्ष में भारत और चीन के बीच टकराव वाला कोई और क्षेत्र नहीं बना है। जनरल पांडे ने एक साक्षात्कार में कहा, 'चीन के साथ सैन्य स्तर के साथ-साथ राजनयिक स्तर पर भी वार्ता जारी है। सेना की तैयारियों के बारे में जनरल पांडे ने कहा, हमारी तैनाती मजबूत व संतुलित है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमने पर्याप्त रिजर्व भी रखे हैं। (पेज-3)

ड्राइवर को लेकर दिल्ली में सोरेन को खोजती रही ईडी

झारखंड के सीएम की गिरफ्तारी को लेकर दिनभर चला अटकलों का दौर

राज्य ब्यूरो, रांची

रांची भूमि घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पहुंच गए। हालांकि वह वहां नहीं मिले। ईडी की टीम वहां 13 घंटे से ज्यादा वक्त तक डटी रही। इस दौरान वहां मौजूद ड्राइवर व अन्य स्टाफ को लेकर ईडी के अधिकारी उन्हें ढूंढने दिल्ली में एक-दो संभावित स्थानों पर भी गए। लेकिन हेमंत नहीं मिले। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच सोमवार को ही सीएम की ओर ईडी को ई-मेल भेजकर यह सूचना दी गई कि वह 31 जनवरी को दिन के एक बजे पूछताछ के लिए रांची में उपलब्ध रहेंगे। ईडी उनसे सीएम आवास आकर पूछताछ कर सकती है। रांची जमीन घोटाले मामले में ईडी आठ अगस्त, 2023 से 27 जनवरी, 2024 के बीच हेमंत को 10 समन भेज चुकी है।

ई-मेल में ईडी पर लगाए आरोप : ईडी को भेजे गए ई-मेल में हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह राजनीतिक एजेंडा के तहत की गई कार्रवाई प्रतीत होती है। इसके जरिए ईडी राज्य सरकार के कामकाज को प्रभावित करना चाहती है और निर्वाचित सरकार को उसके दायित्वों से विमुख करना चाहता है। आपका इरादा गलत और राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित है। ईडी का समन पूरी तरह से उसे मिली शक्तियों का दुरुपयोग है। सीएम ने कहा है कि 20 जनवरी को सात घंटे की पूछताछ में उनसे 17-18 प्रश्न पूछे गए थे। सभी का जवाब उन्होंने दे दिया था।

नौ बजे पहुंचे अधिकारी : ईडी अधिकारी दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ हेमंत सोरेन के दक्षिणी दिल्ली स्थित निवास 5/1 शांति निकेतन भवन में सोमवार सुबह करीब नौ बजे पहुंचे। समाचार एजेंसी प्रेट्र के मुताबिक हेमंत सोरेन के आवास से रात करीब 10.30 बजे ईडी के अधिकारी बाहर आते देखे गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सभी अधिकारी बाहर निकले या नहीं। ईडी के सूत्र के अनुसार टीम के सदस्य हेमंत सोरेन के लौटने तक उनके घर पर ही रुकेंगे। अधिकारियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर भी चौकसी बरतने को कहा गया है।

सियासत गर्म : जमीन घोटाले मामले में हेमंत पर शिकंजा कसता देख झारखंड में सियासी माहौल गर्म हो गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे सत्ताधारी दल झामुमो के कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान में घंटों प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान ईडी और केंद्र सरकार के विरुद्ध झामुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। घाटशिला व जमशेदपुर में भी झामुमो कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दिनभर हेमंत की गिरफ्तारी और सत्ता के समीकरणों को लेकर भी अटकलें लगाई जाती रहीं।

व्यस्तता का हवाला दिया तो सख्ती पेज>>6

- हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर 13 घंटे से ज्यादा डटे रहे ईडी के अधिकारी
- 31 को रांची में दिया गया समय, मुख्यमंत्री आवास में होगी पूछताछ

10 समन भेज चुकी है ईडी

7 घंटे पूछताछ की थी ईडी ने 20 जनवरी को

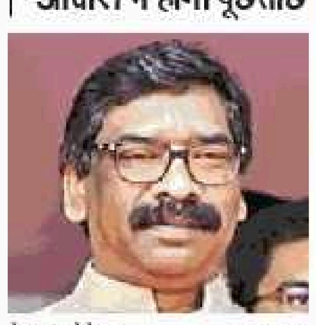

हेमंत सोरेन। फाइल

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नई दिल्ली में स्थित आवास से 'खाली हाथ' लौटते ईडी के अधिकारी। प्रेट्र

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद से 10 घंटे पूछताछ

पटना: जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से लगभग दस घंटे तक पूछताछ की। पटना स्थित ईडी कार्यालय में लालू से सुबह शुरू हुआ सवालों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इस दौरान उनकी पुत्री और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ईडी कार्यालय के बाहर इंतजार करती रहीं। उनके साथ राजद के तमाम वरिष्ठ नेता और समर्थक डटे रहे। (पेज-6)

13 दिन के अंतराल में भूपेंद्र हुड्डा से दूसरी बार पूछताछ

नई दिल्ली : गुरुग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण की अनियमितताओं की शिकायत के मद्देनजर ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 13 दिन के अंतराल में एक बार फिर पूछताछ की। हुड्डा दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में सोमवार सुबह 11.30 बजे पहुंचे और 6.15 बजे वापस लौटे। (पेज-6)

मालदीव में राजनीतिक संकट : राष्ट्रपति मुइज्जू के विरुद्ध महाभियोग की तैयारी

माले, प्रेट्र : मालदीव की मुइज्जू सरकार को अभी सत्ता में आए ढाई महीने ही हुए हैं, लेकिन भारत का मुखर विरोध करने के बाद से वह संकट में आ गई है। मालदीव के मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। संसद में बहुमत वाली एमडीपी भारत से मित्रता की पक्षधर रही है। इसके साथ मालदीव की संसद में सोमवार को चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कैबिनेट के एक मंत्री को मंजूरी मिली और तीन अन्य मंत्रियों को नकार दिया गया। इसके बाद मुइज्जू ने इन तीनों मंत्रियों को फिर से नियुक्त किया।

सन अखबार ने सोमवार को प्रकाशित रिपोर्ट में विपक्षी दल एमडीपी के एक सांसद के हवाले से बताया है कि एमडीपी ने डेमोक्रेट्स की साझेदारी में महाभियोग के प्रस्ताव के लिए पक्षधर सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। मालदीव के आनलाइन समाचार पोर्टल अधाधू के अनुसार, विगत रविवार को संसद में मारपीट कर संसदीय कार्यवाही को बाधित किए जाने के बाद एमडीपी और डेमोक्रेट के सदस्यों ने 45 वर्षीय राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को अपना समर्थन दे दिया है। मालदीव की संसद में कुल 80 सदस्य हैं। यहां हाल ही में महाभियोग का प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

56 वोटों के साथ लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पेज>>11

- एमडीपी ने महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया
- महाभियोग के लिए जरूरी 56 वोट, एमडीपी और डेमोक्रेट का समर्थन

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। आर्काइव

संसद की सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मालदीव की संसद में राजनेताओं के बीच रविवार को हुई 'उठा-पटक' के बाद संसद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संसद में तब हिंसा हुई थी जब सरकार के सांसदों (पीपीएम/पीएनसी पार्टी) ने संसद की कार्यवाही को बाधित कर स्पीकर की घेराबंदी की। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मुइज्जू ने भारत के मित्र समझे जाने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था। मुइज्जू ने 17 नवंबर को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।

राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को

नई दिल्ली: राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होगा। ये सीटें अप्रैल में 56 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के कारण रिक्त हो रही हैं। जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। आठ फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। (पेज-6)

मतांतरण की कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना विवाह अमान्य

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू-मुस्लिम जोड़ों द्वारा सुरक्षा की मांग के लिए दाखिल याचिका पर राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, मतांतरण की कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना किया गया विवाह कानूनी मान्य नहीं है। जोड़ों ने परिवार से जीवन को खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा व वैवाहिक जीवन में किसी के हस्तक्षेप पर रोक की मांग की थी। (पेज-13)

केंद्रीय मंत्री शांतनु का दावा-सात दिनों में देश में लागू हो जाएगा सीएए

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के क्रियान्वयन की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि देश में एक सप्ताह में सीएए लागू कर दिया जाएगा। मतुआ समुदाय के नेता व उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव से भाजपा सांसद ठाकुर ने रविवार शाम दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में सार्वजनिक रैली में उन्होंने कहा कि सीएए लागू करने को लेकर कोई संशय नहीं है। सीएए के कार्यान्वयन पर ठाकुर का दावा इस महीने की उन कई रिपोर्ट के बीच किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस कानून के नियमों को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इससे पहले दिसंबर में बंगाल दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को देश का कानून बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। उधर, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हमारी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंगाल में सीएए किसी हाल में लागू नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक और सामाजिक नफा-नुकसान पेज>>3

- बंगाल से मतुआ समुदाय के नेता ने सार्वजनिक रैली में दी गारंटी

शांतनु ठाकुर। फाइल

तृणमूल का पलटवार-बंगाल में सीएए किसी हाल में लागू नहीं होगा

सियासत

बिहार-झारखंड और उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण के मोर्चे पर क्षति की आशंका, नीतीश के फैसले ने क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ाया, कम सीटों पर समझौते को विवश होगी कांग्रेस

कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है नीतीश की दुश्मनी

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली

भाजपा-जदयू की संयुक्त ताकत की तुलना में लोकसभा चुनाव में बिहार में विपक्ष का नुकसान तो साफ नजर आ ही रहा है, साथ ही बिहार के बाहर भी कांग्रेस को सुकून नहीं मिलने जा रहा है। सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे के झंझट में फंसी कांग्रेस का साथ जदयू ने ऐसे वक्त में छोड़ा है जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी ने बिहार के सीमांचल में प्रवेश किया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को आशंका है कि झटकों का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है।

28 दलों का कुनबा लेकर भाजपा की चुनौती देने के लिए चुनावी अखाड़े की ओर बढ़ रही कांग्रेस का एक अहम सहयोगी साथ छोड़ चुका है, जिससे सड़क से लेकर सदन तक में उसके 'सिपाहियों' की संख्या घट गई है। दूसरी क्षति बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में भाजपा के विरुद्ध सामाजिक समीकरण के मोर्चे पर है। नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं, उसकी संख्या इन तीनों राज्यों में अच्छी-खासी है। बिहार में जातिवार गणना एवं आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करके नीतीश ने खुद को पिछड़ों के हमदर्द नेताओं की पंक्ति में आगे कर लिया था। जाहिर है कि यह ताकत अब भाजपा के साथ है। नीतीश के फैसले ने इन क्षेत्रीय दलों के महत्व को भी बढ़ा दिया है जोकि अभी तक कांग्रेस की अकड़ में जकड़े हुए हैं। अब उनकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे सीट बंटवारे पर बातचीत में कांग्रेस को कम सीटों पर समझौते के लिए विवश होना पड़ सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस को दो सीटों की हैसियत बता दी है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। विपक्षी एकता के लिहाज से अब तक सबसे आसान दिख रहे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ी हो सकती हैं, जहां उसका सिर्फ एक सांसद है, किंतु उसकी चाहत 20 सीटों की है। स्पष्ट है कि कांग्रेस की चुनौतियां जितनी विकट होती जाएंगी, भाजपा की मनोवैज्ञानिक बढ़त उतनी ही बड़ी होती जाएगी। (पेज-4 भी देखें)

50 से बढ़ाकर आरक्षण के दायरे को 75% कर नीतीश ने खुद को पिछड़ों के हमदर्द नेताओं की पंक्ति में आगे कर लिया

- कांग्रेस की चुनौतियां जितनी विकट होती जाएंगी, भाजपा की मनोवैज्ञानिक बढ़त उतनी ही बड़ी होती जाएगी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सीएम नीतीश कुमार।

मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग (जिसे मस्जिद पक्ष फव्वारा कहता है) के वैज्ञानिक परीक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की है। साथ ही शिवलिंग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से वैज्ञानिक जांच कराने और शिवलिंग सहित पूरे सील क्षेत्र का सर्वे कराने की मांग भी की है।

मंदिर पक्ष की ओर से सोमवार को ये दोनों अर्जियां ज्ञानवापी परिसर में माता शृंगार गौरी व अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अधिकार का मूल मुकदमा दाखिल करने वाली महिलाओं की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने दाखिल की हैं। पहली अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से 19 मई, 2023 के रोक आदेश को समाप्त करने की मांग की गई है जिसमें कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग का एएसआइ से वैज्ञानिक परीक्षण कराने के हाई कोर्ट के आदेश को टाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग वाला क्षेत्र जहां मुसलमान वजू करते थे, सील है। अर्जी में कहा गया है कि सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग हिंदुओं की आस्था है और उन्हें अपने भगवान की पूजा-अर्चना का अधिकार है। ऐसे में कोर्ट सील क्षेत्र और वहां मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का एएसआइ को आदेश दे क्योंकि शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के बगैर पूरे परिसर के सर्वे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एएसआइ जांच करके शिवलिंग की प्रकृति का पता लगाए, जिसे मस्जिद पक्ष फव्वारा कहता है।

अर्जी में यह भी कहा गया है कि शिवलिंग के चारों ओर एक बनावटी दीवार बनाई गई है। यह नया निर्माण है, इसका मूल इमारत से कोई लेना-देना नहीं है। इस दीवार का निर्माण जान-बूझकर शिवलिंग पीठिका से जुड़े मूल तथ्यों को छिपाने के लिए किया गया है।

शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना एएसआइ से वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए पेज>>5

- कोर्ट में दो अर्जियां दाखिल कर मंदिर पक्ष ने कहा, एएसआइ से कराएं जांच

एक अर्जी में की शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग

134 पेड़ों के प्रत्यारोपण/स्थानांतरण की मंजूरी एलजी वीके सक्सेना ने पुराने जेएनयू परिसर में नए भवन के निर्माण के लिए दी है। 1.7578 हेक्टेयर क्षेत्र में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आइएसटीएम) के भवन निर्माण होना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 30 जनवरी, 2024

आज का मौसम

सुबह हल्का कोहरा रहेगा।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
30 जनवरी	22.0	08.0
31 जनवरी	20.0	10.0
नोएडा		
30 जनवरी	21.0	11.0
31 जनवरी	21.0	10.0
गुरुग्राम		
30 जनवरी	23.0	07.0
31 जनवरी	22.0	09.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

चार आइएएस अधिकारियों का दिल्ली से बाहर तबादला

नई दिल्ली: दिल्ली में तैनात चार आइएएस अधिकारियों का तबादला दिल्ली से बाहर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के तहत आइएएस डा. दिलराज कौर का तबादला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किया गया है। आइएएस डा. लालतिनखुमा फ्रैंकलिन और विक्रम सिंह मलिक को लद्दाख भेजा गया है। आइएएस डा. सोनल स्वरूप को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। जबकि आइएएस मिताली नामचूम का अरुणाचल प्रदेश, वेदिता रेड्डी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अमोल श्रीवास्तव का मिजोरम से दिल्ली तबादला किया गया है। (राब्यू)

नशे में दीवार फांदकर रनवे तक पहुंचा युवक

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के अगले दिन आइजीआइ एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। नशे की हालत में एक युवक एयरपोर्ट की दीवार फांदकर रनवे तक पहुंच गया। एक पायलट ने उसे देखा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सीआइएसएफ के कर्मचारियों ने उसे पकड़कर आइजीआइ थाना पुलिस को सौंप दिया। हरियाणा के बताए जा रहे इब्राहिम को आइजीआइ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। (जासं)

अस्पतालों पर खर्च में गिरावट पर स्पष्टीकरण तलब

नई दिल्ली: सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों पर खर्च में आई गिरावट पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जीटीबी अस्पताल में सीटी स्कैन पिछले छह महीने से काम नहीं कर रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल एक हलफनामे के अनुसार उसके अस्पतालों पर व्यय 2022-23 में 3500 करोड़ से घटकर 2023-24 में लगभग 2,800 करोड़ रुपये हो गया है। (जासं)

कल तेज हवा चलने के साथ हल्की वर्षा का यलो अलर्ट

- सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे एयरपोर्ट पर दृश्यता रही 200 मीटर
- आज भी सुबह रहेगा हल्का कोहरा, दिन में आसमान रहेगा साफ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

लगातार हो रहे बदलावों के बीच बुधवार को दिल्ली का मौसम फिर करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ ही हल्की वर्षा होने का यलो अलर्ट है। गुरुवार को भी हल्की वर्षा जारी रहने का पूर्वानुमान है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी।

सोमवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्का कोहरा देखने को मिला। नौ बजे के बाद धूप निकलने से आसमान साफ हो गया। अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 22.6 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 6.8 डिग्री रिकार्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 61 प्रतिशत रहा। मुंगेशपुर और जाफरपुर सबसे ठंडे इलाके रहे। इन दोनों ही जगह अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

कोहरे के चलते सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे आइजीआइ एयरपोर्ट पर दृश्यता 200 मीटर रिकार्ड की गई। 70 से अधिक ट्रेनें विलंब से दिल्ली पहुंचीं। 20 ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा। 14 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों के प्रस्थान और सात फ्लाइटों के आगमन में विलंब हुआ। जबकि 62 घरेलू उड़ानें जाने एवं 47 उड़ानें आगमन में लेट हुईं।

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर अब दिल्ली के मौसम पर देखने को मिलेगा। मंगलवार की सुबह हल्का कोहरा रहेगा। जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। शाम के समय बादलों की आवजाही शुरू हो जाएगी। बुधवार को राजधानी के ज्यादातर इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बरसात हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है।

ठंड के साथ सोमवार को दिल्ली में छाए हल्के कोहरे का दृश्य। एएनआइ

हवा 'बहुत खराब', लेकिन ग्रेप-तीन लगाने से इन्कार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ दिल्ली के चार इलाकों का एक्यूआइ 400 से ऊपर 'गंभीर' श्रेणी में रहा

यहां की स्थिति सबसे खराब

सोनिया विहार	409
रोहिणी	408
वजीरपुर	401
जहांगीरपुरी	398
मुंडका	395

सोमवार को भी दिल्ली का एक्यूआइ 300 से ऊपर यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। चार इलाकों का एक्यूआइ तो 400 से भी ऊपर यानी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। इसके बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने फिलहाल ग्रेप-तीन की पाबंदियां लगाने से इन्कार कर दिया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को राजधानी का एक्यूआइ 356 रहा। रविवार को यह 365 था। दिल्ली के चार इलाके ऐसे रहे, जहां का एक्यूआइ शाम चार बजे 400 के पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में रहा। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले दो से तीन दिन वायु प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में ही बना रहेगा।

उधर, सीएक्यूएम की उप-समिति ने सोमवार शाम एक आपात बैठक भी की। इस दौरान वायु गुणवत्ता की स्थिति, मौसम पूर्वानुमान और अनुमानित वायु गुणवत्ता सूचकांक का जायजा लिया। मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) और आइआइटीएम पुणे के पूर्वानुमानों के अनुसार उप-समिति ने सर्वसम्मति से ग्रेप-तीन के प्रविधानों को लागू करने से पहले एक या अधिक दिन तक स्थिति पर नजर रखने का निर्णय लिया। मालूम हो कि ग्रेप-तीन के प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य और एनसीआर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल है।

वयस्कों को टीबी का टीका लगाने के लिए घर-घर सर्वे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और केंद्रीय टीबी डिविजन की पहल पर टीबी की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय ने वयस्क लोगों को बीसीजी का टीका देने की तैयारी कर ली है। इस अभियान के तहत दिल्ली के पांच जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बीसीजी के टीके की एक डोज दी जाएगी। इनमें पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर पूर्व और नई दिल्ली जिले शामिल हैं। इन जिलों में आशा वर्कर घर-घर जाकर टीका लेने वाले लोगों की सूची तैयार कर रही हैं।

परिवार कल्याण निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीका लगने के योग्य लोगों की सूची जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। इस डाटा के आधार पर यह टीकाकरण होगा। फरवरी के दूसरे सप्ताह में वयस्कों को टीका लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान समय में पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों को बीसीजी टीके की एक डोज दी जाती है।

सीएम का दावा, सौर पैनल लगवाने वाले सभी घरों का बिजली बिल आएगा जीरो

सौर नीति 2024 ▶ अमल होने पर व्यावसायिक उपभोक्ताओं का भी बिल हो जाएगा आधा

नई नीति के तहत चार साल में सौर पैनल लगाने के खर्च की हो जाएगी भरपाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली सौर नीति 2024 की घोषणा करते हुए इसे जनता से लिए बड़ी राहत बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि नई नीति लागू होने पर सौर पैनल लगवाने पर दिल्ली में आवासीय क्षेत्र में रहने वाले सभी घरों का बिजली बिल जीरो आएगा। साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा। इतना ही नहीं उन्हें 700 से 900 रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। इससे चार साल के अंदर सौर पैनल लगाने में आए खर्च की भी भरपाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सौर नीति 2024 (सोलर पालिसी 2024) की घोषणा की। इस दौरान बिजली मंत्री आतिशी के अलावा आप नेता जस्मिन शाह भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सौर नीति 2024 के बारे में प्रेस को जानकारी दी। उनके साथ कैबिनेट मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। एएनआइ

सीएम ने कहा कि इससे पहले 2016 में सौर नीति जारी की गई थी, जिसने दिल्ली में सौर ऊर्जा की बुनियाद रखी थी। सौर नीति 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावाट क्षमता के सौर पैनल लगवाए हैं। नीति के तहत डिस्काम ने 1250 मेगावाट सौर ऊर्जा बाहर से खरीदी है। इस तरह इस नीति से दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध हुई है।

ऐसे होगा बिजली बिल जीरो : दिल्ली में सरकार हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देती है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल जीरो आता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल आधा (50 प्रतिशत) आता है। 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का पूरा बिल आता है।

नई नीति के तहत सौर पैनल लगवाने वाले प्रति माह 200 यूनिट से भी अधिक बिजली उत्पन्न कर पाएंगे ऐसे में 200 यूनिट तक सरकार से बिजली का बिल माफ होता है और 200 यूनिट से अधिक यूनिट तक बिजली सौर पैनल से तैयार होगी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप प्रति माह जितनी भी बिजली सौर पैनल से तैयार करेंगे उतनी यूनिट बिजली आप के बिल से कम कर दी जाएगी और जो बिजली बचेगी उसे डिस्काम को बेचकर भुगतान ले सकेंगे। आवासीय सेक्टर में 3 किलोवाट पर 3 रुपये और 10 किलोवाट पर 2 रुपये प्रति यूनिट जेनरेशन बेस्ड इन्सेंटिव मिलेगा। इसके अलावा सरकार प्रतिमाह 700-900 रुपये तक प्रति माह इन्सेंटिव भी देगी।

राज्य सरकार का दावा है कि चाहे आप 800, 1000 या 2000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करें, बिल जीरो आएगा। यह इस नीति की सबसे बड़ी खासियत है। हालांकि इसके लिए बड़े सोलर पैनल की जरूरत होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद अगले तीन साल के अंदर यानी 2027 तक दिल्ली में 4500 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित हो जाएगी। इसमें से 750 मेगावाट क्षमता के सौर पैनल छतों के ऊपर लगाए जाएंगे, जबकि 3750 मेगावाट डिस्काम बाहर से सौर ऊर्जा खरीदेगा। उन्होंने कहा कि सौर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की राख का पुन: उपयोग करे एमसीडी : डीपीसीसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ निगम के चारों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रोजाना निकल रही 1200 टन राख

▶ डीपीसीसी ने राख का इस्तेमाल ईंट व अन्य उत्पाद बनाने में करने को कहा

कूड़े के बाद कहीं राजधानी में राख भी परेशानी का सबब न बन जाए, इसी आशंका के मद्देनजर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने नगर निगम के चारों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रोजाना निकल रही 1200 टन राख का इस्तेमाल ईंट और अन्य उत्पाद बनाने में करने के लिए कहा है।

डीपीसीसी ने शर्तों के साथ तेहखंड में बनी नई इंजीनियरिंग सेनेटरी लैंडफिल (ईएसएल) साइट को छह महीने के लिए कंसेंट टू आपरेट (सीटीओ) दे दिया है। साथ ही डीपीसीसी ने एमसीडी को साफ तौर पर कहा है कि राजधानी के चारों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में रोजाना पैदा हो रही सारी राख का पुनः उपयोग करे। यदि यह राख इसी तरह तेहखंड की ईएसएल साइट पर डाली जाती रही तो छह साल में इसकी क्षमता भी पूरी हो जाएगी। छह महीने की सशर्त सीटीओ जारी करते हुए डीपीसीसी ने साफ कहा है कि चार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला, बवाना, गाजीपुर और तेहखंड में चल रहे हैं। राख को निचले इलाकों में डाल देना समस्या का हल नहीं है। 29.2 एकड़ में बनी तेहखंड ईएसएल की क्षमता 9.23 लाख क्यूबिक मीटर है। इस साइट पर रोज करीब 100 टन राख डाली जा रही है। इस लैंडफिल साइट के भरने के बाद एमसीडी एक बार फिर इसके लिए जमीन की मांग करेगी, जबकि दिल्ली के पास जगह की कमी है। इसलिए यह जरूरी है कि राख का इस्तेमाल ईंट और अन्य सामान बनाकर सड़कें और बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाए।

साइट पर नहीं डलेगा कूड़ा

इस साइट को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। साइट पर छह अलग-अलग लेयर हैं। यह साइट सिर्फ राख के लिए बनाई गई है। यहां पर कूड़ा नहीं डलेगा। एमसीडी ने इस साइट को बनाने में करीब 42.3 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सेंटर फार एन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आफ डिग्रेड इकोसिस्टम (सीईएमडीई) के हेड और डीपीसीसी कमिटी के सदस्य सीआर बाबू ने बताया कि सीटीओ छह महीने के लिए दी गई है। उक्त शर्तें पूरी न होने पर आगे इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे अहम शर्त राख का पुनः उपयोग करने की ही है। इसके बिना यह साइट लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। मालूम हो कि इस साइट पर पीजोमीटर लगाया जाएगा। यह देखेगा कि साइट की वजह से भूजल प्रदूषित तो नहीं हो रहा। लिचेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे।

दिल्ली पुलिस के केंद्रीयकृत मालखाने में लगी आग, 262 वाहन जले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

खजूरी स्थित दिल्ली पुलिस के वजीराबाद ट्रेनिंग स्कूल में बने केंद्रीयकृत मालखाने में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। देखते ही देखते मालखाने में खड़े 262 वाहन जल गए। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका है कि किसी शरारती तत्व ने वारदात को अंजाम दिया है। सोनिया विहार थाना पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच कर रही है। एफएसएल ने घटना स्थल से साक्ष्य जमा किए हैं। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त डा. जाय टिर्की ने बताया कि रविवार रात 12:35 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलिस के मालखाने में आग लगी है। जिस स्थान पर लगी, वहां पर पुलिस के बाहरी जिले का व्हीकल पिट बना हुआ था। वहां पुलिस स्टाफ तैनात रहता है। दमकल ने दो घंटे में आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि केंद्रीयकृत मालखाने में सभी जिलों के लिए स्थान बना है।

वजीराबाद पुलिस मालखाने में आग लगने से जलकर खाक हुए वाहन। सौजन्य :दमकलविभाग

थानों के मालखाने का सामान अधिक होने पर उन्हें केंद्रीयकृत मालखाने में भेज दिया जाता है। ये केस प्रापर्टी होती हैं। अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि 200 कार और 250 दोपहिया वाहन जले हैं। जिला पुलिस उपायुक्त ने कहा कि आग बुझने के बाद जांच में 262 वाहन जलने की पुष्टि हुई।

दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार जीता है। जहां दिल्ली पुलिस ने 'जज च्वाइस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला दल की ट्राफी जीती है, वहीं सीआरपीएफ ने 'पापुलर च्वाइस श्रेणी' में सर्वश्रेष्ठ महिला दल की ट्राफी जीती।

दिल्ली पुलिस की पीआरओ डीसीपी सुमन नलवा ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, बेहद गर्व का क्षण... गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और अन्य सहायक बलों के बीच मार्चिंग दल में जजों की पसंद श्रेणी में दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। 30 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे दिल्ली छावनी के आरआर कैंप में एक ट्राफी प्रतिनिधित्व समारोह आयोजित किया जाएगा। पहली बार दिल्ली पुलिस की सभी महिला टुकड़ियों ने सभी महिला पाइप बैंड के साथ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।

स्थायी समिति गठित होने तक सदन नहीं चलने देगी भाजपा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- नगर निगम : सोमवार को पार्टी ने फिर किया हंगामा, बिना नामकरण समिति के गलियों और सड़कों के नामकरण पर उठाए सवाल
- हंगामे और विरोध के बीच 25 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 16 किए गए पारित

सोमवार को नगर निगम सदन की बैठक के दौरान स्थायी समिति गठित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते भाजपा के पार्षद। चंद्र प्रकाश मिश्र

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का गठन न होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समिति के गठन होने तक स्थायी समिति की शक्तियां सदन को देने के लिए महापौर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका विरुद्ध भी भाजपा ने सदन में विरोध किया। साथ ही भाजपा ने एलान किया कि जब तक महापौर स्थायी समिति का गठन नहीं करेंगी, तब तक निगम की साधारण सदन की बैठक नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने नामकरण समिति का गठन किए बिना गलियों और सड़कों आदि के नाम बदलने के लिए आए प्रस्तावों का विरोध किया। इसे नियमों के विरुद्ध करार दिया। हालांकि हंगामे के बीच सत्तापक्ष ने 25 प्रस्तावों में से सात को स्थगित और एक रद कर दिया। एक प्रस्ताव आयुक्त को वापस भेजा और 16 को पारित किया।

नगर निगम की बैठक शुरू होने पर शोक प्रस्ताव और निगमायुक्त की ओर से घटनात्मक रिपोर्ट पेश करने के बाद ही भाजपा पार्षद महापौर के आसन के सामने पहुंच गए। हाथ में 'स्थायी समिति का गठन करो' की तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महापौर शैली ओबेराय- नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह और भाजपा पार्षदों से शांति बनाए रखने की अपील करती रहीं। लेकिन भाजपा पार्षद हंगामा करते रहे और स्थायी समिति के गठन की मांग करते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने नामकरण समिति के गठन के बिना सड़कों और गलियों के नाम बदलने के लिए लाए गए प्रस्तावों को नियम विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि बिना समिति गठन के ये कार्य हो ही नहीं सकते हैं। इसमें इलाके के इंजीनियर की रिपोर्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति के गठन पर किसी भी प्रकार की रोक किसी भी अदालत ने नहीं लगाई है। बावजूद इसके महापौर स्थायी समिति का गठन नहीं होने दे रही हैं। निगमायुक्त को स्थायी समिति के गठन के लिए वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए तारीख तय करनी होती है और महापौर को इसके लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने होते हैं, लेकिन जानबूझकर समिति का गठन नहीं किया जा रहा है।

डा. शैली ओबेराय ने कहा, भाजपा ने नहीं चलने दिया सदन : महापौर डा. शैली ओबेराय ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी भाजपा पार्षदों ने सदन नहीं चलने दिया। भाजपा पार्षदों से हमारी सदैव अपील रहती है कि सदन की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाए, ताकि दिल्ली के विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। सभी पार्षद प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करें, सकारात्मक चर्चा करें। भाजपा पार्षद कभी भी सदन की गरिमा का सम्मान नहीं करते हैं। हमें आज भी शोर-शराबे के बीच प्रस्तावों को पास करना पड़ा। भाजपा पार्षद नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के विकास के लिए नई नीतियां बनें और नए कार्य हों।

आज से शुरू होगी बजट पर चर्चा

निगम की बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह निगमायुक्त द्वारा पेश किए गए बजट पर अपना वक्तव्य रखेंगे। इसके बाद अगले सोमवार को पांच से सात फरवरी तक सामान्य चर्चा होगी। नौ फरवरी को नेता सदन मुकेश गोयल इसको अंतिम रूप देंगे। निगम एक्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर से पहले निगमायुक्त को बजट पेश करना होता है।

सुंदरीकरण

राजधानी की मुख्य सड़कें और प्रमुख चौराहों को आकर्षक बनाने का किया जा रहा है काम, जनपथ-मौलाना आजाद चौराहे और लेडी इरविन कालेज के सामने लगाई बुद्ध की मूर्ति

राजस्थान के कलाकार फव्वारों और मूर्तियों से संवार रहे दिल्ली

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

जी-20 की तर्ज पर जल्द ही राजधानी की कई मुख्य सड़कें और प्रमुख चौराहे भी बदले हुए नजर आएंगे। इन्हें राजस्थान के कलाकारों की ओर से बनाए गए नए फव्वारों और मूर्तियों से संवारा जा रहा है। विभिन्न डिजाइनों और नाना प्रकार के पत्थरों से बने फव्वारे, मूर्तियां, पैनल और प्लांटर्स दिल्ली आना शुरू हो गए हैं। इन्हें एलजी वीके सक्सेना की निगरानी में लगाया जा रहा है।

राजनिवास अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से पहले सुंदरीकरण अभियान मुख्य रूप से मध्य दिल्ली और हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित था, जबकि अब ये नई मूर्तियां शहर के अन्य हिस्सों में भी स्थापित की जाएंगी। एलजी ने स्थानीय निकायों को पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में प्रमुख स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया है, जहां फव्वारे और मूर्तियां लगाई जा सकें।

> जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद भी दिल्ली को सुंदर बनाने का काम जारी है। हाल ही में पद्मासन भगवान बुद्ध की मूर्ति उपराष्ट्रपति आवास के पास जनपथ-मौलाना आजाद चौराहे पर स्थापित की गई है। मंडी हाउस में लेडी इरविन कालेज के सामने बुद्ध की एक चारमुखी मूर्ति लगाई गई है। जल्द ही, आइएसबीटी के सामने रिंग रोड और यमुना पर समाधि परिसर के पीछे बाइपास का सुधार और सुंदरीकरण कार्य शुरू हो जाएगा।
>
> – वीके सक्सेना, एलजी, दिल्ली

इसके बाद एलजी की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम चिह्नित स्थानों को अंतिम रूप देगी।

शिखर सम्मेलन से पहले 100 से अधिक फव्वारे और मूर्तियां स्थापित की गई थीं। अबकी बार दिल्ली को 50- 60 कलाकृतियां मिलेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राहगीरों एवं वाहन चालकों को असुविधा न हो, सड़कों के किनारे एवं चौराहों के पास खाली स्थानों को चुना जा रहा है।

शिव शीष, बुद्ध पैनल, हाथी की मूर्ति, खड़े बुद्ध, लोगों का स्वागत करते हुए तारा देवी, प्लांटर्स के अलावा, अमूर्त कला एवं दीवार पैनल एलजी की ओर से चुने गए कुछ डिजाइन हैं। ये मूर्तियां हरे, पीले सागौन की लकड़ी, लाल, चूने और नदी के पत्थरों से बनाई गई हैं। कलाकृतियों की ऊंचाई तीन से 10 फीट तक है। अधिकारियों ने बताया कि नए फव्वारे और मूर्तियां भी व्यावसायिक घरानों की ओर से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत प्रायोजित की जा रही हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले स्थापित की गईं कलाकृतियां भी एलजी ने सीएसआर योजना के तहत व्यावसायिक घरानों से ही मंगवाई थीं।

एक अधिकारी के मुताबिक इन मूर्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की होगी। समीक्षा बैठकों में एलजी इसकी जानकारी लेते हैं कि मौजूदा मूर्तियों और फव्वारों का रखरखाव कैसे किया जा रहा है।

जनपथ - मौलाना आजाद रोड गोलचक्कर पर उपराष्ट्रपति आवास के पास लगी पद्मासन में बैठे भगवान बुद्ध की प्रतिमा। सौजन्य: राजनिवास

शिक्षिका ने यूकेजी के छात्र को स्केल फेंककर मारा, आंख में लगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ भगवती गार्डन के गुडलक पब्लिक स्कूल में पढ़ता है अक्षांश, एम्स में हुआ आंख का आपरेशन

मोहन गार्डन थाना इलाके के एक स्कूल में शिक्षिका ने लोहे का स्केल (फुट्टा) फेंककर मारा, जो यूकेजी के छह वर्षीय छात्र की आंख में जा लगा। स्केल लगने के बाद बच्चा घर पहुंचा तो उसकी आंख से पानी निकल रहा था। मां उसे 19 जनवरी को निजी अस्पताल ले गई तो डाक्टर ने बच्चे की आंख में कट (जख्म) होने की बात कहते हुए आंख का आपरेशन करने की सलाह दी। बच्चे के स्वजन के पास आपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे। ऐसे में बच्चे को एम्स रेफर कर दिया गया। एम्स में बच्चे की आंख का आपरेशन किया गया। बच्चा अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ है। उसे देखने में दिक्कत हो रही है। बच्चे की पहचान विपिन गार्डन के अक्षांश कुमार वर्मा के रूप में हुई है। मोहन गार्डन थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस को दी शिकायत में अनुराधा कुमारी वर्मा ने बताया कि उनके बेटे की बाईं आंख से पानी आ रहा था। अक्षांश ने बताया कि 17 जनवरी को कक्षा में शिक्षिका मीनाक्षी रावत ने लोहे का स्केल फेंककर उसे मारा था, जिससे आंख में चोट लग गई। अक्षांश की कक्षा के बच्चों ने भी उन्हें बताया कि मीनाक्षी मैम ने स्केल फेंककर उसे मारा था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अध्यापक का कहना है कि वह बच्चों को चुप करवा रही थी। उसी दौरान स्केल हाथ से छूट गया जो बच्चे को लग गया।

****

31 जनवरी से आरंभ होकर नौ फरवरी को समाप्त होने वाले संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने मंगलवार को विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संबोधन से होगी।

मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं : मोदी

पीएम बोले ▶ इस प्रतीक्षा में नहीं रहता कि स्थितियां सुधर जाएंगी

अगर लाखों चुनौतियां हैं तो उसके करोड़ों समाधान भी हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चुनौतियों के सामने मैं हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठ जाता हूं। न ही इसकी प्रतीक्षा में रहता हूं कि स्थितियां सुधर जाएंगी। बल्कि मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। इसके चलते मुझे नया सीखने को मिलता है। वह सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

छात्रों ने जब उनसे पूछा कि पीएम जैसी जिम्मेदारी को आप तनाव मुक्त होकर कैसे निभाते हैं, कभी तनाव भी होता है? इस पर पीएम ने सवाल करने वाले छात्र से चुटीले अंदाज में पूछा कि क्या आप भी पीएम पद की दौड़ में हो। साथ ही कहा कि चुनौतियां तो आती हैं। लेकिन अगर लाखों चुनौतियां हैं तो उसके करोड़ों समाधान भी हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी हो 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा देश सामर्थ्यवान है। मैं हर चुनौती को पार कर जाऊंगा। इसलिए मैं देश के सामर्थ्य को लगातार बढ़ाने में जुटा हूं।

पीएम ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं सदैव उनके सपनों को ही पूरा करने और उन्हें सामर्थ्यवान बनाने में लगा हूं। जैसे-उन्हें पक्का घर दे दूं। उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाए। आयुष्मान कार्ड मिल जाए। हर घर नल से जल पहुंच जाए। छात्रों को अपने जीवन से जुड़े पहलुओं को साझा करते हुए पीएम ने कहा कि जब कोई स्वार्थ नहीं होता है तो निर्णयों में कभी दुविधा नहीं रहती है। मैं तो आपके लिए काम करता हूं, ताकि आपके माता-पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि आपको भी उससे गुजरना पड़े। मुझे ऐसा देश बनाकर देना है, जिसमें आपकी भावी पीढ़ी को भी लगे कि हम इस देश में और खिल सकते हैं। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच रखें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान देशभर के बच्चों को टिप्स दिए। प्रेट्र

मेरे यहां निराशा के लिए सभी दरवाजे-खिड़कियां बंद

पीएम ने कहा कि तनाव मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें। सही-गलत को पहचानने का विवेक रखें। किसी कारण गलती हो भी जाए तो निराश न हों बल्कि उससे सीखें। उन्होंने बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से घिरी हुई थी, मेरा देश भी घिरा था। मैं कह सकता था कि पूरी दुनिया के सामने संकट है। मैं क्या करूं। सभी अपना-अपना देखो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। रोज टीवी पर आया। रोज देशवासियों से बात की। कभी ताली तो कभी थाली बजाने के लिए कहा तो कभी दिया जलाने के लिए कहा। वह कोरोना को तो खत्म नहीं करता था, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ने की सामूहिक शक्ति को जन्म देता था।

प्रधानमंत्री ने बताया अपने गवर्नेंस का सिद्धांत

पीएम ने कहा कि मेरा गवर्नेंस का सिद्धांत है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए नीचे से ऊपर तक सही जानकारी आनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक परफेक्ट गाइडेंस जाना चाहिए। यदि यह ठीक रहा तो आप चीजों को संभाल सकते हैं।

'यह कोई प्लेटफार्म नहीं, कि जो ट्रेन आई चढ़ गए'

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सूचीबद्ध नहीं की गई एक याचिका का 12 बजे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर एक युवा वकील को सोमवार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह कोई रेलवे प्लेटफार्म नहीं है कि जो भी ट्रेन आ गई बस चढ़ जाएं। वकील चाहते थे कि न्यायिक सुधारों के लिए अनुरोध करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई हो।

सीजेआइ के साथ जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे दिन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठों के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान एक वकील जब अपने अनुरोध पर अड़े रहे तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा-'यह कोई प्लेटफार्म नहीं है कि जो भी ट्रेन आ गई बस चढ़ जाएं। आप इस तरह से कैसे उल्लेख कर सकते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं?' जब वकील ने कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते हैं तो सीजेआइ ने कहा- 'क्या दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि वकील किसी भी वक्त खड़े हो जाते हैं और मामले का उल्लेख करते हैं?' उन्होंने वकील को शीर्ष अदालत की कार्यप्रणाली समझने के लिए किसी अधिवक्ता से संपर्क करने की सलाह दी।

वादियों की जाति और धर्म का उल्लेख करने का चलन बंद करें : सुप्रीम कोर्ट

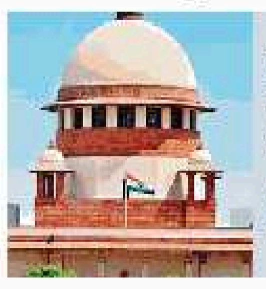

कहा, वादी की जाति, धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नजर नहीं आता

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट मामलों में धर्म एवं जाति का उल्लेख करने का चलन बंद होना चाहिए। साथ ही अपनी रजिस्ट्री व अन्य सभी अदालतों को इसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने सभी हाई कोर्टों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके यहां या उनके अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ अदालतों के समक्ष दायर किसी भी याचिका में पक्षकारों के मेमो (पक्षकारों के ब्योरे) में किसी वादी की जाति या धर्म का उल्लेख न हो। पीठ ने कहा, 'हमें इस अदालत या निचली अदालतों के समक्ष किसी वादी की जाति या धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नजर नहीं आता। इस चलन को छोड़ना होगा और तुरंत बंद करना होगा। इसलिए यह सामान्य आदेश जारी करना उचित प्रतीत होता है कि अब से इस अदालत के समक्ष दायर किसी याचिका या कार्यवाही के पक्षकारों के मेमो में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा, भले ही निचली अदालतों के समक्ष ऐसे विवरण उपलब्ध कराए गए हों।'

शीर्ष अदालत ने यह आदेश राजस्थान में एक परिवार अदालत के समक्ष लंबित वैवाहिक विवाद में स्थानांतरण याचिका को अनुमति प्रदान करते हुए दिया। शीर्ष अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया कि पक्षकारों के मेमो में पति और पत्नी दोनों की जातियों का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने सूचित किया कि निचली अदालत में दाखिल पक्षकारों के मेमो में अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन किया जाता है तो रजिस्ट्री इस पर आपत्ति करती है। वर्तमान मामले में नीचे की अदालत के समक्ष दोनों पक्षकारों की जातियों का उल्लेख किया गया था, लिहाजा उनके पास स्थानांतरण याचिका में भी उनकी जातियों का उल्लेख करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसके आदेश को तत्काल अनुपालन के लिए बार के सदस्यों के साथ-साथ रजिस्ट्री के संज्ञान में लाया जाएगा। पीठ ने कहा, 'इस आदेश की एक प्रति अवलोकन के लिए संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष रखी जाएगी और कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरलों को भेजी जाएगी।'

राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होगा। ये सीटें अप्रैल में 56 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के कारण रिक्त हो रही हैं। जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने द्विवार्षिक चुनाव की तारीख की घोषणा करते हुए कहा कि आठ फरवरी को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

ये सीटें 15 राज्यों में हैं। इनमें सबसे अधिक 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि छह-छह सीटें बिहार और महाराष्ट्र में हैं। बिहार में एक दिन पहले ही सत्ताधारी गठबंधन का स्वरूप बदला है। नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ साझा सरकार बनाई है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल दो अप्रैल को और बाकी छह का उसके अगले दिन खत्म हो रहा है। अप्रैल में राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया भी शामिल हैं। वैसे इस साल कुल 68 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा। चार नामित सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में पूरा होगा। ये हैं सोनल मान सिंह, महेश जेठमलानी, रामशकल और राकेश सिन्हा। अप्रैल में जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें ओडिशा से बीजद के प्रशांत नंदा और अमर पटनायक, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी (उत्तराखंड), केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कांग्रेस के नारनभाई राठवा और अमी याग्निक भी हैं। कुल नौ केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में अपना मौजूदा कार्यकाल अप्रैल में पूरा करेंगे। विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे की सीटों पर भी मतदान होना है।

फिर से निर्वाचित होने के लिए नड्डा को अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से बाहर की कोई सीट देखनी होगी, क्योंकि वहां कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है और भाजपा अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक (चार सीटें) और तेलंगाना (तीन) के जरिये अपने कम से कम पांच उम्मीदवारों को ऊपरी सदन में पहुंचा सकती है।

▶ **नड्डा, मनमोहन, प्रधान और अश्विनी वैष्णव का खत्म हो रहा कार्यकाल**

▶ **सबसे अधिक 10 सीटें यूपी में, बिहार व महाराष्ट्र में छह-छह सीटें**

राज्यवार चुनावी सीटें

राज्य	सीटें	मध्य प्रदेश	5
आंध्र प्रदेश	3	महाराष्ट्र	6
बिहार	6	तेलंगाना	3
छत्तीसगढ़	1	उत्तर प्रदेश	10
गुजरात	4	उत्तराखंड	1
हरियाणा	1	बंगाल	5
हिमाचल प्रदेश	1	ओडिशा	3
कर्नाटक	4	राजस्थान	3

महाराष्ट्र में छह सीटों पर राज्यसभा चुनाव खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि राज्य में शिवसेना और राकांपा में विभाजन के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के अबीर रंजन बिस्वास, सुभाष चक्रवर्ती, मोहम्मद नदीमुल हक और शांतनु सेन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कार्यकाल अप्रैल में पूरा होगा।

बिहार से राजद के मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम, जदयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह तथा भाजपा के सुशील कुमार मोदी के साथ ही कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश से जिन सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में पूरा होगा, उनमें भाजपा के अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कर्दम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिंह राव, विजय पाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी, हरनाथ सिंह यादव और सपा से जया बच्चन हैं। यहां भाजपा को अपने सदस्यों की जीत दिलाने में असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सपा भी कुछ अधिक की आशा कर सकती है। छत्तीसगढ़ से भाजपा की सरोज पांडेय तथा हरियाणा से डीपी वत्स का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त होगा।

लड़कियों की विवाह उम्र बढ़ाने पर गठित संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाले विधेयक पर विचार कर रही एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। आगामी 31 जनवरी से शुरू होने वाला संसद का बजट सत्र लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले वर्तमान लोकसभा का आखिरी सत्र है। समिति अब चार महीने के कार्यकाल विस्तार के बाद मई तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी जबकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है।

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 दो साल पहले लोकसभा में पेश किया गया था और ऐसे में वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह विधेयक निष्प्रभावी हो सकता है। गत 24 जनवरी के बुलेटिन में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति ने बाल विवाह निषेध से संबंधित विधेयक पर विचार के लिए शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को 24 जनवरी, 2024 से चार महीने की अवधि के लिए समय विस्तार दिया है।

सीएए लागू करने में सीमित हो सकती है राज्यों की भूमिका

नीलू रंजन, नई दिल्ली

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता भले ही अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं होने देने का दावा कर रहे हों, लेकिन नागरिकता का मुद्दा पूरी तरह से केंद्रीय विषय होने के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने में राज्यों और खासकर जिलाधिकारियों की भूमिका सीमित हो सकती है। सीएए के तहत नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी और आवेदक के दावे के वेरीफिकेशन के लिए जिलाधिकारी के अलावा किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को अधिकार देने का विकल्प भी खुला हुआ है।

गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस महीने के शुरू में ही सीएए के नियम बन जाने पर आनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन की सुविधा दिए जाने का दावा किया था। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीएए को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक हफ्ते के भीतर इसके लागू होने का दावा किया है। वैसे तो केंद्र सरकार को सीएए के लिए बने नियमों को सीधे अधिसूचित करने का अधिकार है और अधिसूचित होते ही ये नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन संसदीय नियम के मुताबिक इन नियमों को अगले संसद सत्र में सदन के पटल पर रखना होगा। एक हफ्ते में लागू होने की स्थिति में इन नियमों को 31 जनवरी से सात फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र में रखना होगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार वैसे तो नियमों को सदन से पास कराने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि किसी सदस्य ने इसमें संशोधन करने या इसे निरस्त करने का नोटिस दिया, तो उस पर चर्चा कराना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आगामी सत्र में सीएए को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है।

दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति के नागरिकता के आवेदन को प्रोसेस करने के लिए गृह मंत्रालय अपना अधिकार जिलाधिकारी को देता है। लेकिन मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि वह जिलाधिकारी के बजाय किसी अन्य अधिकारी को भी नागरिकता के आवेदनों को प्रोसेस के लिए चुन सकता है। इस बार चूंकि आवेदन की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी, इसीलिए जिलाधिकारी की भूमिका सीमित या नगण्य हो सकती है। गृह मंत्रालय सुविधा के अनुसार किसी जिले में जिलाधिकारी को, तो किसी अन्य जिले में दूसरे अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है। बंगाल जैसे विपक्ष शासित राज्यों में वेरीफिकेशन का अधिकार पोस्ट आफिस या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को भी दिया जा सकता है।

राजनीतिक और सामाजिक नफा-नुकसान का समीकरण

प्रथम पृष्ठ से आगे

तृणमूल कांग्रेस शुरू से सीएए का विरोध करती आ रही है। उसका कहना है कि मतुआ समुदाय को पहले से सभी नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। भाजपा सीएए के नाम पर इन्हें गुमराह कर रही है। भाजपा का कहना है कि सीएए को लेकर तृणमूल मतुआ समुदाय को गुमराह कर रही है। दरअसल, सीएए लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा मतुआ समुदाय को होगा। वर्ष 2019 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए सीएए का उद्देश्य 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। माना जा रहा है कि अगर सीएए लागू होता है तो बंगाल में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले मुस्लिमों की बड़ी आबादी नागरिकता पाने के अधिकार से वंचित हो जाएगी, जो टीएमसी का वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को सीएए लागू होने से मतुआ समुदाय का वोट बैंक पूरी तरह से खिसकने का डर है। इसलिए वह इसका विरोध करती हैं।

इसलिए मतुआ समुदाय पर रहती है राजनीतिक दलों की नजर : बंगाल की अनुसूचित जाति की आबादी में मतुआ समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। पिछली सदी के पांचवें दशक में यह समुदाय मुख्यरूप से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में धार्मिक उत्पीड़न के कारण बंगाल की ओर पलायन कर गया था। पिछली सदी के नौवें दशक के बाद से बंगाल में राजनीतिक दलों ने सक्रिय रूप से मतुआ समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश शुरू की, क्योंकि ये अपनी उल्लेखनीय आबादी और एक साथ मतदान करने की प्रवृत्ति के कारण एक अहम वोट बैंक माने जाते हैं। इनकी आबादी करीब एक करोड़ है तथा बंगाल की लगभग 70 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है।

'एलएसी पर हालात स्थिर, लेकिन संवेदनशील'

सेना प्रमुख ने कहा, पिछले एक वर्ष में नहीं बना टकराव वाला कोई और क्षेत्र

नई दिल्ली, एएनआइ : थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हालात स्थिर, लेकिन संवेदनशील हैं। लेकिन पिछले एक वर्ष में भारत और चीन के बीच टकराव वाला कोई और क्षेत्र नहीं बना है। जनरल पांडे ने एक साक्षात्कार में कहा, 'समाधान के प्रयासों की बात करें तो चीन के साथ सैन्य स्तर के साथ-साथ राजनयिक स्तर पर भी वार्ता और संवाद जारी है। अप्रैल, 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच 20 उच्चस्तरीय सैन्य वार्ताएं और भारत-चीन सीमा मामलों पर वर्किंग मैकेनिज्म फार कंसल्टेशन एंड कोआर्डिनेशन (डब्ल्यूएमसीसी) की 14 बैठकें हो चुकी हैं।' उल्लेखनीय है कि मई, 2020 में जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में आक्रामक रूप से यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था, तभी से दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चों पर अपने सैन्य बल तैनात कर रखे हैं।

उत्तरी सीमा पर सेना की तैयारियों के बारे में जनरल पांडे ने कहा, 'हमारी तैनाती मजबूत व संतुलित है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमने पर्याप्त रिजर्व भी रखे हैं। जब यह सब कुछ हो रहा है तो हम नई तकनीक का इस्तेमाल, आधुनिकीकरण और सुरक्षा वाहनों, निगरानी ड्रोन, बेहतर संचार रेडियो सेट जैसी बेहतर प्रणालियों को शामिल करके अपनी क्षमताओं के विकास पर भी फोकस कर रहे हैं। साथ ही हमारा प्रयास एवं फोकस बुनियादी ढांचा विकास पर भी है।

आतंकियों से निपटने का अभियान जारी रहेगा : जनरल पांडे ने कहा कि पिछले वर्ष नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर हिंसा के स्तर में कमी आई है और सेना एलओसी व भीतरी इलाकों में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए अपना अभियान लगातार जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि 2023 में जम्मू-कश्मीर में 71 आतंकियों को मार गिराया गया जिनमें से 35 अंदरूनी इलाकों में मारे गए। राजौरी एवं पुंछ में हाल ही में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि के बारे में कहा कि एलओसी पर तैनाती और घुसपैठ रोधी प्रणालियों को मजबूत किया गया है।

आयात निर्भरता लगभग शून्य करने की जरूरत

सेना में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जनरल पांडे ने कहा, 'कोविड महामारी व रूस-यूक्रेन युद्ध से सीखा गया एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें आत्मनिर्भर बनने और अपनी आयात निर्भरता लगभग शून्य करने की जरूरत है। इसके लिए हम देश की नवाचार क्षमता के साथ-साथ वाइब्रेंट स्टार्टअप ईकोसिस्टम का लाभ उठाना चाहते हैं।' उन्होंने बताया कि भविष्य में सेना की लगभग शत प्रतिशत खरीद स्वदेशी रूट से की जाएगी। आज की तिथि में आर्मी डिजायन ब्यूरो लगभग 350 डिजायन एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिसमें वे डीआरडीओ सहित लगभग 450 उद्योगों से जुड़ रहे हैं। लागत के लिहाज से यह लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये है। सेना प्रमुख ने कहा, 'हम क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षणों के अंतिम चरण में हैं, इसके पूरा हो जाने पर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्रिप्शन एंट टेक्नोलाजी के जरिये बेहतर सुरक्षित कम्युनिकेशन होगा।'

यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में घटी युवा बेरोजगारी दर

▶ **वित्त मंत्रालय ने कहा, 2022-23 में 10 प्रतिशत रही 15-29 उम्र वर्ग की बेरोजगारी दर**

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएएनएस : वित्त मंत्रालय द्वारा अर्थव्यवस्था पर जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं के बीच बेरोजगारी दर में गिरावट का नेतृत्व युवा आबादी की बड़ी हिस्सेदारी वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश) ने किया। रिपोर्ट में श्रम आवधिक बल सर्वे के हवाले से कहा गया है कि 15-29 उम्र वर्ग की बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8 प्रतिशत घटकर 2022-23 में 10 प्रतिशत हो गई है।

इसी तरह युवाओं की श्रम बल भागीदारी दर 38.2 प्रतिशत से बढ़कर 44.5 प्रतिशत हो गई। इन छह वर्षों में रोजगार पाने वाले युवाओं का अनुपात 31 प्रतिशत से बढ़कर 40.1 प्रतिशत हो गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं के बीच बेरोजगारी दर घटाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 2021 के जनसंख्या अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6.9 करोड़, बिहार में 3.5 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़ युवा हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 2017-18 के 16.7 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में सात प्रतिशत हो गई है। इसी तरह प्रदेश में युवाओं की श्रम बल भागीदारी दर 33.7 प्रतिशत से बढ़कर 41.4 प्रतिशत हो गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2015 से अब तक 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसकी बदौलत वर्ल्ड स्किल प्रतिस्पर्धा में भारत 2022 में 11वें स्थान पर रहा जबकि 2011 में 39वें स्थान पर था।

(पेज 10 भी देखें)

गौरव गान

नई दिल्ली के विजय चौक पर तीनों सेना के साथ अर्धसैनिक सैनिक बल के बैंड ने दी 31 धुनों की प्रस्तुति

बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय धुनों की प्रस्तुति ने भरा जोश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विजय चौक पर सोमवार को बीटिंग रिट्रीट में सेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड की संगीतमय प्रस्तुति के साथ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पारंपरिक बग्गी में महोत्सव स्थल तक पहुंचीं और सलामी लीं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आम लोगों ने इस उत्सव का आनंद उठाया।

बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जब सेनाएं सूर्यास्त होने पर लड़ना बंद कर देती थीं और युद्ध मैदान से शिविरों में लौटती थीं। यह समारोह बीते समय की यादें ताजा करता है। भारतीय थलसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना समेत अर्धसैनिक बल के संगीत बैंड ने दर्शकों के सामने मनमोहक और झूमने पर मजबूर कर देने वाली 31 भारतीय धुनें बजाईं। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड की 'शंखनाद' धुन के साथ हुई। उसके बाद पाइप और ड्रम बैंड की ओर से वीर भारत, संगम दूर, देशों का सरताज भारत और अर्जुन जैसी मनमोहक धुनें प्रस्तुत की गईं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड ने भारत के जवान और विजय भारत धुन प्रस्तुत की। भारतीय वायुसेना के बैंड ने 'टाइगर हिल', 'रेजाइस इन रायसीना' और 'स्वदेशी' के धुन बजाई, जबकि भारतीय नौसेना के बैंड की धुनें 'आइएनएस विक्रांत', 'मिशन चंद्रयान', 'जय भारती' और 'हम तैयार हैं' का दर्शकों ने आनंद उठाया। थलसेना के बैंड ने 'फौलाद का जिगर', 'अग्निवीर', 'कारगिल 1999' और 'ताकत वतन' सहित कई धुनें प्रस्तुत कीं। सामूहिक बैंड 'कदम कदम बढ़ाए जा' और 'ड्रमर्स काल' की धुन ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का समापन 'सारे जहां से अच्छा' के साथ किया गया। समारोह के मुख्य संचालक लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी रहे।

नई दिल्ली में सोमवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान देशभक्ति की स्वदेशी धुन बजाता सेना का बैंड। एएनआइ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में पारंपरिक बग्गी से पहुंचीं। ध्रुव कुमार

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

बिहार में अब महागठबंधन में वैकेंसी, एनडीए हाउसफुल

जदयू के जाने के बाद कांग्रेस-वामदल मांगेंगे बड़ी हिस्सेदारी

एनडीए में जीतन राम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा का घटेगा कद

कुमार रजत, पटना

जदयू की राजग में वापसी ने बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों के गणित भी बदल गए हैं। राजग में अभी तक बड़ी पार्टी के रूप में सिर्फ भाजपा थी। हम, लोजपा के दोनों गुट और रालोजद जैसे छोटे दल थे। मगर जदयू की इंट्री ने सीटों की बड़ी हिस्सेदारी छीन ली है। वहीं, दूसरी ओर आइएनडीआइए में जदयू-राजद के होने से कांग्रेस और वामदलों की दावेदारी कमजोर थी मगर अब मैदान खाली है। आइएनडीआइए इस खाली जगह को भरने के लिए मुकेश सहनी की वीआइपी (विकासशील इंसान पार्टी) या ओवैसी की एआइएमआइएम जैसे दलों को अपने साथ जोड़ सकता है।

वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो राजग के लिए सीट बंटवारा अधिक मुश्किल नहीं था। लोकसभा की कुल 40 सीटों में भाजपा और जदयू को 17-17 सीटें मिली थीं, जबकि लोजपा (लोक जनशक्ति पार्टी) को छह सीटें दी गई थीं। इस बार जदयू-भाजपा के साथ लोजपा दो खेमे में बंट गई है। अगर, छह जीती सीटों पर चिराग और पशुपति पारस वाले दोनों खेमों को मना भी लिया जाए तो जीतन राम मांझी की हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) और उपेंद्र कुशवाहा की रालोजद (राष्ट्रीय लोक जनता दल) के लिए सीट निकालने की चुनौती होगी।

हम और रालोजद को एक-एक सीट: पिछले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा था। उस समय पार्टी ने तीन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, मगर तीनों पर हार का सामना करना पड़ा। इस बार हम को एक से अधिक सीट मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। वह एक सीट गया की हो सकती है। जीतन राम मांझी या उनके बेटे संतोष कुमार सुमन चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) को महागठबंधन में पांच सीटें दी थीं। कारण, उनके पास तीन सीटिंग सांसद थे। हालांकि, सभी पांच सीटों पर रालोसपा को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उनके दल का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल (रालोजद) है। इस बार कुशवाहा के पास एक भी सांसद नहीं है। फिलहाल उन्हें काराकाट की पेशकश की जा सकती है, जहां से वे 2014 में सांसद थे।

2019 में राजग में सीटों का बंटवारा

2019 में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा

राजद-19, कांग्रेस-9, रालोसपा-5, हम-3, वीआइपी-3, आरा सीट पर राजद ने भाकपा-माले को समर्थन दिया था।

- लेफ्ट फ्रंट : दोनों गुटों से अलग 17 सीटों पर लड़ा था।

कांग्रेस-वाम दल अब मांगेंगे दोगुनी सीटें

महागठबंधन में जदयू के रहते कांग्रेस और वाम दल को छह-आठ सीटों से अधिक नहीं मिलतीं। लेकिन, अब इनकी दावेदारी बढ़ जाएगी। कांग्रेस कम से कम 10-12 और वामदल चार से छह सीटें मांग सकते हैं। विधानसभा चुनाव के अनुभव को देखते हुए राजद भी कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे में कांग्रेस, वामदलों और अन्य नए साथियों को करीब 15 सीटें मिल सकती हैं।

उप्र में सपा से 14-15 सीटों पर कांग्रेस की बन सकती है बात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के साथ प्रदेश में 14-15 लोकसभा सीटों पर गठबंधन की बात बन सकती है। बिहार और बंगाल में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए को लगे झटके के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन की एकतरफा घोषणा शनिवार को ही कर चुके हैं। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी दबाव में है, साथ ही पिछले कई चुनाव में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में सपा की ओर से उसे तीन-चार सीटें ही और मिलने की उम्मीद है। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए में शामिल सपा, कांग्रेस व रालोद मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रालोद से सात सीटों पर समझौता करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं। सपा ने रालोद की तरह कांग्रेस के साथ समझौते के तहत दी जाने वाली सीटों के बारे में नहीं बताया है। हालांकि, सपा मुखिया द्वारा की गई घोषणा से कांग्रेस की प्रदेश इकाई खुश नहीं है, वह ज्यादा सीटें चाह रही है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व 20 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि, उसके नेता सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गठबंधन की सीटों पर केंद्रीय कमेटी निर्णय ले रही है। बहुत अच्छे वातावरण में बात चल रही है, जल्द ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे। वहीं, सपा भी कांग्रेस पर पूरा दबाव बनाए हुए है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि यह चुनाव टिकट बंटवारे का नहीं है। भाजपा को हराना है और लोकतंत्र बचाना है। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाने के साथ ही कांग्रेस का सम्मान रखते हुए पहले ही 11 सीटें दे दी हैं।

अखिलेश यादव। फाइल

वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से दबाव में है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व

सपा अध्यक्ष कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन की कर चुके हैं घोषणा

सीट बंटवारे पर तृणमूल से बातचीत जारी : जयराम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आने वाले लोकसभा चुनाव में बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस और तृणमूल के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। यह बातें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहीं। वह बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आइएनडीआइए को मजबूत करने पर सभी का पूरा ध्यान है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी आइएनडीआइए को समर्थन हासिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं का मकसद आइएनडीआइए को मजबूत करना है।

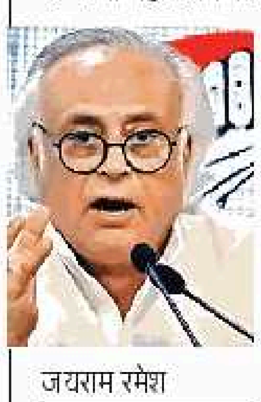

जयराम रमेश

नीतीश मंत्रिमंडल के नए चेहरों पर टिकी सबकी नजर

सुनील राज, पटना : बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही कयास के बिंदु बदल गए हैं। अब चर्चा आने-जाने की नहीं, उन चेहरों की है जो बतौर नए मंत्री विभागों की कमान संभालेंगे। जदयू में मंत्रियों के नाम करीब-करीब तय माने जा रहे हैं।

पुरानी सरकार में मंत्री रह चुके भाजपा के बड़े चेहरे भी संशय में हैं कि उनका क्या होगा? कहा जा रहा है कि भाजपा कोटे से बने तीन मंत्रियों के अलावा और सात लोगों को फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सर्वाधिक तवज्जो पुराने चेहरों को ही दी जाएगी। नए चेहरे अधिक से अधिक 20 प्रतिशत ही होंगे। दूसरी ओर, जदयू में सब करीब-करीब तय माना जा रहा है। अधिकांश चेहरे पुराने ही होंगे नई मंत्रिमंडल में, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का ऐसा ही दावा है। कुछ नाम जरूरत कट सकते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि नए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना है। परंतु इन दावों पर मुहर लगाने वाला दोनों दलों में कोई भी नहीं है। चर्चा है कि भाजपा कोटे से शाहनवाज, श्रेयसी सिंह, जनक राम, जीवेश कुमार, नितिन नवीन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जबकि, जदयू कोटे से लेशी सिंह, शीला मंडल, जयंत राज, संजय झा जैसे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नंद किशोर यादव और अमरेंद्र प्रताप सिंह का नाम है।

मोदी फिर पीएम बने तो देश में चुनाव नहीं होने देंगे : खरगे

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि भाजपा का काम केवल लोगों को लड़ाकर सत्ता में बने रहना है। नरेन्द्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह देश में चुनाव नहीं होने देंगे। यह देश में आखिरी चुनाव होगा। खरगे सोमवार को भुवनेश्वर में ओडिशा बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। खरगे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस अगर कुछ नहीं करती तो मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बनते। देश में आज भी 30 लाख वैकेंसी है। हर साल दो करोड़ नौकरी देने की गारंटी मोदी ने दी थी, दी क्या? मोदी, आपको दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको अपना हक चाहिए तो मोदी को सत्ता में आने से रोकना होगा।

नीतीश के जाने से कमजोर नहीं होगा आइएनडीआइए : बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर खरगे ने कहा कि किसी एक के जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होगा।

ओडिशा बचाओ रैली के बहाने कांग्रेस ने भुवनेश्वर में किया शक्ति प्रदर्शन

भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करते मल्लिकार्जुन खरगे। जागरण

'वे जो थोपेंगे, उसी को देवता मानने के लिए में बाध्य नहीं'

जासं, कूचबिहार : वे जिस देवता को मानने के लिए कहेंगे, उसे ही मानना होगा, ऐसा करने के लिए मैं बाध्य नहीं। धर्म को लेकर सबकी अपनी-अपनी भावनाएं हैं। वे मदनमोहन मंदिर, जल्पेश्वर और मां दुर्गा की बात नहीं करते हैं। मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं। कूचबिहार में आयोजित कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाम लिए बगैर कुछ इसी अंदाज में भाजपा पर हमला बोला।

'बिहार के पास है सबसे बेहतर रिवर्स स्विंग गेंदबाज'

अक्षय पांडेय, पटना

बिहार के राजनीतिक निर्णय से अगर जनता किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती हो, तो यह भूल हो सकती है। सियासत ने ऐसा घटनाक्रम पैदा किया है कि इंटरनेट मीडिया की गलियों में सकारात्मक-नकारात्मक भाव से नीतीश कुमार का नाम फर्राटा भर रहा है। प्रतिक्रियाओं की बाढ़ में 'पाटलिपुत्र' भी 'पलटीपुत्र' बन गया है। वर्षों से एक सीएम और विपक्ष के समय-समय पर बदलने का परिणाम स्क्रीन पर अंगुली चलाकर यह निकाला जा रहा कि बिहार के पास सबसे बेहतर रिवर्स स्विंग गेंदबाज है।

वेब सीरीज 'महारानी' का एक डायलाग खूब साझा किया जा रहा, बिहार की एक खासियत है, जब-जब आपको लगता है आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है। एक्स पर अमित प्रकाश राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर साझा कर पूछ रहे हैं, पांच बार चुनाव हुए, नीतीश कुमार ने नौ बार शपथ कैसे ले ली? फेसबुक पर प्रतीक भारद्वाज का दर्द थोड़ा गंभीर समझ आ रहा। वह कह रहे, भांजी की बड़ी मुश्किल से बताया था कि एक सरकार का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, अब बिहार का उदाहरण देकर उसका प्रश्न मेरा दिमाग चकरा दे रहा है। एक्स पर विकास मिश्र के पोस्ट को खूब पसंद किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, ये क्या है भाई, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। रितु लिखती हैं, जैसे हर सब्जी के लिए आलू की जरूरत होती है, वैसे ही बिहार के लिए नीतीश जरूरी हैं। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिया से निकलकर गीत 'मोये-मोये' (बुरा सपना) बिहार की राजनीतिक पिच पर बैटिंग कर रहा है। प्रीति कुमारी कहती हैं, अबतक गुनगुना रहे थे, अब 'मोये-मोये' हो गया है। मोहन लिखते हैं, मरना हो या जीना हो, कुछ भी कबूल है, पर कप्तान तो हम ही रहेंगे। मुख्यमंत्री के एक समर्थक निशांत कहते हैं कि 'पलटूराम' बोलने का एक फायदा तो है, कम से कम मुंह से 'राम' तो निकलता है।

राजनीतिक घटनाक्रम पर इंटरनेट मीडिया पर लोगों की रोचक टिप्पणियां

सामाजिक न्याय के अगुआ बिहार को करनी है निर्णायक पहल : राहुल

विकास चन्द्र पाण्डेय, किशनगंज

दोपहर की खड़ी धूप से तमतमाए चेहरे पर मुदुल भाव लाने का भरपूर जतन करते हुए राहुल गांधी सोमवार को बिहार से सामाजिक न्याय के नेतृत्व का विनम्र निवेदन कर गए। किशनगंज के अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम में उपस्थित जनसमूह से उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना देश की प्रगति अधूरी और बेमानी है। इसके लिए जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे केंद्र सरकार कन्नी काट रही। अनवरत उपेक्षा से गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग मर्माहत है। बिहार सामाजिक न्याय का अगुआ रहा है। आज पूरा देश अपेक्षा के साथ उसका मुंह ताक रहा। इस बार बिहार को निर्णायक पहल करनी है और उसके लिए हृदय से आभार है।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 16वें दिन राहुल सीमांचल के रास्ते बिहार में प्रवेश किए। बिहार में चार जिलों (किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार) को जोड़कर सीमांचल का स्वरूप बनता है। भव्य स्वागत से अभिभूत राहुल ने न्याय यात्रा को सिर-आंखों पर लेने के लिए बिहार का बारंबार आभार प्रकट किया। किसी की सराहना-आलोचना से परे राहुल ने केवल देश, काल और समाज की बात की। उन पांच वर्ग-समाज (नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय) का उल्लेख किया, जिसके हक में यह न्याय यात्रा निकाली गई है। उनकी हर बात पर जयकारे लगा रहे किशनगंज के शमीम अख्तर और संजीव राय का कहना है कि परिवर्तन अचानक नहीं होगा। राहुल एक दीर्घकालिक उपक्रम पर निकले हैं, जिसका सुफल अवश्य मिलेगा, भले ही समय लगे। इस संभावना से सहमति जताते हुए कांग्रेस नेताओं की यह खुसुर-फुसुर भी इधर-उधर फैल जा रही कि काश, यह जुटान वोट में परिवर्तित हो जाता!

मोहब्बत की दुकान (बस) से अभिवादन लेते-देते राहुल को देखने-सुनने के लिए किशनगंज से अररिया तक जगह-जगह टांट की तरह बिछ आई जनता ने फूल भी बरसाए और जयकारे भी लगाए। करीने से तराशी गई दाढ़ियों और सलीके से ओढ़े गए बुर्के के पीछे एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी-चौथी कतार बता रही कि सीमांचल में मुस्लिमों की जनसंख्या औसतन 60 प्रतिशत से अधिक है। कभी सवर्ण और दलित के साथ मिलकर यह जनसंख्या कांग्रेस की अजेय आधार थी। आज भी यह बिहार में कांग्रेस के लिए उर्वर क्षेत्रों में से एक है। पार्टी के एकमात्र सांसद इसी क्षेत्र से हैं और 19 में से पांच विधायक भी। इस क्षेत्र ने ऐसे पलक-पांवड़े बिछाए कि राहुल सूर्यास्त के बाद ही अररिया में जीरोमाइल तक पहुंच पाए। अंत में वह खड़गेश्वरी काली मंदिर के समक्ष नतमस्तक हो गए। माथे पर रोली-अक्षत का टीका लगाए कालेज पहुंचे।

कभी अजेय रहे सीमांचल में की देश, काल व समाज की बात

देर शाम खड़गेश्वरी काली मंदिर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी

बिहार के किशनगंज में सोमवार को न्याय यात्रा के दौरान बच्चे को गले से लगाए राहुल गांधी। जागरण

राहुल पर अशोभनीय टिप्पणी, सुवेंदु के खिलाफ केस करेगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करने पर बंगाल कांग्रेस राज्य के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्यभर के विभिन्न थानों में एफआइआर दर्ज कराएगी। दरअसल, एक टीवी चैनल द्वारा बार-बार राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रश्न पूछे जाने पर सुवेंदु भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का दावा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपमानजनक है।

सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि जो (राहुल गांधी) यह कह रहा है कि सुबह में स्टोव पर कोयला रखकर चाय बनाई जाती है। स्टोव पर कोयला रखकर चाय बनाते हुए तो मैंने न तो देखा, न सुना है। जिसकी समझ इतनी है, उसे क्यों गिनते हो? बंगाल में अप्रासंगिक पार्टी है। इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। सुवेंदु की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि उनके (सुवेंदु अधिकारी) लिए राहुल गांधी की राजनीति को समझना संभव नहीं है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता, मंत्री व सांसदों ने भी घटना की निंदा करते हुए एक्स हैंडल से सुवेंदु पर निशाना साधा।

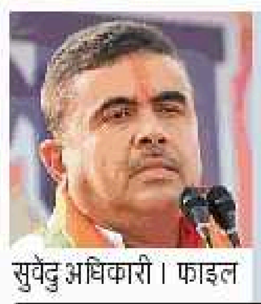

सुवेंदु अधिकारी। फाइल

राहुल गांधी के नाम का उल्लेख किए बिना एक्स पर तृणमूल ने भी नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना

मप्र में भाजपा का गढ़ बनीं कई सीटें, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती

राज्य ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश में लोकसभा की कई सीटें भाजपा का गढ़ बन चुकी हैं। इन्हें जीत पाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें इंदौर और भोपाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इंदौर में वर्ष 1984 में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी जीते थे। इसके बाद 1989 से लगातार भाजपा के कब्जे में यह सीट रही है। यही स्थिति भोपाल की है। यहां से आखिरी बार कांग्रेस प्रत्याशी केएन प्रधान 1984 में जीते थे। इसके बाद 1989 से यहां भी लगातार भाजपा जीतती रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को यहां से लड़ाया, पर उन्हें भी हार मिली। पार्टी अब इन सीटों पर जीत के लिए नए और दमदार चेहरे आगे करने की तैयारी में है।

छिंदवाड़ा ही ऐसी सीट, जहां कांग्रेस जीती रही : एकमात्र छिंदवाड़ा ही ऐसी सीट है, जहां एक बार को छोड़ कांग्रेस लगातार जीतती रही है। 1997 के उप चुनाव में यहां से भाजपा के सुंदरलाल पटवा जीते थे।

मुश्किल सीटों पर कांग्रेस की ऐसी है तैयारी: कांग्रेस ने सभी लोकसभा सीटों के लिए समन्वयक नियुक्त किए हैं, जो क्षेत्र में जाकर तथ्य के समीकरणों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी के अलग-अलग स्तर पर प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वे भी हो रहा है। सभी पहलुओं के साथ कांग्रेस यह भी नजर रख रही है कि भाजपा किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे जातिगत समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी की तलाश की जा सके। इसके साथ ही उन मतदान केंद्रों पर, जहां पार्टी पिछले चार चुनाव में लगातार हार रही है, घर-घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आम सहमति से किसी एक दावेदार का नाम ही चिह्नित किया जाए। तीन फरवरी से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी।

कांग्रेस अब इन सीटों पर दमदार चेहरे उतारने की कर रही तैयारी

इन लोस सीटों पर भाजपा लंबे समय से विजेता

- 1989- इंदौर, भोपाल, भिंड, विदिशा, दमोह,
- 1996- जबलपुर, बैतूल, मुरैना, सागर,
- 1998- सतना, बालाघाट
- 2004- खजुराहो
- 2007- ग्वालियर,
- 2009- खरगोन, सीधी, टीकमगढ़
- 2014- शहडोल, मंडला, रीवा, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, धार, खंडवा
- 2019 - गुना, रतलाम

कांग्रेस के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया ने दिया त्याग-पत्र

राज्य ब्यूरो, भोपाल

विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का क्रम थम नहीं रहा है। पूर्व प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुगालिया के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया ने भी प्राथमिक सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। पलिया विधानसभा चुनाव में सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला था। उनकी नाराजगी को देखते हुए तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया था। बता दें कि ग्वालियर-चंबल संभाग में कई कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने पर प्रवक्ता, पूर्व कांग्रेस के लिए उर्वर ... विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता त्याग-पत्र दे दिया था।

सतपाल पलिया। फाइल

आपत्ति

उद्धव ठाकरे ने कहा, क्या नार्वेकर को यह जिम्मेदारी सौंपना देश में लोकतंत्र को समाप्त करने वाला एक कदम माना जाए, राकांपा ने भी उठाए सवाल, कहा- उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपे जाने से बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है

नार्वेकर बने दलबदल कानून की समीक्षा समिति के अध्यक्ष ... विपक्षी नाखुश

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दलबदल कानून की समीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाना महाराष्ट्र के विरोध दलों को नहीं भा रहा है। शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे एवं राकांपा शरद पवार गुट के नेता जीतेंद्र आह्वाड ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महाराष्ट्र विधानभवन में बीते शनिवार-रविवार को हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 84वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दलबदल कानून की समीक्षा का निर्णय किया। इसके लिए बनने वाली समिति की अध्यक्षता का दायित्व महाराष्ट्र के ही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंपा। लेकिन, लोकसभा अध्यक्ष का यह चयन महाराष्ट्र के विरोधी दलों को अच्छा नहीं लग रहा है।

शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल किया है कि क्या राहुल नार्वेकर को यह जिम्मेदारी सौंपना देश में लोकतंत्र समाप्त करने वाला एक कदम माना जाना चाहिए। शिवसेना (उद्धव गुट) के ही प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भी नार्वेकर पर तंज करते हुए कहा कि शायद उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई होगी, क्योंकि उन्हें स्वयं दलबदल करने का काफी अनुभव है। राकांपा शरद पवार गुट के विधायक जीतेंद्र आह्वाड ने कहा है कि राहुल नार्वेकर को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने से बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है।

गौरतलब है कि विरोधी दलों की यह प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है, क्योंकि इसी माह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के दोनों गुटों की याचिका पर फैसला सुना चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने फैसले में किसी गुट के किसी विधायक को अपात्र नहीं किया। लेकिन उनके इस निर्णय से दोनों ही गुट असंतुष्ट हैं और दोनों गुटों ने न्यायालय का शरण ली है।

नार्वेकर ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनाया था। उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित बगावत करने वाले 16 विधायकों को अपात्र ठहराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उसे अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट इन विधायकों को अपात्र घोषित कर देगा और शिंदे सरकार गिर जाएगी। लेकिन उसने यह फैसला करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया था। नार्वेकर ने किसी गुट के किसी भी विधायक को अपात्र नहीं ठहराया। इससे दोनों गुटों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राहुल नार्वेकर को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपा जाना उद्धव गुट एवं शरद पवार गुट को रास नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि ओम बिरला ने उन्हें यह जिम्मेदारी उनके हाल के अनुभव को देखते हुए ही सौंपी है, क्योंकि हाल के वर्षों में शिवसेना और राकांपा जैसी टूट किसी और राज्य में देखने को नहीं मिली है। ये दोनों मामले पेचीदा थे। इनमें से शिवसेना के मामले में नार्वेकर 1200 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर फैसला सुना चुके हैं और राकांपा के मामले में कुछ ही दिनों में फैसला सुनाने वाले हैं। स्वयं कानून के विद्यार्थी रहे युवा विधायक राहुल ने इन दोनों मामलों में दलबदल कानून का गहरा अध्ययन किया है। संभवतः इसीलिए उन्हें अन्य राज्यों के अनुभवी विधानसभा अध्यक्षों की तुलना में इस समिति की अध्यक्षता के लिए अधिक योग्य माना गया है।

राहुल नार्वेकर

उद्धव ठाकरे। फाइल

हार पर चर्चा के दौरान भिड़े मप्र कांग्रेस प्रवक्ता व अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की कसक कांग्रेस नेताओं में बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय परिसर में सोमवार को जब चुनाव में हार को लेकर चर्चा हो रही थी, तब वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी बताते हुए अपशब्दों के उपयोग पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप अहिरवार आपस में भिड़ गए। उनके बीच धक्का-मुक्की हो गई, जिसमें शहरयार गिर पड़े। बात इतनी बढ़ी कि अहिरवार ने मारने के लिए कुर्सी उठा ली, पर वहां उपस्थित अन्य पदाधिकारियों ने उसे उनसे छीन लिया। काफी देर तक दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप होते रहे। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले सहित अन्य पदाधिकारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। बाद में शहरयार का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्द का उपयोग किया जा रहा था। वरिष्ठ नेता के प्रति इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जब ऐसा करने से मना किया तो अहिरवार हाथापाई पर उतर आए। अहिरवार ने आरोप लगाया है कि विवाद नहीं हुआ, शहरयार दलित विरोधी हैं और मुझसे वैमनस्यता रखते हैं।

मैं अपनी बात कह रहा था तो लड़ने पर उतारू हो गए और दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा ने इसका वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि कमल नाथ समर्थक द्वारा दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्द बोलने पर प्रदेश कांग्रेस में जमकर लात-घूंसे, कुर्सियां चलीं।

प्रदीप अहिरवार ने शहरयार खान को मारने के लिए उठा ली कुर्सी

3.30 बजे सोमवार दोपहर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन मंगलवार सुबह पांच बजे अयोध्या पहुंचेगी। 31 जनवरी को वापस लौटेगी।

दर्शन व्यवस्था के प्रति पूर्ण तत्पर रहें अधिकारी : योगी

श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ की बैठक

प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या 10 गुना तक जा पहुंची

जागरण संवाददाता, अयोध्या

भव्य मंदिर में श्रीरामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या 10 गुना तक जा पहुंची है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो विशेष रूप से आमंत्रित सात हजार अतिथियों को ही श्रीरामलला के दर्शन का अवसर मिला, किंतु इसके बाद की सात दिन की अवधि में श्रीरामलला के दर्शनार्थियों की संख्या 20 लाख के पार पहुंचने का अनुमान है। इस तथ्य से मुख्यमंत्री भी परिचित हैं और अपने दायित्व के प्रति सजग मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर सहित संपूर्ण श्रीरामजन्मभूमि परिसर और दर्शन मार्गों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पूरी तरह तत्पर रहने का निर्देश दिया।

इस दौरान मंडलायुक्त गौरव दयाल ने सुलभ दर्शन के लिए किए गए प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री के निर्देश पर किए गए प्रबंधों के संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखकर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान 'बालकराम' के दर्शन किए और अधिकारियों के साथ कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा की। एएनआइ

रामलला के सम्मुख हुए साष्टांग समर्पित : हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन-पूजन किए। वहां मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह रामलला के सम्मुख साष्टांग समर्पित हुए। मुख्यमंत्री की भक्ति देखकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित अर्चक गण, आम श्रद्धालु और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी भी निहाल हो उठे।

एक सप्ताह में 21.5 लाख भक्तों ने किए रामलला के दर्शन

जागरण संवाददाता, अयोध्या : प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन की आस लेकर रामलला के देहरी तक आने वाले भक्तों का क्रम जारी है। बीते एक सप्ताह के आंकड़ा देखें तो सोमवार की रात्रि में दस बजे पट बंद होने तक 21.5 लाख भक्त रामलला समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित कर चुके थे। इससे पहले 13 सितंबर, 2021 को जब वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कारिडोर का लोकार्पण हुआ था तब वहां एक सप्ताह में 17 लाख भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए थे। रामभक्तों की उमड़ती भीड़ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी अपनी पांच शताब्दियों की अकुलाहट रामलला के एक दर्शन से मिटाना चाह रहे हैं। सोमवार को भी पट बंद होने तक दो लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या से लौटे दर्शन करने वालों की भीड़ मंदिर में बढ़ गई। पहले यही तय था कि 23 से ही दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन भक्तों का उल्लास और भीड़ देखकर 22 को ही रात दस बजे तक रामलला के दर्शन कराए गए। अगले दिन तो इतनी भीड़ उमड़ी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक अयोध्या पहुंचना पड़ा और उस दिन पांच लाख लोगों ने रामलला की छवि निहारी। इधर, अफसर व्यवस्था में जुटे हैं क्योंकि दूसरे राज्यों से विशेष ट्रेनें आनी प्रारंभ हो गई हैं।

प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने पर इमाम के विरुद्ध फतवा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने पर आल इंडिया इमाम आर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डा. उमेर अहमद इलियासी के विरुद्ध फतवा जारी किया है, जिसमें उनके धार्मिक बहिष्कार के आह्वान के साथ जान से मारने तक की धमकी दी गई है। इस संबंध में इमाम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। उधर, विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि इस मामले में खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले संगठन और लोगों की चुप्पी पर गंभीर सवाल है। इमाम डा. उमेर अहमद इलियासी ने बताया कि प्रभु राम के मंदिर जाने के साथ ही उनके द्वारा इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म तथा राष्ट्र को धर्म से ऊपर बताने से कट्टरपंथी नाराज हैं।

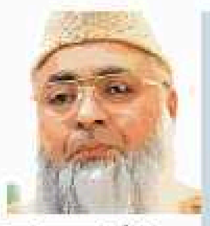

डा. इमाम उमेर अहमद इलियासी।

इमाम बोले, फोन व इंटरनेट माध्यमों से मिल रही धमकियां, लेकिन मैं डरने वाला नहीं

घाट पर पानी लाने को मोड़ी गई सरयू नदी की धारा

जलयानों के लिए गुप्तारघाट पर नदी को गहरा करने के लिए की जा रही ड्रेजिंग

सरयू नदी के गुप्तारघाट पर कराई जा रही ड्रेजिंग। जागरण

जागरण संवाददाता, अयोध्या

अयोध्या में जल पर्यटन को बढ़ावा देने में सरकारी तंत्र जुट गया है, जिसकी कभी अयोध्यावासियों ने कल्पना भी नहीं की थी, उस दिशा में केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार जुटी है। सरयू नदी में नयाघाट से गुप्तारघाट तक जलयानों के संचालन के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वर्तमान में नदी का जलस्तर कम होने और धारा बदल जाने से जलयानों का संचालन नहीं हो पा रहा है। अब नदी की धारा को घाट की ओर मोड़ा जा रहा है। इसके लिए गुप्तारघाट पर सरयू नदी में तकरीबन 100 मीटर बाड़ बनाई गई है। घाट पर पानी कम होने के कारण ड्रेजिंग भी कराई जा रही है, जिससे नदी गहरी हो जाए और जलयान घाट से होते हुए जेटी तक पहुंच सके। यह कार्य निरंतर चल रहा है। बता दें, ड्रेजिंग झीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के नीचे से तलछट और मलबे को हटाना है। सरयू का जलस्तर घटने से नदी ने रास्ता ही नहीं बदला, बल्कि घाटों से भी दूरी बना ली है। अब वहां किसान खेती कर रहे हैं। गुप्तारघाट से ही नदी की धारा काफी दूर चली गई और गोंडा जिले का हिस्सा बन गई। अगर कहीं पानी दिखता है तो केवल गुप्तारघाट और यहां से 10 किलोमीटर दूर रामकी पैड़ी के सामने पक्के घाट पर है। गुप्तारघाट पर ड्रेजिंग कर नदी के बहाव को घाट की ओर मोड़ा गया है, लेकिन अभी उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है। घाट की ओर नदी का पानी तो आ रहा है लेकिन 100 मीटर बाद ही बदली धारा में समाहित हो जा रहा है। सर्वाधिक सिल्ट लेकर चलने वाली सरयू नदी में जलयानों का संचालन सरकारी तंत्र के लिए चुनौती बना है। गुप्तारघाट पर नदी बमुश्किल तीन फीट ही गहरी है, जबकि जलयानों के संचालन को नदी का एक मीटर से अधिक गहरा होना आवश्यक है।

शबरी रसोई में मिल रही 55 रुपये की एक चाय, एडीए ने दिया नोटिस

जासं, अयोध्या

सुविधाएं प्रदत्त कराने के नाम पर रामनगरी में श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) की मल्टीलेवल कार पार्किंग अरुंधति भवन में संचालित रेस्तरां का है। शबरी रसोई के नाम पर संचालित इस रेस्टोरेंट में एक चाय 55 रुपये में दी जा रही है। यहां पहुंचे किसी ग्राहक ने रेस्तरां से मिले बिल को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। इसके बाद से मामला गरमा गया।

नगर निगम के पार्षद सूर्यकुमार तिवारी भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्हें भी एक चाय के 55 रुपये देने पड़े। उनके तीन और साथियों ने भी चाय पी। चारों चाय का बिल जीएसटी जोड़ कर 231 रुपये भुगतान करना पड़ा। उन्होंने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की और कहा कि यह तो श्रद्धालुओं का शोषण है। मामला तूल पकड़ता देख प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल सिंह की ओर से रेस्तरां संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी भी दी गई

उन्होंने खानपान की उचित दर निर्धारित करने का निर्देश दिया है। साथ ही नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी भी दी है।

रेस्तरां का संचालन कवच ग्लोबल कनेक्स नाम की संस्था कर रही है। संस्था के निदेशक तक्ष रावल ने बताया कि रेस्तरां वातानुकूलित व इकोनामी श्रेणी में है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित बिल वातानुकूलित श्रेणी का है। इस श्रेणी में सामान्य चाय की दर 30 रुपये है। चाय की गुणवत्ता के अनुसार दाम अलग-अलग हैं। इकोनामी क्लास में 15 रुपये की चाय है। रेस्तरां के रखरखाव एवं खानपान की गुणवत्ता के अनुपात में अन्य बड़े रेस्टोरेंट की तुलना में दरें उचित रखी गई हैं। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद उच्चाधिकारियों की ओर से जो निर्देश मिलेगा उसका अनुपालन कराया जाएगा।

तमिलनाडु सरकार ने पूजा के लिए 252 मंदिरों को अनुमति दी

नई दिल्ली, एएनआइ : तमिलनाडु सरकार ने प्रदेश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक के आरोपों से इन्कार करते हुए प्रदेश के डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। राज्य सरकार ने बताया कि 22 जनवरी को मंदिरों में विशेष पूजा की अनुमति के लिए कुल 288 आवेदन आए थे जिनमें से 252 को मंजूरी दे दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता की खंडपीठ को तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने बताया कि 36 आवेदनों को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अनुमति नहीं दी गई थी। अदालत ने अगली सुनवाई 15 दिन बाद के लिए सुनिश्चित की है।

डीजीपी ने बताया, 'भाजपा के प्रदेश सचिव विनोज पी. सेल्वम ने सरकार को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल गलत और निंदनीय है।' तमिलनाडु भाजपा ने आरोप लगाया था कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने सजीव प्रसारण पर रोक लगा दी थी।

लोस चुनाव से पहले 'दर्शन' से 'राममय' होगा देश

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा भगवान के दर्शन से देश को राममय करेगी। हालांकि, घोषित तौर पर भाजपा इस अभियान में मात्र रामभक्तों के सेवक की भूमिका में है, लेकिन जिस नियोजित ढंग से भाजपा इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, उससे स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही भगवा रंग हर राज्य और हर जिले में दिन ब दिन चटख ही होगा। भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इस मुद्दे का प्रभाव पूरे देश में दिखा। पूरा देश उल्लास में डूब गया था।

रामदर्शन के लिए पहले 29 जनवरी से ही आस्था स्पेशल ट्रेनों का नियमित संचालन करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन स्वप्रेरणा से अत्यधिक संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के दृष्टिगत व्यवस्थाएं प्रभावित न हों, इसलिए अब इनका नियमित संचालन पांच फरवरी से होगा। इसी कारण विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उनके मंत्रिमंडल के दर्शन की तिथियों में बदलाव संभावित है। आगामी तीन मार्च तक 311 ट्रेनें आएंगी।

अयोध्या धाम जंक्शन के प्लेटफार्म पर मौजूद राजस्थान के श्रद्धालु : जागरण

रामनगरी पहुंची पहली आस्था स्पेशल ट्रेन, स्वागत में बरसे श्रद्धा के फूल

जासं, अयोध्या : प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद रामलला का दर्शन कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सोमवार की सुबह पहली ट्रेन जयपुर तथा उसके बाद दोपहर 2.30 बजे दूसरी स्पेशल ट्रेन भगत की कोठी से अयोध्याधाम जंक्शन पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही श्रद्धालुओं के स्वागत में फूल बरसाए गए। स्टेशन श्रीराम का जयघोष से गूंज उठा। विहिप नेता राजाराम ने बताया कि दोनों ट्रेनों से करीब तीन हजार कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे है। राजस्थान से पांच ट्रेनें आना प्रस्तावित है, जिसमें सात हजार श्रद्धालुओं को रामनगरी में राममंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का दर्शन एवं सरयू स्नान कराया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के विश्राम का प्रबंध तीर्थक्षेत्र पुरम में किया गया है।

हालांकि, यह अभियान 24 मार्च तक चलेगा। बाद की तिथियों के लिए शीघ्र ट्रेनें तय होंगी। तीन मार्च तक प्रत्येक ट्रेन में 14 सौ से 15 सौ लोग अयोध्या आएंगे। प्रतिदिन आठ से 10 ट्रेन अयोध्या पहुंचेंगी। इसके साथ ही प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रवार भी लोगों को दर्शन कराने के लिए चार पहिया वाहनों व बसों से अयोध्या लाने की योजना है। इसी गणना से तीन मार्च तक ही देशभर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे।

दर्शन के अलावा पूरे देश से भाजपा कार्यकर्ता यहां सेवा देने आएंगे, जिससे श्रद्धालुओं से आसानी से संवाद स्थापित किया जा सके। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के कार्यकर्ता तमिलनाडु के लोगों की सेवा में लगेंगे, जिससे आपसी वार्तालाप में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि उन सभी राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका तय की गई है, जहां की भाषा हिंदी से भिन्न है। पूरी अयोध्या में 22 स्थानों पर भंडारे संचालित किए जाएंगे। इस यात्रा की मानीटरिंग राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल कर रहे हैं।

अयोध्या जाकर रामलला के चरणों में पगड़ी उतारेंगे सम्राट चौधरी

राज्य ब्यूरो, पटना : डेढ़ वर्ष से सिर पर पगड़ी बांध कर चल रहे बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है कि वह कब अपनी पगड़ी उतारेंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने यह मुरेठा (पगड़ी) सिर पर बांधी थी, तो मेरे लिए भावुक पल था। जिसमें मैंने वह बात कही थी। अब मैं अपने मुरेठा को प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित करने के लिए अयोध्या जा रहा हूं।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एवं मंत्री प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब मैंने पगड़ी बांधी थी कि तो उस समय मेरी मां का निधन हुआ था। उसी समय भाजपा ने मुझे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में पार्टी के सम्मान और उसके वजूद के लिए भावुक क्षण था, जब मैंने वह बात कही थी। अब हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। जहां मैं अपने मुरेठे को प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित करूंगा, साथ ही अपना मुंडन भी कराऊंगा।

...आखिर किसके आदेश पर बंद हुआ श्रृंगार गौरी का दर्शन-पूजन

जागरण संवाददाता, वाराणसी

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी समेत अन्य देवी-देवताओं के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे में परिसर का एएसआइ सर्वे हुआ है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कई बार सवाल आया कि आखिर किसके आदेश पर ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग की गई और उसकी पश्चिम दीवार पर मौजूद मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा के दर्शन-पूजन पर रोक लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विवादित ढांचा ध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के इस्तीफा देने के बाद 1993 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उस समय केंद्र में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। बैरिकेडिंग किसके आदेश पर हुई और मां श्रृंगार गौरी का दर्शन-पूजन किसने आदेश से रोका गया, यह जानकारी किसी को नहीं है।

मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में जस्टिस जेजे मुनीर के सामने भी यह सवाल उठा था कि किसके आदेश पर बैरिकेडिंग की गई और मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन पर रोक लगाई गई। उस वक्त उप्र सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने अदालत को बताया था कि इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं है। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष के वकीलों ने अदालत को जानकारी दी थी कि 1993 तक भूखंड आराजी संख्या 9130 (ज्ञानवापी) में मौजूद देवी-देवताओं का नियमित पूजा-पाठ होता था। छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ध्वंस के बाद 1993 में यहां पहले बांस-बल्ली और उसके बाद लोहे की ऊंची बैरिकेडिंग करा दी गई। स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में दाखिल मुकदमे के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी के अनुसार ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग से पहले पूरे ढांचे के चारों तरफ चार फीट का परिक्रमा पथ था। हिंदू मां श्रृंगार गौरी की पूजा करते और ढांचे की परिक्रमा करते थे। 1993 में पहले इसी परिक्रमा पथ पर बांस-बल्ली और फिर लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे वहां लोगों के प्रवेश पर रोक लग गई। इसके खिलाफ विजय शंकर रस्तोगी की ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक की अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया। उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की मांग करते हुए कहा था कि किसी लिखित आदेश के बिना बैरिकेडिंग की गई है। इसी मुकदमे में उन्होंने ज्ञानवापी में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही की मांग भी की। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह को कमिश्नर नियुक्त किया। उन्होंने परिसर में कमीशन की कार्यवाही की, लेकिन दक्षिणी व उत्तरी तहखाने में ताला बंद होने की वजह से वहां नहीं जा सके थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल भी की थी। हालांकि वादी पक्ष की ओर से उचित पैरवी नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज हो गया था। विजय शंकर रस्तोगी का कहना है कि बैरिकेडिंग होने के बाद काबिज लोगों के विरोध की वजह से पूजा-पाठ पर जबरन रोक लगा दी गई।

ज्ञानवापी में वैरिकेडिंग को लेकर मंदिर पक्ष कई वार उठा चुका है सवाल

प्रशासन या मस्जिद पक्ष की ओर से भी इस वारे में कभी जवाव दाखिल नहीं किया गया

श्रृंगार गौरी। फाइल

शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना एएसआइ से परीक्षण कराया जाए

प्रथम पृष्ठ से आगे

मंदिर पक्ष का कहना है कि इस क्षेत्र का मुस्लिम पक्ष के लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है, उनके मुताबिक तो यह कथित फव्वारा है। ऐसे में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी प्रकृति की पहचान करने के लिए एएसआइ से वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए। इसके लिए कोर्ट अपने 19 मई के आदेश को समाप्त करे जो इस पर रोक लगाता है। अर्जी में यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं की मांग पर जिला अदालत ने सील क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी के बाकी परिसर में एएसआइ को सर्वे का आदेश दिया था और एएसआइ ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। मंदिर पक्ष ने ये अर्जियां मस्जिद पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं पर दाखिल की हैं। मस्जिद पक्ष की तीन विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं जिनमें से एक में पूजा स्थल कानून को आधार बनाते हुए मंदिर पक्ष के मूल मुकदमे की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी गई है। दूसरे में शिवलिंग के परीक्षण को चुनौती दी गई है और तीसरी याचिका में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

ज्ञानवापी की परिक्रमा को जा रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मठ में ही रोका

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआइ) की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मूल विश्वनाथ मंदिर के प्रमाण मिल जाने के बाद सोमवार को उसकी परिक्रमा करने जा रहे ज्योतिष्पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने केदारघाट स्थित श्रीविद्या मठ में ही रोक दिया। पूरे मठ के चारों ओर काफी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। स्वामी के निकलते ही पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें धारा 144, नई परंपरा शुरू न करने व अनुमति नहीं होने का तर्क देते हुए रोका। अनुयायियों ने प्रतिरोध किया, लेकिन प्रशासन अडिग रहा।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अपने आराध्य की परिक्रमा कोई नई परंपरा नहीं है। स्वयं मैंने और मुझसे पूर्व अनेक आचार्यों ने कई बार ज्ञानवापी की परिक्रमा की है। मस्जिद पक्ष के सैकड़ों लोग प्रतिदिन वहां नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उनके लिए निषेधाज्ञा नहीं है। डेढ़ वर्ष से मुकदमा चल रहा है, इस दौरान मूल बाबा विश्वनाथ को पूजा, राग-भोग से वंचित कर दिया गया है।

मंजूरी

ड्रोन से सर्वेक्षण कराएगा उत्तरी रेलवे, 33.7 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा ट्रैक, बारामुला के सोपोर रेलवे स्टेशन से कुपवाड़ा के लिए बिछाई जाएगी रेललाइन

एलओसी से सटे कुपवाड़ा में गूंजेगी ट्रेन की सीटी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर एलओसी के साथ सटे कुपवाड़ा निकट भविष्य में जल्द ही रेल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उत्तरी रेलवे को कुपवाड़ा में रेललाइन बिछाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। वर्तमान में कश्मीर में रेल नेटवर्क बारामुला तक है जो बनिहाल-बारामुला रेल नेटवर्क का ही हिस्सा है।

कश्मीर में कुपवाड़ा को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग लंबे समय से हो रही है। केंद्र सरकार ने बीते वर्ष कुपवाड़ा तक रेल नेटवर्क के विस्तार की अनुमति दी थी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कुपवाड़ा के लिए रेललाइन बारामुला जिले के सोपोर रेलवे स्टेशन से बिछाई जाएगी। प्रस्तावित रेललाइन 33.7 किलोमीटर लंबी है। बनिहाल-बारामुला रेललाइन की लंबाई 136 किलोमीटर है और इसी मार्ग पर नौ किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग भी है जो बनिहाल और काजीगुंड रेलवे स्टेशन के बीच है। अधिकारियों ने बताया कि सोपोर से कुपवाड़ा तक रेलवे संरेखण (ग्राफ पर आधारित गणना) 33.7 किलोमीटर तक फैला है। सर्वेक्षण से इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े मिलने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में योगदान देगा। प्रस्तावित ड्रोन सर्वेक्षण जो फाइनल लोकेशन सर्वे के काम के लिए जरूरी है, के पूरा होने के बाद प्रस्तावित रेल नेटवर्क से संबंधित अगली योजना पर काम होगा। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने रेलवे अधिकारियों को प्रदान की गई अनुमति में स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण टीम को कुपवाड़ा और कुपवाड़ा जिला प्रशासन में तैनात सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा।

पर्यटन गतिविधियां को बढ़ावा मिलेगा : कश्मीर मामलों के जानकार आसिफ कुरैशी ने कहा कि कुपवाड़ा तक रेल नेटवर्क के विस्तार से कुपवाड़ा और उससे आगे एलओसी तक पर्यटन गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। सिर्फ यही नहीं, सुरक्षाबलों को एलओसी तक पहुंचने के लिए भी आसानी होगी। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

अब नियंत्रण रेखा के आसपास से गुजरेगी ट्रेन। फाइल

सर्वेक्षण टीम के लिए यह रहेगी गाइडलाइन

- सर्वेक्षण टीम को सर्वे के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जाने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस चौकी में सूचित करना होगा।
- सर्वेक्षण टीम किसी भी तरह से यातायात व अन्य गतिविधियों में व्यवधान पैदा नहीं करेगी।
- शिक्षा संस्थानों, धर्मस्थलों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व संस्थानों की गतिविधियां सर्वेक्षण से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- एलओसी व अन्य संवेदनशील इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- ड्रोन का प्रयोग सिर्फ सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक ही किया जाएगा।
- सर्वे में सर्वोच्च न्यायालय व अन्य समर्थ प्राधिकारियों द्वारा तय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित बनाया जाएगा।

****

शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर जारी रहेगी रोक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मस्जिद मामले को अप्रैल में नियमित सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश देते हुए सर्वे पर लगी रोक जारी रखी। शीर्ष कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि वह अप्रैल में मामला सुनवाई पर आने तक इस मामले में उत्तर प्रतिउत्तर दाखिल करने का काम पूरा कर लें। ये निर्देश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिए।

सोमवार को जैसे ही मामला सुनवाई पर आया मंदिर पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुल तीन विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। दो याचिकाओं में कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित सभी मुकदमे मथुरा की जिला अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि तीसरी विशेष अनुमति याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। पीठ ने इस जानकारी पर तीनों याचिकाओं को एक साथ अप्रैल में नियमित सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि मामले में जो भी अंतरिम आदेश है, वह जारी रहेगा। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

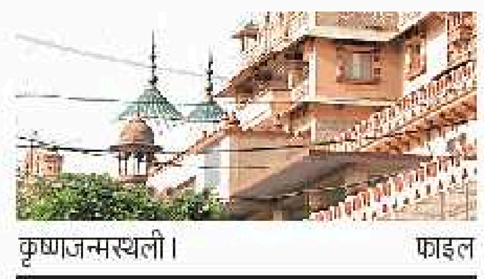

कृष्णजन्मस्थली। फाइल

पुलिस की एफआइआर के अभाव में शुरू नहीं हुई मनी लांड्रिंग की जांच

हेमंत सोरेन पर शिकंजा

नीलू रंजन, नई दिल्ली

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी लगातार समन भेज रही है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार खनन घोटाले से लेकर मनरेगा और ग्रामीण विकास में गड़बड़ियां सीधे-सीधे आदिवासी और कमजोर वर्गों को प्रभावित करती हैं। आदिवासियों की जमीन हथियाने की कई शिकायतें ईडी को मिली हैं, लेकिन पुलिस की एफआइआर नहीं दर्ज होने के कारण मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत इसकी जांच शुरू नहीं हो पा रही है। कानून के मुताबिक बिना पूर्व एफआइआर के ईडी किसी मामले में मनी लांड्रिंग की जांच शुरू नहीं कर सकती।

ईडी झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े 20 मामलों की जांच कर रहा है और इनमें उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत पूछताछ करना चाहता है। इस मामले में हेमंत सोरेन को नौ नोटिस भी भेज चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ एक बार रांची स्थित घर पर ही पूछताछ का मौका मिला है। हेमंत सोरेन से पूछताछ करने की अनिवार्यता के बारे में पूछने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घोटालों के तार सीधे मुख्यमंत्री सोरेन से जुड़े होने के सबूत हैं। इन पर मुख्यमंत्री का पक्ष जानना जरूरी है। पूछताछ होने के बाद सोरेन की सफाई का जिक्र करते हुए अपने सबूतों के साथ ईडी इन मामलों में पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जाहिर है चार्जशीट में सीधे तौर पर नाम आने की स्थिति में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शायद यही कारण है कि हेमंत सोरेन ईडी का सामना करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

2022 में आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने मनरेगा में हुए घोटाले के आरोप में ही गिरफ्तार किया था। वैसे मनरेगा घोटाला हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के पहले का है। लेकिन सोरेन ने पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें खनन सचिव बना दिया। उनके कार्यकाल में हुए खनन घोटाले की अलग से जांच हो रही है। ईडी ने सिंघल के यहां छापे में 19 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे। ईडी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर चुकी है और साथ मनी लांड्रिंग के ठोस सबूतों के आधार पर पूजा सिंघल के करीबियों की 82.77 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। मनरेगा मुख्य तौर पर गरीबों और आदिवासियों को काम की गारंटी देने के लिए है। ईडी ने झारखंड में मनरेगा में घोटाले के सुबूत मिलने का दावा किया है। झारखंड के खनन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में 23.26 करोड़ घन फीट पत्थर के अवैध खनन का आरोप लगाया है। इसकी बाजार की कीमत 1250 करोड़ रुपये से अधिक है। अवैध खनन से साहिबगंज इलाके में बड़े पैमाने पर जंगल खत्म कर दिया है। आदिवासी इलाकों में ग्रामीणों को दिए गए जंगल में पट्टे व अन्य अधिकार भी अवैध खनन की भेंट चढ़ गए। विकास योजनाओं में घोटालों की भी स्थिति यही है। ईडी को जांच में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाले के सुबूत मिले हैं।

झारखंड में आदिवासियों की जमीन हड़पने के कई मामलों में मिली हैं शिकायतें

खनन व ग्रामीण विकास योजना घोटालों से सीधे प्रभावित हैं आदिवासी और गरीब

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर पहुंचे ईडी के अधिकारी, लेकिन उन्हें हेमंत नहीं मिले। एएनआइ

व्यस्तता का हवाला दिया तो ईडी ने दिखाई सख्ती

प्रथम पृष्ठ से आगे

हेमंत ने अपने जवाब में व्यस्तता का हवाला देकर बाद में पूछताछ का समन देने की बात कही। इसके बाद ईडी ने उन्हें पत्र लिखकर उन्हें सख्त चेतावनी दी थी कि ईडी उनसे 29 या 31 जनवरी को ही पूछताछ करेगी। या तो सीएम इन्हीं दो तारीखों में पूछताछ के लिए समय दें या ईडी स्वयं समय निर्धारित कर पूछताछ के लिए पहुंच जाएगी। ईडी के बढ़ते दबाव को देखते हुए एक दिन पहले ही हेमंत अपने तमाम कार्यक्रम रद कर 27 जनवरी को इस मामले पर कानूनी परामर्श लेने के लिए रांची से दिल्ली चले गए थे। एक दिन बाद ही सोमवार को ईडी की टीम भी दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंच गई।

अवैध खनन मामले में भी हुई थी पूछताछ : हेमंत सोरेन से ईडी ने इससे पहले भी 18 नवंबर, 2022 को अवैध खनन घोटाले मामले में 10 घंटे तक पूछताछ की थी। साहिबगंज में लगभग 1250 करोड़ के इस घोटाले में हेमंत के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा तथा राज्य की खान सचिव रहीं निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर चुकी है। हेमंत के करीबियों व राज्य के कई अधिकारियों से भी पूछताछ हो चुकी है।

राज्यपाल की स्थिति पर है नजर : झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के मद्देनजर वह राज्य की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह अभी केवल अनुमान है। समय तथा परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रेट्र के अनुसार, हेमंत के परिवार के एक सदस्य ने कहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। उनके घर में न होने का मतलब यह नहीं कि वह फरार हैं।

पलामू में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को हाई कोर्ट की अनुमति

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट में पलामू में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा आयोजन की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कार्यक्रम की अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत ने कहा किसी भी धार्मिक आयोजन को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने आयोजन समिति को कई निर्देशों का पालन करने को कहा। अदालत ने कहा, सरकार चाहे तो कार्यक्रम के लिए कुछ शर्त भी लगा सकती है। अदालत ने पलामू उपायुक्त के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी।

अदालत ने कथा आयोजन समिति को श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, एंबुलेंस, पार्किंग, शौचालय आदि की व्यवस्था स्वयं करने का निर्देश दिया है। मौलिक सुविधाओं के लिए प्लान तैयार कर उपायुक्त को सौंपने और उपायुक्त को उस पर विचार करने का निर्देश भी दिया।

इस संबंध में हनुमंत कथा आयोजन समिति ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पलामू में दस से 15 फरवरी तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पलामू उपायुक्त ने कई कारणों से पूर्व में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद नए सिरे से कार्यक्रम को दस से 15 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। पुराने कार्यक्रम स्थल नदी के किनारे पर था, वहां पर उपायुक्त ने पर्यावरण असंतुलित होने की बात को लेकर कार्यक्रम रद कर दिया था।

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद से 10 घंटे पूछताछ

जांच ▶ पटना में ईडी कार्यालय के बाहर इंतजार करती रहीं मीसा, डटे रहे राजद समर्थक

60 प्रश्नों को किया था सूचीबद्ध, कुछ के जवाब दिए, कुछ पर कहा-याद नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से लगभग दस घंटे तक पूछताछ की। पटना स्थित ईडी कार्यालय में लालू से सुबह शुरू हुआ सवालों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इस दौरान उनकी पुत्री और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती ईडी कार्यालय के बाहर इंतजार करती रहीं। उनके साथ राजद के तमाम वरिष्ठ नेता और समर्थक डटे रहे। शाम ढलने के बाद राजद समर्थकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में सीआरपीएफ को तैनात करना पड़ा। ईडी ने तेजस्वी यादव को समन देकर मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि वह करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद सुबह करीब 11 बजे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर को निकले। उनके साथ पुत्री मीसा भारती भी थीं। बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर के बाहर जब लालू पहुंचे यहां पहले से ही राजद नेता-समर्थकों की भीड़ जुट चुकी थी। कई समर्थक उनकी कार के आगे लेट गए। बहुत समझा-बुझा कर उन्हें हटाया गया। ईडी कार्यालय में मीसा भारती को प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनके पिता बीमार हैं और उठने बैठने में उन्हें परेशानी होती है। समय-समय पर दवाएं भी देनी होती हैं। मीसा से दवाओं का समय लेकर ईडी अधिकारी लालू प्रसाद को लेकर अंदर चले गए। लेकिन, मीसा और राजद समर्थक दफ्तर के सामने बने दादी जी मंदिर में ही डटे रहे।

ईडी सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद से पूछताछ के लिए करीब 60 सवालों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसे बारी-बारी से उनके सामने रखा गया। कुछ सवालों के जवाब उन्होंने सहजता से दिए, जबकि कुछ जवाब यह कहकर टाल दिए कि उन्हें याद नहीं। पूछताछ का समय जैसे जैसे बढ़ रहा था ईडी कार्यालय के बाहर राजद समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई। शाम ढले सुरक्षा कारणों से सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया। इससे राजद समर्थकों के बीच लालू प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर संशय होने लगा। राजद कार्यकर्ता हो-हल्ला करने लगे। इस पर मीसा सामने आईं और कहा कि आप लोग हंगामा करेंगे तो वे और लंबे समय तक लालू प्रसाद को बिठाकर रखेंगे। इसके बाद लोग शांत हुए। ईडी की पूछताछ करीब पौने नौ बजे तक चली।

इसी मामले में मंगलवार को तेजस्वी यादव से होगी पूछताछ

जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद पटना स्थित ईडी कार्यालय में पेश हुए। एएनआइ

पटना स्थित ईडी कार्यालय में सोमवार को मौजूद राजद की सांसद मीसा भारती। प्रेट्र

रोहिणी बोलीं, पापा को खरोंच भी आई तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई

लालू की छोटी पुत्री रोहिणी ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट एक्स पर ताबड़तोड़ कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि मेरे पापा को खरोंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सबको मालूम है कि मेरे पापा की हालत क्या है, बिना मदद के चल नहीं सकते। फिर भी कितना गिरोगे। ये गुंडई के लाल लालू हैं, शेर अकेला है कमजोर नहीं। दूसरी पोस्ट में लिखा कि मेरे पापा को आज कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ सीबीआइ, ईडी व इसके मालिक होंगे।

मीसा बोलीं, नीतीश का कल भी सम्मान करते थे, आगे भी करेंगे

पत्रकारों से बातचीत में मीसा ने कहा कि नीतीश कुमार जी हमसे बड़े हैं। हम कल भी उनका सम्मान करते थे और आगे भी सम्मान करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों तोड़ा, एनडीए में क्यों गए, वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में तो वह ही बेहतर बता सकते हैं। महागठबंधन में आने का और फिर उससे हटने का निर्णय उनका ही था। हमारी ओर से कोई भी पहल नहीं की गई। इस सरकार ने बेहतर काम किए हैं। 17 महीने में जो काम किए गए वह एक नजीर है।

13 दिन के अंतराल में ईडी ने हुड्डा से दूसरी बार की पूछताछ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

हुड्डा वाले, एक इंच भी जमीन किसी बिल्डर को नहीं दी

मानेसर में 1500 करोड़ के भूमि घोटाले की हो रही जांच

गुरुग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण की अनियमितताओं की शिकायत के मद्देनजर ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 13 दिन के अंतराल में एक बार फिर पूछताछ की। हुड्डा दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में सोमवार सुबह 11.30 बजे पहुंचे और 6.15 बजे वापस लौटे। पूछताछ के बाद वह अपने आवास पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और कुछ कानूनविदों ने उनसे मुलाकात की, लेकिन मीडिया के समक्ष वह इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले।

ईडी वर्ष 2004 से 2007 के दौरान मानेसर में भूमि अधिग्रहण के मामले में हुई मनी लांड्रिंग के सिलसिले में जांच कर रहा है। ईडी ने सोमवार को हुड्डा का तीसरी बार बयान दर्ज किया। पिछली बार 17 जनवरी को उनसे पूछताछ की गई थी। हुड्डा कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार में एक इंच जमीन भी भूमि अधिग्रहण कर किसी प्राइवेट बिल्डर को नहीं दी। हुड्डा ईडी के समक्ष भी अपनी इसी बात पर कायम रहे। उन्होंने पहली बार पूछताछ के बाद कहा था कि उनका कानून को मानने में भरोसा है। ईडी जितनी बार बुलाएगी, उतनी बार जांच में शामिल होने के लिए वह जाएंगे।

यह है मामला : आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर व नखड़ौला गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली थी। किसानों का आरोप था कि उनके साथ लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। अगस्त, 2014 के इस मामले में पुलिस की एफआइआर के आधार पर ईडी ने सितंबर, 2016 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीबीआइ भी कर रही है। सीबीआइ ने हुड्डा सहित 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में 108.79 करोड़ की जमीन अटैच की जा चुकी है। 2019 में पूर्व सीएम हुड्डा स्पेशल कोर्ट में पंचकूला पेश हुए थे। यह मामला एजेएल प्लाट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाले से ही जुड़ा हुआ था। ईडी इस मामले में दूसरा पूरक चार्जशीट दायर कर चुकी है। चार्जशीट में हुड्डा के अलावा उनके मुख्यमंत्रित्व काल में प्रधान सचिव रहे एमएल तायल, छतर सिंह और नगर आयोजना विभाग के आयुक्त रहे एसएस ढिल्लों सहित पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों का नाम है।

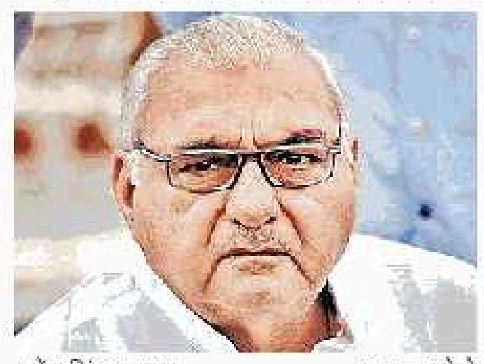

भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फाइल फोटो

महरम के बिना हज पर जाएंगी 5162 महिलाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत से इस साल 5,162 महिलाएं महरम (पुरुष रिश्तेदार) के बिना हज के लिए जाएंगी। इनमें सबसे अधिक 3584 महिलाएं केरल से हैं। भारत से महरम के बिना हज पर जाने वाली महिलाओं की यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। भारतीय हज समिति ने हज-2024 के लिए सोमवार को कम्प्यूटरीकृत लाटरी के जरिये हज यात्रियों का चयन किया। हज समिति की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि हज-2024 में 70 वर्षों और उससे अधिक आयु के 6370 और बिना महरम वाली 5162 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए। इन दोनों श्रेणियों में सभी आवेदकों का चयन बिना लाटरी किया गया।

हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लियाकत अली अफाकी ने बताया कि बिना महरम वाली महिलाओं के सर्वाधिक 3584 आवेदन केरल से प्राप्त हुए, जबकि तमिलनाडु से 378, कर्नाटक से 249, महाराष्ट्र से 166, उत्तर प्रदेश से 141, तेलंगाना से 130, जम्मू-कश्मीर से 82, मध्य प्रदेश से 72, गुजरात से 64 और दिल्ली से 50 आवेदन मिले थे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से 44, बंगाल से 40, राजस्थान से 33, बिहार से 30, असम से 29, पुडुचेरी से 19, छत्तीसगढ़ से 14, उत्तराखंड से 10, झारखंड से नौ, गोवा और ओडिशा से पांच-पांच, लद्दाख से तीन, लक्षद्वीप से दो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से एक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अफाकी ने कहा कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सर्वाधिक 1306 आवेदन महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जबकि केरल से 1250, उत्तर प्रदेश से 586, जम्मू-कश्मीर से 530, कर्नाटक से 514, तेलंगाना से 376, गुजरात से 292, हरियाणा से 274, तमिलनाडु से 214, मध्य प्रदेश से 204, राजस्थान से 190, बिहार से 136, असम से 104, दिल्ली से 80, बंगाल से 84, झारखंड से 56, उत्तराखंड से 44, आंध्र प्रदेश से 42 आवेदन मिले हैं।

70 वर्षों और उससे अधिक आयु के 6370 लोग जाएंगे हज

कम्प्यूटरीकृत लाटरी के जरिये हज यात्रियों का किया गया चयन

जीपीएस ट्रैकर लगवा ट्रेस करता था लोकेशन, फिर पार कर देता था कारें

जागरण संवाददाता, लखनऊ : 10 राज्यों से करीब 500 कारें चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सत्येंद्र सिंह शेखावत को लखनऊ पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। वह चोरी की गाड़ियां स्मैक, शराब तस्करी और हवाला का काम करने वाले माफिया लारेंस बिश्नोई समेत अन्य बड़े गिरोह को आधी कीमत में बेचता था। गाड़ी चोरी करने के लिए ट्रेन और हवाई यात्रा करके विभिन्न शहरों में पहुंचा था। वह होटलों में रुकता था। बड़ी कंपनियों के सर्विस सेंटर में जाता और गाड़ियां खरीदने के झांसे में लेकर चिह्नित गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगा देता था। साफ्टवेयर की मदद से गाड़ियों की इलेक्ट्रानिक चाबी बनाता और एक-दो दिन शहर में रुककर गाड़ी की लोकेशन पर पहुंचकर चोरी कर भाग जाता था। गिरफ्तार आरोपित सत्येंद्र सिंह शेखावत जयपुर के करजाली नांगल हनुमान नगर का रहने वाला है। वह करीब 20 साल से गाड़ियां चोरी कर रहा था। पहले सामान्य गाड़ियां चोरी करता था। फिर महंगी कारें पार करने लगा। सत्येंद्र अपनी गाड़ियां राजस्थान के गैंगस्टर भजनलाल बिश्नोई को देता था।

हिमपात से चमक उठे कश्मीर के पहाड़

जागरण टीम, नई दिल्ली

गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत घाटी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी

पहाड़ी राज्य हिमाचल व उत्तराखंड में आज वर्फबारी व वर्षा के आसार

कश्मीर में बर्फबारी ने पर्यटन क्षेत्र में खुशी ला दी है। इस खुशी को तब और ऊष्मा मिल गई, जब पसंदीदा पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में सोमवार को भी हिमपात हो गया। इन स्थानों समेत कश्मीर के अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 30 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 31 जनवरी को भारी हिमपात और वर्षा होने की संभावना जताई है। उधर, कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट से 130 उड़ानों में विलंब हुआ है।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बारामुला जिले के गुलमर्ग और बांडीपोरा के गुरेज के स्की रिसार्ट और उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग पर्यटन स्थल पर भी बर्फ गिरी है। देर शाम तक कश्मीर के मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही थी।

उधर, सैकड़ों पर्यटक गुलमर्ग और सोनमर्ग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। किश्तवाड़ के पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, जिससे अनंतनाग-किश्तवाड़ मार्ग बंद हो गया। राजौरी-पुंछ के रास्ते कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड बर्फ जमी होने के चलते पहले से ही बंद है। अलबत्ता, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी सुगमता से जारी है। मौसम विज्ञानियों ने मंगलवार और बुधवार को भी बारिश और बर्फबारी की प्रबल संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के लाहुल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिले में मंगलवार को भारी हिमपात व वर्षा हो सकती है। इससे राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। कृषि-बागवानी के साथ पेयजल योजनाओं के लिए यह संजीवनी होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मंगलवार को कहीं-कहीं वर्षा-बर्फबारी हो सकती है। बुधवार और गुरुवार को राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

कोहरे की वजह से 130 उड़ानों में विलंब : कोहरे की वजह से आइजीआइ एयरपोर्ट पर सोमवार को 130 उड़ानों में विलंब हुआ। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तुलना में घरेलू उड़ानों की संख्या तीन गुना से ज्यादा रही। रविवार को 109 घरेलू उड़ानों में विलंब रहा। इनमें से 62 ने देरी से प्रस्थान किया व 47 का देरी से एयरपोर्ट पर आगमन हुआ।

जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल गुलमर्ग समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को हिमपात हुआ। इस दौरान पर्यटकों ने बर्फ के गोले बनाकर एक-दूसरे पर फेंके और बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। एएनआइ

'अदालतें उद्योग व बार एसोसिएशन ट्रेड यूनियन नहीं'

तल्ख टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट की वकीलों की हड़ताल पर तल्ख टिप्पणी, उप्र बार काउंसिल से मांगी गाइडलाइन, पूछा-हड़तालियों पर क्या कार्रवाई हुई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलिया की रसड़ा तहसील में वकीलों की हड़ताल पर कहा कि अदालतें कोई उद्योग नहीं हैं और न ही बार काउंसिल अथवा बार एसोसिएशन ट्रेड यूनियन हैं, जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए उद्योग मालिकों से सौदेबाजी करते हैं।

यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जंग बहादुर कुशवाहा की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने कहा, 'बिना उचित कारण वकीलों की हड़ताल समाज में हाशिए पर बैठे गरीब वादकारी की जीवन स्वतंत्रता व जीविकोपार्जन को कठिनाई में डालती है। वादकारियों की मौन चीत्कार सुनकर सभ्य समाज को हल निकालना चाहिए अन्यथा न्याय के दरवाजे बंद होने पर वे कानून के दायरे से बाहर अपराधियों की मदद लेने लगेंगे। वकील तथा अदालत को संविधान प्रदत्त न्याय प्रणाली में भरोसा कायम रखने का उपाय करना चाहिए।' कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 'वकील जिसने वादकारी से केस लिया है, वह अदालत जाने से इन्कार नहीं कर सकता।' यह भी कहा कि छह जून, 2023 को कोर्ट ने बार काउंसिल को शिकायत निवारण कमेटी बनाने के निर्देश दिया था। इसमें जिला जज, अपर जिला जज, सीजेएम, डीजीसी सिविल व क्रिमिनल एवं जिला बार एसोसिएशन को शामिल करने का आदेश था, ताकि वकीलों की हड़ताल को नियंत्रित किया जा सके। कोर्ट ने उप्र बार काउंसिल के अध्यक्ष को यह जानकारी दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या हड़ताल पर नियंत्रण की कोई गाइडलाइन बनी है और हड़तालियों पर क्या कार्रवाई की गई है? प्रकरण में अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

याची ने रसड़ा तहसील बार एसोसिएशन की 31 जनवरी, 2023 से जारी हड़ताल पर कार्रवाई करने की मांग की है। कोर्ट ने बार काउंसिल से जानकारी मांगी तो 19 जनवरी, 2024 को बताया गया कि अब हड़ताल समाप्त हो गई है और अदालतें काम कर रही हैं, किंतु यह नहीं बताया कि कितने दिन हड़ताल रही? खंडपीठ ने कहा, तहसील बार एसोसिएशन के पत्र से साफ है कि किसी वकील की मौत पर न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं। याची ने इसे गलत करार देते हुए कहा कि वकील हो सकते हैं, उनके परिवार व दूर के रिश्तेदार की मौत पर, यहां तक कि सभा के जिला अध्यक्ष की मौत पर वकीलों ने हड़ताल की।

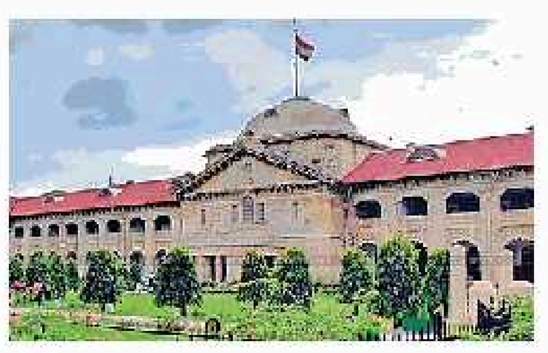

वकीलों की हड़ताल न केवल न्याय देने के समय को बर्बाद करती है अपितु इससे सामाजिक मूल्यों का ह्रास व हानि होती है और विचाराधीन मुकदमे बढ़ते हैं। साथ ही न्याय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। – इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी

मप्र में महिलाओं को अब वन विभाग में भी मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण

राज्य ब्यूरो, भोपालः मध्य प्रदेश के वन विभाग में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने संकल्प पारित किया था कि सभी शासकीय विभागों में (वन विभाग को छोड़कर) महिलाओं को सीधी भर्ती के पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने के निर्देश दिए थे। तीन अक्टूबर 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम संशोधित कर 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था में केवल वन विभाग छूट रहा था।

अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने वन विभाग में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली गई है।

पढ़ाई के तनाव के कारण एक और छात्रा ने कोटा में दी जान

जागरण संवाददाता, जयपुर

इस साल आत्महत्या का यह दूसरा मामला, सुसाइड नोट में लिखा-मम्मी-पापा सारी, आइ एम लूजर

जेईई 30 जनवरी को होने से पहले राजस्थान के कोटा में एक और छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा था। शव के पास मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा-मम्मी-पापा सारी, आइ एम लूजर, इसलिए सुसाइड कर रही हूं। यही अंतिम विकल्प है। कोटा के बोरखेड़ा निवासी विजय सिंह की 18 वर्षीय पुत्री निहारिका 12वीं कक्षा की छात्रा थी। वह जेईई की तैयारी कर रही थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पढ़ाई के तनाव के कारण उसने आत्महत्या की है। पुलिस के अनुसार छात्रा के पिता विजय सिंह बैंक में गनमैन हैं। वह सोमवार को ड्यूटी पर गए थे। छात्रा घर की दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। परिवार के अन्य सदस्य भूतल पर बने कमरों में थे। सुबह करीब 10 बजे दादी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काफी आवाज देने पर भी छात्रा ने जवाब नहीं दिया तो स्वजन ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो निहारिका दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से फंदे पर लटक रही थी। स्वजन ने बताया कि पढ़ाई में निहारिका अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई के बोझ से परेशान थी। स्वजन ने उसे आराम से रहकर पढ़ाई करने को लेकर समझाया भी था। उल्लेखनीय है कि इस साल कोटा में आत्महत्या की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी छात्र मोहम्मद जैद ने आत्महत्या की थी। कोटा में पिछले साल 26 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की थी।

28 सितंबर 2022 को आतंकी संगठनों से संलिप्तता के सबूत मिलने के बाद पीएफआइ यानी पापुलर फ्रंट आफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने पीएफआइ और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर पांच साल का बैन लगाया है।

सिमी पर प्रतिबंध पांच साल और बढ़ा

कसा शिकंजा ▶ पहली बार 2001 में अटल सरकार के कार्यकाल में लगा था सिमी पर प्रतिबंध

इसकी आतंकी व देशविरोधी गतिविधियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने लिया निर्णय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर पांच साल में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाने की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, समाज में वैमनस्यता बढ़ाने में इसकी संलिप्तता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शाह ने साफ किया कि मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति जारी रहेगी। देश में इस्लामिक शासन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 1977 में सिमी का गठन किया गया था। मुस्लिम युवाओं में कट्टरता फैलाने, आतंकी हमलों और समाज में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने में सिमी से जुड़े लोगों की संलिप्तता को देखते हुए इसे प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया। हालांकि सिमी पर प्रतिबंध के बाद इससे जुड़े कई कट्टरपंथी इंडियन मुजाहिदीन और बाद में पीपुल्स फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) में शामिल हो गए थे। वैसे गृह मंत्रालय इन दोनों संगठनों को भी प्रतिबंधित कर रखा है। 23 साल बाद भी प्रतिबंध बढ़ाने की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंध हटने की स्थिति में कट्टरपंथी लोग सिमी के बैनर तले एकजुट हो सकते हैं, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

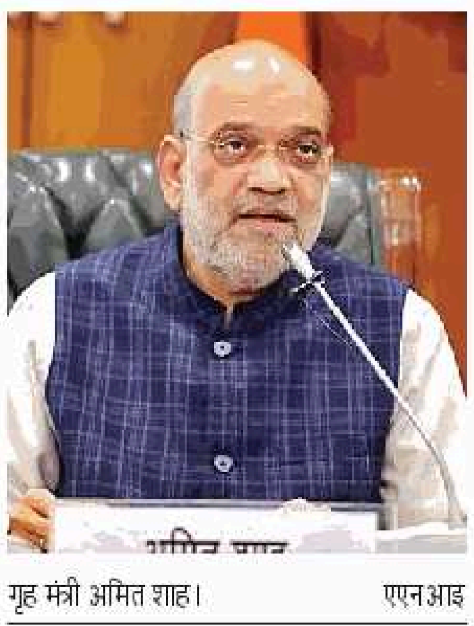
गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

बारामुला में दो आतंकियों पर लगाया पीएसए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के बारामुला में आतंकी फैयाज अहमद उर्फ नरसिम्हा और सफीर अहमद बट उर्फ सफीर मौलवी को पुलिस ने सोमवार एक बार फिर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बना लिया। दोनों को कोट भलवाल जेल जम्मू में ले जाया गया है। फैयाज के विरुद्ध जिला बारामुला में विभिन्न पुलिस थानों में 37 एफआइआर दर्ज हैं। वह पहले भी आठ बार पीएसए के तहत जेल में रह चुका है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फैयाज और सफीर दोनों कानून व्यवस्था और आम लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। फैयाज को पुलिस ने सितंबर 2020 में बारामुला में एक ग्रेनेड हमले की वारदात में संलिप्तता के आधार पर पकड़ा था। फैयाज ने अपने साथियों संग मिलकर अगस्त 2022 को बारामुला में सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंका था। इस हमले में सुरक्षाकर्मी बाल-बाल बच गए थे, लेकिन सात लोग जख्मी हुए थे। सफीर भी पुराना पत्थरबाज रह चुका है, वह बाद में लश्कर के मुखौटा संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट का आतंकी बन गया। सफीर और उसके साथियों ने ही 17 मई 2022 को बारामुला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला किया था।

बड़गाम में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर का मकान अटैच

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पुलिस ने सोमवार को लश्कर के एक ओवरग्राउंड वर्कर का जिला बड़गाम में स्थित मकान जब्त कर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जब्त किया गया मकान बड़गाम के रख्सुग में है। यह मकान मोहम्मद रमजान मीर का है। वह इस समय जेल में है। रमजान बड़गाम में सक्रिय आतंकियों के कुख्यात ओवरग्राउंड वर्करों में एक है। उसके खिलाफ आतंकियों को शरण देने और आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार व अन्य साजो सामान उपलब्ध कराने, आतंकी संगठन में स्थानीय युवाओं की भर्ती से संबंधित मामले दर्ज हैं। जिस मामले में यह मकान जब्त किया गया है, वह बीते वर्ष की शुरुआत में ही उसके खिलाफ दर्ज किया गया था। रमजान द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के आतंकी लतीफ और लश्कर कमांडर यासीन का करीबी था और दोनों उसके पास आकर अक्सर रुकते थे। इस मकान का इस्तेमाल सुरक्षाबलों पर हमले और अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग का षड्यंत्र रचने में भी हुआ है। यह मकान मोहम्मद रमजान ने आतंकी फंडिंग से आतंकियों की मदद के लिए बनवाया था।

बंगाल में मेडिकल प्रवेश में अनियमितता व जाति प्रमाणपत्र घोटाले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ एकल और खंडपीठ में लंबित मामले शीर्ष कोर्ट ने अपने यहां ट्रांसफर किए

▶ मामले की सुनवाई को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों में हुआ था विवाद

बंगाल में एमबीबीएस प्रवेश में अनियमितता और जाति प्रमाणपत्र घोटाला मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच चल रही तनातनी को देखते हुए सुनवाई अपने यहां स्थानांतरित कर ली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के समक्ष लंबित जाति प्रमाणपत्र घोटाले से जुड़े मामले अपने यहां ट्रांसफर करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। तब तक हाई कोर्ट से संबंधित फाइलें और दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे।

यह आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पांच सदस्यीय पीठ ने सोमवार को सुनवाई के बाद दिया। सोमवार को जैसे ही मामला सुनवाई पर आया, पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसके लिए औपचारिक रूप से हाई कोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित किया जाता है। बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले की सीबीआइ जांच के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि एकल पीठ के जज लगातार ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वह भविष्य में फिर ऐसा आदेश दे सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज दाखिल किया है कि वह पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने पक्षकारों को जज पर किसी भी तरह का आक्षेप लगाने से परहेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि कौन केस किसे सुनवाई के लिए आवंटित करना है, यह काम चीफ जस्टिस का है और वह ही इसे देखेंगे। यह कोर्ट उसमें कोई दखल नहीं देगा। जाति प्रमाणपत्र घोटाले की सुनवाई को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों में तनातनी हो गई थी। एकल पीठ के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने जाति प्रमाणपत्र घोटाले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था, लेकिन जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने फिर मामले पर सुनवाई की और खंडपीठ के रोक आदेश को अवैध करार देकर अनदेखा कर दिया था। साथ ही सीबीआइ को मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि अपील मेमो के बगैर खंडपीठ मामले की सुनवाई कैसे कर सकती है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के एक न्यायाधीश पर टिप्पणियां भी की थीं। एक छोटी पीठ द्वारा बड़ी पीठ के आदेश को अवैध करार देकर अनदेखी किए जाने से एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई के लिए गठित की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों की सुनवाइयों पर रोक लगा दी थी। साथ ही सीबीआइ जांच के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मामले में सीबीआइ और बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

हनुमान ध्वज को लेकर कर्नाटक में तनाव बरकरार

▶ कर्नाटक के केरागोडु गांव में 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारे जाने पर बवाल

▶ भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर किया विरोध प्रदर्शन

मांड्या, प्रेट्र : कर्नाटक के मांड्या जिले के केरागोडु गांव में 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारे जाने और पुलिस कार्रवाई को लेकर सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में रही। ध्वज उतारे जाने के खिलाफ भाजपा, जद-एस और बजरंग दल के सदस्यों के साथ-साथ गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ध्वज उतारे जाने के विरोध में भगवा झंडे लेकर मांड्या शहर के जिला मुख्यालय में उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को काबू करने के लिए रविवार को लाठीचार्ज करना पड़ा था। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने हनुमान ध्वज की जगह राष्ट्रध्वज लगा दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने ध्वज स्तंभ के चारों ओर अवरोधक भी लगाए हैं और क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने बताया, प्रदर्शनकारियों और ग्रामीणों ने स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया था, जिसके कारण गांव में अधिकतर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं। भाजपा नेता और कार्यकर्ता सोमवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी नीति की निंदा की। कांग्रेस पर राष्ट्रध्वज का अपमान करने का आरोप भी लगाया। बेंगलुरु में, भाजपा ने जयनगर से विधायक सी के राममूर्ति के नेतृत्व में मैसूर बैंक सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस ने कहा, स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

कर्नाटक के मांड्या जिले में सोमवार को हनुमान ध्वज उतारने जाने के बाद प्रदर्शन करते लोग। प्रेट्र

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने सोमवार को भाजपा और जद-एस पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मांड्या जिले के केरागोडु गांव में सरकारी अधिकारियों द्वारा 108 फुट ऊंचे ध्वजस्तंभ पर फहराए गए भगवा ध्वज को हटाने के मुद्दे पर लोगों को भड़का रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा कि अनुमति केवल राष्ट्रीय और कन्नड़ ध्वज फहराने के लिए ली गई थी। उन्होंने खुद को हिंदू विरोधी कहने के भाजपा के आरोप पर भी पलटवार किया और कहा कि वह एक हिंदू हैं, जो सभी धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं। वहीं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि प्रदर्शनकारी राजनीति करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लें। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने कहा कि अगर भाजपा को राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और देश की अखंडता पसंद नहीं है, तो उनके नेता पाकिस्तान जा सकते हैं।

आइएस के अम्मार की जमानत याचिका पर एनआइए को नोटिस

जासं, नई दिल्ली : आइएस आपरेटिव अम्मार अब्दुल रहिमन की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआइए से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने एनआइए को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।

आइएस आपरेटिव अम्मार ने वर्ष 2021 के मामले में जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी है। उसके अधिवक्ता अर्चित कृष्णा ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यूएपीए की धारा 38 और 39 के साथ धारा 2 (ओ) और 13 के तहत आरोप तय किए गए हैं। वह दो साल से अधिक समय से हिरासत में है। एनआइए ने मामले में आठ सितंबर, 2022 को मोहम्मद अमीन कथोडी उर्फ अबू याह्या, मुशाब अनवर उर्फ इब्नानवर और रहीस रशीद उर्फ सनू के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। बाद में एजेंसी ने आठ आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दायर किया।

गुजरात के लोगों पर टिप्पणी मामले में उपयुक्त बयान दाखिल करें तेजस्वी

▶ सुप्रीम कोर्ट ने नया बयान दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का दिया समय

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को अपनी उस टिप्पणी को वापस लेते हुए उपयुक्त बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी के पहले के हलफनामे को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति जताये जाने के बाद एक नया बयान दाखिल करने के लिए राजद नेता को एक सप्ताह का समय दिया।

पीठ ने अगली सुनवाई पांच फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि हम याचिकाकर्ता को एक उपयुक्त बयान दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देते हैं। तेजस्वी ने अपनी टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को एक हलफनामा दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट तेजस्वी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ अहमदाबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत को राज्य के बाहर स्थानांतरण का अनुरोध किया था। उसने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए इससे पहले आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले गुजरात के निवासी को नोटिस जारी किया था। आपराधिक मानहानि को लेकर तेजस्वी के खिलाफ आइपीसी की धारा- 499 और 500 के तहत शिकायत दायर की गई थी। गुजरात की अदालत ने अगस्त में आइपीसी की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था।

शिकायत के अनुसार, तेजस्वी ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी। यदि वे एलआइसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा।

अजमेर में छात्र से मारपीट कर पेशाब पिलाया

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में अजमेर के आनासागर चौपाटी पर 10वीं कक्षा के एक छात्र की कुछ लोगों ने डंडों से पिटाई कर दी। करीब एक दर्जन लोगों ने उसे मुर्गा बनाकर पेशाब भी पिलाया। छात्र ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वालों ने उस पर शराब भी गिराई। पीड़ित छात्र और उसके स्वजन ने सोमवार को इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महमूद खान से मुलाकात कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। खान ने क्रिश्चियन गंज पुलिस थाने को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

अजमेर के भोपो का बाड़ा निवासी 18 साल का छात्र 26 जनवरी को आनासागर चौपाटी पर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इस दौरान रोहित, पुष्पेंद्र व गोकुल सहित करीब एक दर्जन लोग वहां पहुंचे और उन्होंने डंडों से उसकी पिटाई कर दी। पेशाब भी पिलाया। मारपीट करने वालों ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो भी बनाया। छात्र का आरोप है कि उसके बाल भी काटे। जातिसूचक शब्दों से गाली भी दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र और उससे मारपीट करने वालों के परिवारों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा है।

छत्तीसगढ़ में कोयला के बाद डीएमएफ व चावल घोटाला

नईदुनिया, रायपुर

▶ ईडी के आवेदन पर एसीबी ने आइएएस रानू सहित 10 पर दर्ज किया केस

छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के समय हुए घोटालों की जांच में तेजी आई है। ईडी के आवेदन पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने चावल और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) घोटाले में दो नई एफआइआर दर्ज की हैं। ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी की इकोनामिक आफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने दोनों मामलों में आइएएस रानू साहू समेत कई आइएएस-आइपीएस का नाम दर्ज किया है। एफआइआर में खनिज अधिकारियों, ठेकेदारों और कई कंपनियों के मालिकों के नाम शामिल हैं। बता दें, राज्य में कोयला घोटाले में जांच जारी है।

एफआइआर के अनुसार, चावल घोटाले में 175 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। डीएमएफ में 1200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। इसके पूर्व कोयला और शराब घोटाले में कांग्रेस नेताओं, सरकारी अधिकारियों समेत 106 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। ईडी डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद आइएएस रानू साहू से लंबी पूछताछ कर चुका है। आरोप है कि साहू ने कोरबा कलेक्टर रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में हेराफेरी की है। उनके पहले और बाद जो भी कोरबा, रायगढ़ कलेक्टर बना, सभी जांच के घेरे में हैं। इसमें कुछ वर्तमान और पूर्व विधायक, सेवानिवृत्त आइएएस समेत 54 से ज्यादा लोगों को आरोपित बनाया गया है। माना जा रहा है कि जांच की आंच भूपेश बघेल तक पहुंच सकती है। इसके पहले महादेव सट्टेबाजी एप मामले में भी बघेल का नाम जुड़ा था।

ईडी की ओर से एसीबी को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न राइस मिलर्स द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम एवं एफसीआइ में कस्टम मिलिंग के लिए जमा किए जाने वाले चावल पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। पद का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न शासकीय अधिकारियों द्वारा राइस मिलर्स से मिलीभगत कर लाभ प्राप्त कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।

पुलिस की चिंता न करें, फडणवीस हैं न : राणे

पुणे, प्रेट्र : भाजपा विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू जनाक्रोश सभा से कहा कि वह उनकी आक्रामकता का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। वे पुलिस की चिंता न करें। उनके बास सागर बंगला में बैठे हैं। सागर बंगला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का सरकारी आवास है। राणे ने कहा कि वह हिंदू समुदाय के साथ खड़े हैं। उन्हें पुलिस कार्रवाई से डरे बिना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यहां किसी के काम में दखल देने नहीं आया हूं। मैं सभी जिहादियों से कहना चाहता हूं कि आप जहां हैं वहीं रहें। हमसे न भिड़ें, क्योंकि हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है कि आपको कैसे मिटाना है। राणे ने कहा, यदि कोई पुलिसकर्मी केवल इसलिए आपको परेशान करता है, क्योंकि आप हिंदू हैं तो उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दीजिए। आपको आश्वासन दे रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, सरकार आपके साथ है। राणे ने फडणवीस का जिक्र करते हुए कहा कि मैं आपको पुलिस के सामने यह विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी मुझसे नहीं भिड़ सकता, क्योंकि हमारा बास सागर बंगले में बैठा है।

बुलेट ट्रेन कारिडोर के लिए लगाए जाएंगे 28 भूकंपरोधी संयंत्र

▶ संयंत्र भूकंप प्रेरित झटकों का पता लगाएंगे और स्वचालित बिजली बंद करने में सक्षम होंगे

▶ बिजली बंद होने से बुलेट ट्रेन में आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाएंगे और ट्रेनें रुक जाएंगी

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कारिडोर के लिए 28 भूकंपरोधी संयंत्र लगाए जाएंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन (एनएचएसआरसीएल) ने सोमवार को कहा कि यात्रियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जापानी शिंकानसेन तकनीक पर आधारित भूकंप जांच प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 28 भूकंपमापी सिस्मोमीटर में से 22 को रेल पटरी के समानांतर स्थापित किया जाएगा। इनमें से आठ महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, विरार और बोइसर में होंगे, जबकि 14 गुजरात के वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद महेम्बादाद और अहमदाबाद में होंगे। शेष छह भूकंपमापी जमीन के अंदर स्थापित किया जाएगा। इन्हें महाराष्ट्र के खेड़, रत्नागिरी, लातूर और पंगरी जैसे भूकंप-प्रवण क्षेत्रों के साथ-साथ गुजरात के अडेसर और पुराने भुज में लगाया जाएगा। ये भूकंपमापी प्राथमिक तरंगों के माध्यम से भूकंप प्रेरित झटकों का पता लगाएंगे और स्वचालित बिजली बंद करने में सक्षम होंगे। एनएचएसआरसीएल ने बताया कि बिजली बंद होने से बुलेट ट्रेन में आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाएंगे और प्रभावित क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनें रुक जाएंगी।

जापानी विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि हाई स्पीड कारिडोर वाले क्षेत्रों में पिछले 100 वर्षों में 5.5 से अधिक तीव्रता के भूकंप आए हैं। सिस्मोमीटर लगाने के लिए स्थल का चयन विस्तृत सर्वेक्षण और मिट्टी की उपयुक्तता अध्ययन के बाद किया गया।

बुलेट ट्रेन कारिडोर निर्माण कार्य है जारी। फाइल

चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने नायडू को राहत देने वाले हाई कोर्ट के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा, अन्य आरोपितों से संबंधी उसी प्राथमिकी से उत्पन्न मामले में एक अपील को अदालत ने पिछले साल पहले ही खारिज कर दिया था। इसमें कहा गया कि इस कोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। इनर रिंग रोड घोटाला मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की पेशकश के लिए राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान में घालमेल और हेरफेर करने से संबंधित है।

अग्रणी पहल

मछली से विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके प्रयोगशाला में विकसित होगा मांस, इस परियोजना का लक्ष्य इस क्षेत्र में विकास को गति देना है

भारत में प्रयोगशाला में विकसित होगा मछली का मांस

▶ सीएमएफआरआइ ने की पहल, स्टार्टअप नीट मीट बायोटेक के साथ किया सहयोगात्मक अनुसंधान समझौता

कोच्चि, प्रेट्र : भारत में पहली बार मछली का मांस प्रयोगशाला में विकसित किया जाएगा। आइसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआइ) ने इसके लिए अग्रणी पहल की है। इस परियोजना का लक्ष्य सीफूड (समुद्र से मिलने वाला खाद्य पदार्थ) की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ भारत को समुद्री मछली के मांस के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

प्रयोगशाला में विकसित मछली का मांस मछली से विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके और उन्हें प्रयोगशाला में विकसित करके बनाया जाता है। प्रारंभिक चरण में किंग फिश, सीयर फिश जैसी महंगी समुद्री मछलियों के मांस प्रयोगशाला में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

सीएमएफआरआइ ने इस पहल को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में शुरू करने के लिए नीट मीट बायोटेक के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान समझौता किया है। नीट मीट बायोटेक इस क्षेत्र में काम करने वाला स्टार्टअप है। सीएमएफआरआइ के निदेशक डा. ए. गोपालकृष्णन और नीट मीट बायोटेक के सह-संस्थापक और सीईओ डा. संदीप शर्मा ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार सीएमएफआरआइ महंगी समुद्री मछली प्रजातियों के प्रारंभिक कोशिका विकास पर अनुसंधान करेगा। इसमें अनुसंधान और विकास के लिए मछली की कोशिकाओं को अलग करना और विकसित करना शामिल है। परियोजना से संबंधित जैव रासायनिक और विश्लेषण की जिम्मेदारी भी सीएमएफआरआइ की होगी। संस्थान में बुनियादी सुविधाओं के साथ सेल कल्चर प्रयोगशाला की सुविधा है। सेल कल्चर तकनीक में अपनी विशेषज्ञता के साथ नीट मीट बायोटेक बायोरियक्टर्स के जरिये उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा।

सीएमएफआरआई के निदेशक डा. ए. गोपालकृष्णन ने कहा कि इस परियोजना का लक्ष्य इस क्षेत्र में विकास को गति देना है, यह सुनिश्चित करना है कि भारत इस उभरते उद्योग में पीछे न रह जाए। बता दें कि मत्स्य अनुसंधान को लेकर केंद्र सरकार लगातार संस्थानों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार की प्राथमिकता मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही व्यवसाय को संगठित करने का प्रयास भी है।

प्रतीकात्मक

****

गुजरात के वडोदरा नाव दुर्घटना मामले में हाई कोर्ट ने मांगी कार्यवाही रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात के वडोदरा झील में नाव पलटने से 12 स्कूली बच्चों और दो शिक्षकों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने महानगरपालिका को खरी-खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अब तक कार्यवाही रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की गई, क्या महानगरपालिका प्रशासन राजनीति से जुड़े लोगों को बचाना चाहता है। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने 18 जनवरी को वडोदरा की झील में नाव पलटने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरुरू की है। कोर्ट ने घटना को लेकर महानगरपालिका की ओर से कार्यवाही रिपोर्ट पेश न करने पर कहा कि आप केवल जवाब नहीं, इस मामले में तथ्य पेश करें। क्या आप राजनीति से जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर, राज्य सरकार ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किये गये। इस मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

एक महीने तक बंद रहने के बाद रेलवे प्लेटफार्मों पर जनता खाना फिर शुरू

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

▶ 27 दिसंबर से बंद थी व्यवस्था, छह माह के लिए फिर से लागू

▶ 20 रुपये में पूड़ी-सब्जी और तीन रुपये में मिलेगा पानी का गिलास

रेलवे ने यात्रियों के लिए जनता खाने की व्यवस्था फिर शुरू की है। 27 दिसंबर को अवधि पूरी होने पर इस सुविधा को बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने अब छह माह की अवधि के लिए इसे फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। इस व्यवस्था के तहत 20 रुपये में सात पूड़ी और सब्जी मिलती है। तीन रुपये में पानी का गिलास (200 मिली लीटर) और 50 रुपये में 350 ग्राम चावल व 250 ग्राम राजमा या छोले भी मिलेंगे।

10 साल पहले इस सुविधा को शुरू किया गया था : जनता खाने में वेंडर को छूट है कि वह जनरल बोगी के सामने ठेला लाकर बिक्री कर सकता है। जिन रेलवे स्टेशन पर भोजनालय है, वहां इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। रेलवे में आम यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए करीब 10 साल पहले इस सुविधा को शुरू किया गया था। इसके पीछे मकसद था कि जनरल बोगी में आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों को भी कम दाम में खाना उपलब्ध हो जाए। हालांकि कुछ साल बाद इसे बंद कर दिया गया। जून, 2023 में इसे छह माह के लिए फिर शुरू किया गया था। अवधि पूरी होने पर सुविधा बंद कर दी गई थी। इस वर्ष 22 जनवरी को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (टीएंडसी) सुमित सिंह ने आदेश जारी कर इसे छह माह के लिए फिर शुरू किया है। इस बारे में सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि जिस स्टेशन पर भोजनालय है, वहां इसकी बिक्री कराने का आदेश दिया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 30 जनवरी, 2024

दैनिक जागरण

गलतियों को चिह्नित किए बिना सुधार असंभव है

कांग्रेस की राजनीतिक जमीन

अब इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार के आइएनडीआइए से अलग होने के बाद इस गठबंधन के साथ-साथ कांग्रेस की भी कठिनाई बढ़ने जा रही है। अपनी इस कठिनाई के लिए वही अधिक जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जिन कारणों से आइएनडीआइए से अलग हुए, उनमें एक बड़ा कारण उन्हें इस गठबंधन का संयोजक न बनाया जाना रहा। नीतीश कुमार आइएनडीआइए के संयोजक बनने के अधिकारी इसलिए थे, क्योंकि उन्होंने ही कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की थी। कांग्रेस ने केवल नीतीश कुमार की ही अनदेखी नहीं की, बल्कि उसने आइएनडीआइए के अन्य घटकों को एकजुट करने और सीटों के बंटवारे को महत्व देने के स्थान पर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने को प्राथमिकता प्रदान की। इस यात्रा का उपयोग आइएनडीआइए की एकजुटता को मजबूत करने में किया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता कि कांग्रेस ने ऐसा करना आवश्यक क्यों नहीं समझा? उसने घटक दलों को इस यात्रा में सम्मिलित होने का औपचारिक निमंत्रण देकर कर्तव्य की इतिश्री ही अधिक की और इसी कारण ममता बनर्जी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि वह लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा अवश्य कर दी, लेकिन यह घोषणा उन्होंने कांग्रेस से व्यापक विचार-विमर्श के बजाय अपने स्तर पर ही की। कांग्रेस का इससे संतुष्ट न होना स्वाभाविक है।

यदि नीतीश कुमार आइएनडीआइए में बने रहते तो कांग्रेस को केवल बिहार में ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि उत्तर भारत में भी उसके पक्ष में मनोवैज्ञानिक माहौल बनता, जहां वह बहुत अधिक कमजोर है। अब ऐसा होने के आसार कम हैं। इसका एक कारण कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना भी है। पता नहीं, कांग्रेस के रणनीतिकार यह साधारण सी बात क्यों नहीं समझ सके कि सांस्कृतिक महत्व के इतने महत्वपूर्ण आयोजन में न जाना और उसके निमंत्रण को ठुकराना एक ही बात नहीं। आइएनडीआइए में भले ही दो दर्जन से अधिक राजनीतिक दल शामिल हों, लेकिन संप्रग के बाहर का कोई बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा नहीं दिख रहा है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह पंजाब में अपने दम पर लड़ेगी। पता नहीं दिल्ली में क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस आइएनडीआइए को सशक्त नहीं कर सकी। हैरानी नहीं कि अब आइएनडीआइए की राजनीतिक हैसियत संप्रग सरीखी ही नजर आए। कांग्रेस यह मानकर चल सकती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है, लेकिन सच यह है कि उसकी राजनीतिक जमीन मजबूत होती नहीं दिख रही है।

रुके मानव तस्करी

झारखंड में मानव तस्करी बड़ी समस्या रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से व्यापक पैमाने पर बच्चों और महिलाओं को काम कराने के लिए महानगरों में ले जाया जाता रहा है। कई बार इनकी खरीद-बिक्री भी होती है और तरह-तरह से इनका शोषण किया जाता है। किशोरियां, युवतियां और महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती हैं। बच्चे-बच्चियों और किशोर-किशोरियों का भविष्य तस्करों, दलालों, ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो जाता है। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बहला-फुसलाकर ले जाए जाने के बाद इनके लिए घर लौटना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं घर वालों से भी संपर्क टूट जाता है और इन्हें काम को उचित मजदूरी भी नहीं मिलती।

> झारखंड के लिए मानव तस्करी किसी अभिशाप से कम नहीं। इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे

गुहार लगाए जाने पर या मदद के लिए किसी के आगे आने पर इन्हें मुक्त कराया जाता है। झारखंड में कुछ बड़े मानव तस्कर अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मानव तस्करी का खेल रोके नहीं रुक रहा है। इसे रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। वहीं तस्करी रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को भी अपना तंत्र मजबूत करना होगा। रविवार को नई दिल्ली में 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। इसके पीछे राज्य सरकार का सार्थक प्रयास भी रहा है। बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों से मुक्त कराकर पुनर्वास केंद्रों में अथवा उनके ही घरों में पुनर्वासित कराया जा रहा है। बावजूद इसके मानव तस्करों की गतिविधियां जारी हैं और उन्हें रोकने के प्रयास विफल हो रहे हैं। इस स्थिति को बदलना होगा, क्योंकि यह किसी कलंक और दुर्भाग्य से कम नहीं।

संभव हैं एक साथ चुनाव

डा. एके वर्मा

देश में एक साथ चुनाव दुष्कर अवश्य हैं, लेकिन असंभव नहीं। इस मामले में जर्मनी जैसे कुछ देशों की व्यवस्था का अनुसरण उपयोगी हो सकता है

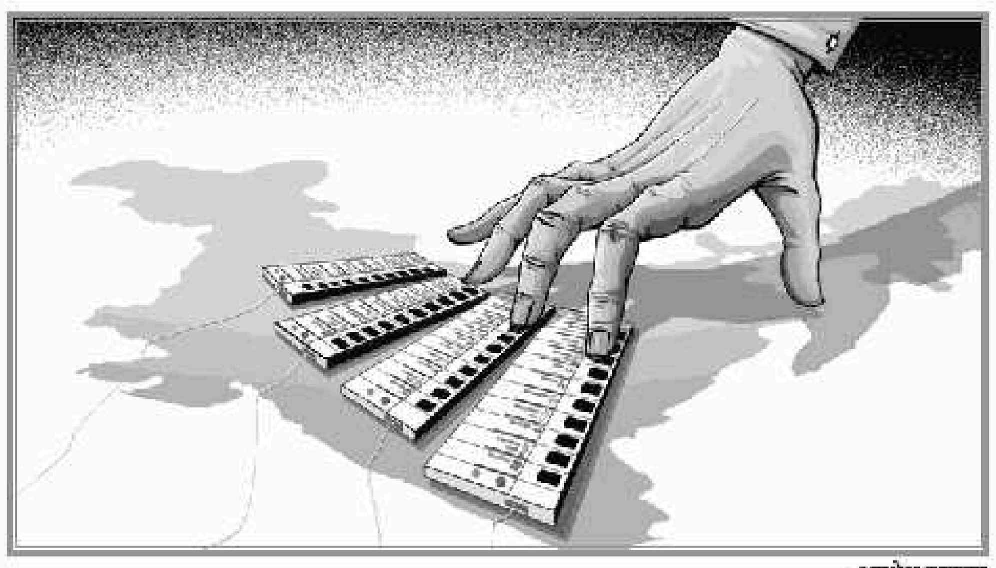

अवधेश राजपूत

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में 'एक देश-एक चुनाव' पर गठित समिति ने देश में सभी पक्षों और जनता से 15 जनवरी तक सुझाव मांगे थे। समिति इन सुझावों पर विचार करने के साथ विभिन्न विशेषज्ञों से मंत्रणा कर रही है। सर्वप्रथम 1983 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने का सुझाव दिया था। फिर 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग ने चुनाव कानून सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में इसकी संस्तुति की। 2017 में पूर्व-राष्ट्रपतियों प्रणब मुखर्जी और कोविन्द ने भी इसका समर्थन किया। 26 नवंबर, 2017 को नीति आयोग और विधि आयोग द्वारा आयोजित संविधान दिवस पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में इस पर राष्ट्रीय विमर्श का आह्वान किया। तब विधि आयोग ने 2018 में इस पर विचार-विमर्श किया और रिपोर्ट सौंपी।

स्वतंत्रता के बाद चार बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, मगर 1967 में आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनने और दलबदल की समस्या से अस्थिरता आने के कारण यह क्रम टूट गया। आज चुनाव आयोग को प्रतिवर्ष चार-पांच राज्यों में चुनाव कराने पड़ते हैं, जिसमें अपने दल के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों को लगना पड़ता है। इससे शासन-प्रशासन प्रभावित होता है। आदर्श आचार-संहिता से विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। अत्यधिक धन खर्च होता है। पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे कई देशों में एक-साथ चुनाव होते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद के विपरीत नहीं। इंग्लैंड में भी 2011 में संसद ने 'निश्चित कार्यकाल अधिनियम' पारित किया जिसके अनुसार मध्यावधि चुनाव तभी होंगे जब संसद दो तिहाई बहुमत से इसकी संस्तुति करे। इंग्लैंड में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तब भी प्रधानमंत्री संसद को तुरंत भंग नहीं करा सकता। संसद के पास विकल्प होता है कि वह 14 दिनों के भीतर वैकल्पिक सरकार गठित कर सके।

जहां तक एक साथ चुनाव की बात है तो इस राह में भारत में दो प्रमुख संवैधानिक अवरोध दिखते हैं। पहला यह कि भिन्न-भिन्न समयावधि वाली विधानसभाओं और लोकसभा को एक साथ चुनाव के लिए कैसे साथ लाया जाए? चुनावों को एक साथ कराने का मुद्दा टेढ़ा है। इसमें कानूनी और संवैधानिक तरीकों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों में आम सहमति की जरूरत भी होगी। संभव है कि कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़े और कुछ सरकारों को समय से पूर्व त्यागपत्र दिलाना पड़े। यह उतना आसान नहीं होगा। दूसरा अवरोध यह है कि एक साथ चुनाव हों भी तो कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यह क्रम बना रहे। एक बार निर्वाचित होने पर अनेक कारणों से लोकसभा या विधानसभाओं को भंग होना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पांच वर्ष के पहले ही त्यागपत्र दे दे। सरकार अविश्वास के प्रस्ताव पर पराजित हो जाए और लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सलाह दे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपातकाल लागू होने पर सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी जाए। सरकार का बजट प्रस्ताव गिर जाए और वह त्यागपत्र देकर नए चुनाव की सलाह दे या चुनावों के बाद कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में न हो और पुनः मध्यावधि चुनाव करना पड़े आदि-इत्यादि। स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में लोकसभा या विधानसभाएं भंग होती हैं, जिससे चुनावों का क्रम बिगड़ता है। ऐसे में सरल उपाय यह है कि संविधान से लोकसभा और विधानसभाओं के भंग होने का प्रविधान ही समाप्त कर दिया जाए और उसे निलंबित रखने का प्रविधान किया जाए। इससे चुनावों का पंचवर्षीय क्रम नहीं बिगड़ेगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं बंटेगा। पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी तथा जनता और चुनाव-आयोग को बार-बार चुनावों से छुटकारा मिलेगा।

सरकारों के गिरने से उत्पन्न अस्थिरता से निपटने के लिए जर्मनी के संविधान का अनुसरण किया जा सकता है। जर्मन संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार विपक्ष अपने प्रधानमंत्री (चांसलर) के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तभी ला सकता है, जबकि वह पहले उसका उत्तराधिकारी चुने, जिससे सरकार गिरने की स्थिति में देश को तत्काल एक नई सरकार मिल सके। हालांकि यदि चांसलर स्वयं विश्वास प्रस्ताव लाए (जैसे बजट पर) और हार जाए तो अनुच्छेद 68 के अनुसार वह सदन को तत्काल भंग नहीं करा सकता। सदन को 21 दिन का समय मिलता है कि वह कोई नया चांसलर चुन सके। इसे कुछ संशोधनों के साथ हम स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बिना चुनाव कराए सरकारों में परिवर्तन हो सके। फिर भी, दोबारा 1967 जैसी स्थिति न उत्पन्न हो और चुनावों का पंचवर्षीय क्रम बना रहे, इसके लिए संविधान के अनेक प्रविधानों जैसे अनुच्छेद 75(3), 83, 85(1), 113, 164(2), 172, 174(1), 203, 243(यू), संविधान के भाग 15 (चुनाव संबंधी), 10वीं अनुसूची, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950-51 एवं लोकसभा की कार्यप्रणाली संबंधी नियम 198 आदि में संशोधन करना पड़ेगा। इनमें कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी।

यह कार्य दुष्कर अवश्य है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। इस मुद्दे पर वर्तमान सांसद और विधायक एकमत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका भी व्यापक लाभ निहित है। एक बार निर्वाचित होने पर उनका पांच वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित हो जाएगा और वे भी रोज-रोज के चुनावी झंझट से बचेंगे। फिर चुनाव बहुत खर्चीले भी हो गए हैं और सभी जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि किसी तरह उनको पांच वर्ष के पूर्व चुनाव में न उतरना पड़े। यदि मोदी सरकार सभी सांसदों और सभी राज्यों के विधायकों को इसे समझा सकी तो उपरोक्त सभी संशोधनों पर दलीय सहमति प्राप्त की जा सकेगी।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

साकार हो गांधी के रामराज्य का सपना

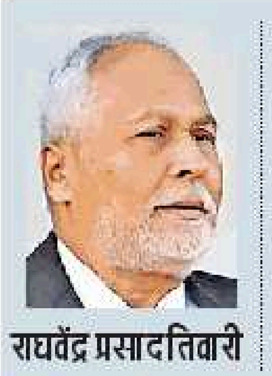

राघवेंद्र प्रसाद तिवारी

गांधी जी रामराज्य की बात इसीलिए करते थे, क्योंकि उनके लिए राम मानव जीवन के उच्चतम आदर्श थे

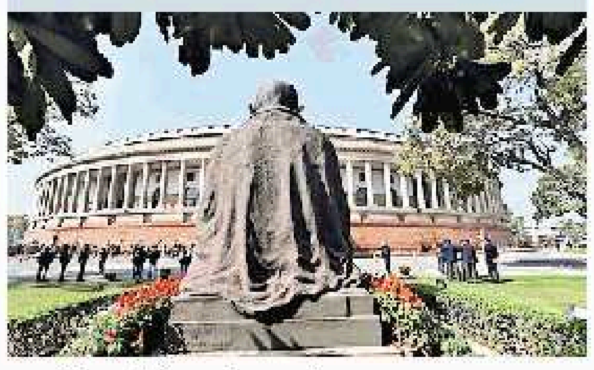

राजनीति का केंद्रीय व्यक्तित्व बनें राम। फाइल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके महनीय कार्यों को स्मरण करते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह पिछली सदी के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं में से एक थे। जब मानवता गृहयुद्ध, उपनिवेशवाद, बर्बरता एवं विश्वयुद्धों से त्रस्त थी, तब गांधी जी ने शांति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, नैतिकता, शुचिता एवं करुणा की ज्योति प्रज्वलित की। प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व के कारण उन्होंने इन मूल्यों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में रोपित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि सत्य एवं अहिंसा के सहारे बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। प्रश्न है कि गांधी जी को सत्य एवं अहिंसा की प्रेरणा कहां से मिली? वास्तव में गांधी के प्रेरणास्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम थे। डा. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि राम का चरित्र कुछ ऐसा है कि उनके पीछे चलने को जी चाहता है, किंतु अब यह कहने का मानो फैशन ही चल पड़ा है कि राम का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। जब कभी यह कहा जाता है कि इस या उस मामले में राजनीति न की जाए या फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब उसका मतलब होता है कि संकीर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। संकीर्ण राजनीति को राजनीति का पर्याय बना देना ठीक नहीं। यदि राजनीति का उद्देश्य समाज को दिशा देना और उसका कल्याण करना है तो फिर हर क्षेत्र में उसका समावेश क्यों नहीं होना चाहिए? वास्तव में राम ही देश की राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व होने चाहिए। आदर्श जीवन, राज्य एवं प्रजा-राजा का संबंध कैसा हो, इसके सूत्र रामकथा में मिलते हैं। गांधी रामराज्य की बात इसीलिए करते थे, क्योंकि उनके लिए राम मानव जीवन के उच्चतम आदर्श थे।

गोस्वामी तुलसीदास राम नाम को 'घर' मानते थे। अनुलोम-विलोम की तरह ही 'राम' शब्द का जाप नाड़ी शोधन करता है और दोनों नाड़ियों में प्रवाहित ऊर्जा में तारतम्य बैठाता है। अर्थात 'राम' नाम के उच्चारण से न केवल आध्यात्मिक, अपितु भौतिक उन्नति भी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार राम नाम तारक है तो उनकी राजव्यवस्था प्रजा हितकारी। ऐसे में राम से जुड़कर विश्वास प्रबल होता है कि जीवन मंगलकारी होगा। इसीलिए गांधी ने राम के आदर्शों को आंदोलनों में समाहित कर स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित किया। स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए स्वतंत्रता के सपने का अर्थ है रामराज्य की स्थापना यानी आदर्श राज्य का तत्व रामराज्य है। राम ने जैसा राज किया, वैसा ही उन्हें संपूर्ण मानवता के लिए अभिप्रेत था। जनमानस के बीच हजारों साल से चली आ रही रामकथा में आखिर ऐसा क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन का महानायक उसका सहारा लेता है? एक आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक चिंतक को पौराणिक-आध्यात्मिक चरित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी?

देखा जाए तो गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों की विशिष्टता एक पौराणिक आख्यान को स्वाधीनता आंदोलन एवं मानव जीवन से जोड़ देने में थी। परतंत्रता के दौर में देश अंग्रेजों की मानव विरोधी नीतियों और अमानुषिक कृत्यों से पीड़ित था। नमक कानून, रालेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नील की खेती आदि ऐसे कुकृत्य थे जिनसे जनसामान्य में रोष था। वह विकल्प की तलाश में थे और उन्हें यह विकल्प रामराज्य में दिखा था। तुलसीदास द्वारा वर्णित रामराज्य के स्वीकृत मूल्यों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर गांधी जी ने अध्यात्म एवं सामाजिकता की युति बनाने का अभूतपूर्व प्रयत्न किया। गांधी ने यंग इंडिया में लिखा, 'मैं जितने धर्मों को जानता हूं, उनमें हिंदू धर्म सर्वाधिक सहिष्णु है। मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। यह न केवल मनुष्य, बल्कि प्राणिमात्र की एकता एवं पवित्रता में विश्वास रखता है।' गांधी के अनुसार, 'रामराज्य अर्थात जहां अंत्योदय की प्रकृति राज करती हो। रामराज्य ही वास्तविक लोकतंत्र है। न्याय व्यवस्था में राजा और रंक का भेद नहीं होता।' राम ने प्रजा को निर्भय करते हुए कहा था, 'यदि राजा होते हुए भी मैं कुछ अनीति करूं तो निर्भय होकर आलोचना करें।' जब गांधी जी राजनीतिक-सामाजिक जीवन में शुचिता की बात करते हैं, तब स्पष्ट ही राम द्वारा की गई यह घोषणा उनके स्मरण में रही होगी, 'निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।।' यानी राम को छल कपट नहीं भाता। निर्मल मन से जो पास आता है, राम उसे अपना लेते हैं। गांधी को इसीलिए बुराई से नफरत थी और मनुष्य के भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने में वह विश्वास रखते थे।

यद्यपि हमारा देश उपनिवेशवादी शक्तियों से स्वतंत्र हो गया, किंतु अनेक चुनौतियां रूप बदलकर हमारे समक्ष विद्यमान हैं। पश्चिमी अपसंस्कृति का प्रसार बढ़ रहा है। आतंकवाद एवं मजहबी उन्माद भी नए-नए रूप धारण कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या देश में जातिगत विद्वेष की भी है। स्मरण रहे कि लगभग 500 वर्षों बाद गांधी सहित हम सब के आराध्य प्रभु राम का अपनी अयोध्या में लौटना कोई सामान्य घटना नहीं है। विचारणीय है कि यदि हम स्वतंत्रता की कठिन लड़ाई जीत सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि राम के आदर्शों को जीवन में अंगीकार कर गांधी के सपनों के रामराज्य की स्थापना के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित न कर सकें। आज ज्ञान-विज्ञान से युक्त, युवा-ऊर्जा से ओतप्रोत, कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छाशक्ति से संपन्न हम सभी के समक्ष यह अवसर है कि नवीन राहों का अन्वेषण करते हुए वे अपने पुरखों के सपनों का स्वर्णिम भारत बनाएं एवं समूची धरा को राममय कर दें।

(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परिवर्तन की शुरुआत

परिवर्तन की शुरुआत सर्वप्रथम स्वयं से होनी चाहिए। अगर आप दूसरे को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम खुद को बदलने के लिए तैयार कीजिए। हमें देखना चाहिए कि दुर्गुण कहीं हमारे अंदर ही तो कुंडली मारकर नहीं बैठे हैं। अगर एक व्यक्ति अपने अंदर बदलाव करने के लिए संकल्प ले लेता है तो वहीं से उसके जीवन में नवनिर्माण की शुरुआत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। वह पग-पग पर उसका सहयोग करने लगते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने ईश्वर की सबसे सुंदर कृति को बेहतर बनाने के लिए स्वयं के अंदर के नकारात्मक विचारों का परित्याग करने का संकल्प लिया है और सृजनात्मक कार्यों को गति देने के लिए ईश्वरीय नियमों-सिद्धांतों और सूत्रों का वरण किया है।

स्वयं को बिना बदले देश-समाज में किसी भी प्रकार के बदलाव की आशा करना निरर्थक है। स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाना व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जिस प्रकार नए मकान का निर्माण करने से पूर्व उसकी मजबूत नींव बनाई जाती है, तभी उस पर ऊंची गगनचुंबी इमारत खड़ी हो पाती है। इसी तरह से महानता की इमारत तैयार करने के लिए भी व्यक्तित्व की ठोस नींव तैयार करनी पड़ती है। महानता और मनुष्यता का निर्माण व्यक्तित्व को गढ़ने से ही संभव है। व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर निरंतर बालू, सीमेंट, छड़ और पानी के रूप में श्रद्धा, संकल्प, लगन, जिज्ञासा, योजना और साहस का मन के साथ पूर्णरूपेण तारतम्य बनाएं रखना होता है। वैसे क्षणिक सुख-शांति तो थोड़े परिश्रम के बल पर प्राप्त हो जाती है, पर शाश्वत सुख-शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने मन में बैठे दुर्गुणों से निरंतर लड़ते हुए उन्हें बाहर निकालकर उनकी जगह सद्गुणों को नियोजित करते रहना पड़ता है।

भगीरथ कुमार

कम न होने पाए बुजुर्गों का सम्मान

सुनीता मिश्रा

> माता-पिता कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का प्यार से पालन-पोषण करते हैं। बच्चों को भी बुजुर्गों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए

बीते दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने एक पारिवारिक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बुजुर्ग सास, दादी सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए में निहित मौलिक कर्तव्यों, यजुर्वेद और मनुस्मृति का भी हवाला दिया। उसने यजुर्वेद का जिक्र करते हुए कहा- हे महिला, तुम चुनौतियों से हारने के लायक नहीं हो, तुम सबसे शक्तिशाली चुनौती को हरा सकती हो। मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस परिवार की महिलाएं दुखी होती हैं, वह परिवार जल्द ही नष्ट हो जाता है। जहां महिलाएं संतुष्ट रहती हैं, वह परिवार हमेशा फलता-फूलता है। वहीं अनुच्छेद 51-ए का उल्लेख करते हुए कहा, ''मौलिक कर्तव्यों में हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का प्रविधान है।''

देखा जाए तो हमारा समाज पुरुष और महिलाओं दोनों से कुछ उम्मीदें करता है। विवाह के बाद पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वह पैसे कमाकर अपना घर चलाएगा। पत्नी की देखभाल करेगा और उसकी जरूरतों का ख्याल रखेगा। वहीं महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह पति, बच्चों और ससुरालवालों की अच्छे से देखभाल करेगी। बुढ़ापे में सास-ससुर की सेवा करेगी।

एक परिवार की तरक्की में बुजुर्गों का बड़ा योगदान होता है। वे परिवार की रीढ़ होते हैं। घर में बुजुर्गों के रहने से बच्चों के अलावा अन्य लोगों को भी सहारा रहता है। बुजुर्ग स्वजनों में संस्कार निर्माण में सहायक होते हैं। उनकी सूझबूझ से परिवार पर आने वाली हर मुश्किल दूर होती है। बुजुर्ग हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते हैं, जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, वे सबसे खुशनसीब होते हैं। उनके होने से बच्चों को माता-पिता के साथ-साथ दादा-दादी का भी प्यार मिलता है। उनके बिना खुशहाल परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि खुशहाल परिवार के लिए घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि वे परिवार को एक सूत्र में बांधकर ले चलते हैं। बुजुर्गों के साथ रहना हमारी संस्कृति रही है। उनसे अलग रहकर कोई भी परिवार तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बुजुर्गों की सेवा करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार माता-पिता कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का बहुत ही प्यार से पालन-पोषण करते हैं। उसी प्रकार युवाओं को भी बुजुर्गों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। युवाओं को बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की जरूरत है। अगर वे बुजुर्गों के साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो आगे चलकर उनको भी इस दौर से गुजरना पड़ सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

राष्ट्र निर्माण से जुड़ी प्राण प्रतिष्ठा

यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अलौकिक दृश्य के हम सब साक्षी बने। संजय गुप्त के आलेख 'राम से राष्ट्र की ओर' में यह जाहिर होता है कि भारत एक ऐसे युग की ओर अग्रसर है जहां धार्मिक मुद्दों से आगे बढ़कर विकास के मुद्दों पर बात हो रही है। आज की जनता उन घिसे-पिटे धर्म और जाति वाले वादों से परे ज्ञान और सुविधाओं का विकास चाहती है। राम मंदिर बनने से जिनके मन को ठेस लगी है उन्हें इतिहास के पन्नों में झांकने की जरूरत है। उन्हें यह समझना होगा कि भारत का इतिहास उनके सोच से कहीं ज्यादा विशाल और संपन्न है। हमारे पूर्वजों ने सभी धर्मों का सम्मान किया है तो वहीं आवश्यकता पड़ने पर धर्मरक्षा के लिए हथियार भी उठाए हैं। यह जरूरी है कि लोग जागरूक हों और किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता को जांच लें। यूपी में 1948 के उपचुनाव में विपक्ष की तरफ से पहली बार राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया था। क्या तब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो रही थी? देखा जाए तो धर्म और राजनीति एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। समाजवादी चिंतक डा. राममनोहर लोहिया ने धर्म और राजनीति को एक ही बताया था। उन्होंने कहा था, 'राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति।' प्रधानमंत्री मोदी के शब्द की 'राम आग नहीं ऊर्जा हैं' को साकार करने का यही सही समय है। यह ऊर्जा श्रीराम के आदर्शों के रूप में हम सबमें विद्यमान है और इसी के साथ हमें राष्ट्र निर्माण की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। मंदिर श्रीराम के आदर्शों को अपनाते हुए समर्थ, सक्षम और भव्य भारत बनाने की प्रेरणा देता है। जिस दिन देशवासियों के मन में श्रीराम के शुभ विचार समाएंगे तभी राम आएंगे और पुनः स्थापित होगा रामराज्य।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

सिमटते जनाधार को बचाने का उपक्रम

आइएनडीआइए में दिखती दरार के बीच नीतीश कुमार भाजपा के साथ हो लिए। इस पाला बदल खेल को एक कहावत से समझा जा सकता है कि नई बोतल में पुरानी शराब फिर से भरी गई है। हाल में अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से भाजपा खासकर नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता में हुई गुणात्मक वृद्धि से प्रभावित होकर एवं अपने सिमटते जनाधार को बचाने का उपक्रम करते हुए जदयू ने राजद से किनारा कर लिया। वहीं दूसरी ओर राजद की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। इससे आइएनडीआइए के खत्म होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

जागृत होता भारत का "स्व"

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा तो केवल प्रारंभ है, आगे का मार्ग जनमानस को ही तय करना है। हजार वर्षों की गुलामी को मन मस्तिष्क से मिटाना दस वर्षों का काम नहीं है। बेशक इन दस वर्षों में भारत का ''स्व'' जागृत होना आरंभ हुआ है। केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और संघ के ही भरोसे रहकर ''स्व'' से स्वराष्ट्र के परम वैभव की संपूर्ण संकल्पना संभव नहीं है। इसके लिए वह सभी कारकों को पहचानने और उन कंटकों को मार्ग से हटाने का भी प्रण लेने की आवश्यकता है, जो भारत के परम वैभव को नष्ट-भ्रष्ट करने या अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमें श्रीराम, श्रीकृष्ण, सम्राट अशोक, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा चाहिए और जयचंदों को दंड देने वाली जनशक्ति चाहिए। समाज में नारी पर कोई आंख भी न उठाए, जाति-धर्म का कोई विद्वेष न हो और समाज के सभी वर्गों को बराबरी देने वाली राजनीतिक व्यवस्था संसद और विधानसभाओं में स्थापित हो। देशद्रोहियों के इस देश को खंडित करने के मंसूबे मिट्टी में मिलाने की आवश्यकता है। रामराज्य की स्थापना कपोल कल्पित धारणाओं से नहीं होगी, इसके लिए फौलादी इरादे चाहिए। राजनीति की दिशा जनमानस को ही मोड़नी है, जिसके लिए हमें मोदी जैसे सैकड़ों नायक चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं प्रबंध संपादक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

30 करोड़ आयुष्मान कार्डधारकों की संख्या है देश में, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश (4.83 करोड़) से हैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्डधारकों की संख्या 3.78 करोड़ और महाराष्ट्र में 2.39 करोड़ है।

आजकल

भारतीय राजनीति में 'एएम' और 'पीएम'

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

बिहार में रविवार को जदयू औपचारिक रूप से राजग में शामिल हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं। संभवत: जदयू के लोकसभा के संभावित अधिकांश उम्मीदवारों समेत पार्टी के अन्य नेताओं को यह महसूस हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए भाजपा का सहयोग आवश्यक है, लिहाजा उन्होंने भाजपा का साथ आवश्यक समझा, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना का उद्धव गुट आज भी यह समझ नहीं पा रहा है

आगामी चुनावी रणनीति के तहत राजनीतिक लाभ के लिए बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के सहयोग से बने मुख्यमंत्री। फाइल

सामान्य बोलचाल की भाषा में 'एएम' और 'पीएम' शब्दों को आंटे मेरीडियन (पूर्वाह्न) और पोस्ट मेरीडियन (अपराह्न) के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा से जोड़ते हुए 'आरोहणम मार्तंडस्य' एवं 'पतनम मार्तंडस्य' भी कहने लगे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में अब 'एएम' और 'पीएम' का अर्थ- 'मोदी से पूर्व' और 'मोदी के पश्चात' भी कहा जा सकता है। यानी राष्ट्रीय राजनीति में 2014 से पहले और उसके बाद का काल। देखा जा रहा है कि जो राजनेता 'एएम-पीएम' की इस वास्तविकता को समझ पा रहे हैं, वे गलतियां करने से बच जा रहे हैं, या हुई गलतियां सुधार ले रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उपरोक्त तथ्य के दो बड़े उदाहरण महाराष्ट्र और बिहार में देखे जा सकते हैं। इन दोनों राज्यों में राजग गठबंधन का हिस्सा रहे जदयू और शिवसेना को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में अच्छी सफलता मिली थी, क्योंकि ये दोनों दल मोदी के उभार के बाद वाली भाजपा से गठबंधन करके लड़े थे। शिवसेना का तो तब तक भाजपा के साथ सबसे पुराना गठबंधन था ही। उधर जदयू को भी 2019 के चुनाव में भाजपा से गठबंधन करके लड़ने पर 16 सीटें हासिल हुईं, जबकि 2014 में वह अकेले लड़कर महज दो सीटों पर ही अटक गई थी। जबकि भाजपा ने उस समय 22 सीटें (पूरे गठबंधन को 31) प्राप्त की थीं। यह भाजपा की उदारता ही थी कि उसने 2019 में गठबंधन करते समय केवल दो सीटों वाली जदयू को 17 सीटों पर लड़ने का अवसर देकर स्वयं अपनी सीटें कम कर लीं। इस कारण उसे 2019 में 17 सीटें ही हासिल हुईं। भाजपा ने यही उदारता जदयू के साथ विधानसभा चुनाव में भी दिखाई और कम सीटें पानेवाली जदयू को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। लेकिन जदयू ने उसकी उदारता की बेकद्री करते हुए दूसरा साझीदार तलाश लिया था। लेकिन डेढ़ वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस गलती का अहसास हुआ, और उनकी घरवापसी भी हो गई।

महाराष्ट्र में शिवसेना की गलती : यही गलती महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी की। वर्ष 2004 में 12 और 2009 में 11 सीटें ही जीत पानेवाली शिवसेना को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 18-18 सीटें मिलीं। वर्ष 2014 में पहली बार 18 सीटें जीतते ही शिवसेना अतिआत्मविश्वास में इसे अपने दम पर मिली सफलता मानने लगी। जबकि इस अप्रत्याशित सफलता में बड़ा योगदान उस समय की 'मोदी लहर' का था। लेकिन शिवसेना ऐसा मानने को तैयार नहीं थी। लोकसभा चुनाव के छह माह बाद ही विधानसभा के भी चुनाव होने थे। उससे पहले के विधानसभा चुनावों में राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से शिवसेना 171 और भाजपा 117 पर चुनाव लड़ती आई थी। जबकि शिवसेना की लड़ी जानेवाली सीटों में 50 सीटें ऐसी थीं, जिन पर वह कभी चुनाव नहीं जीत सकी थी। भाजपा का आग्रह था कि इनमें से ही कुछ सीटें उसे देकर इस बार बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। भाजपा का मानना था कि बराबरी की सीटों पर लड़कर मोदी लहर का लाभ लेते हुए अधिक सीटें जीती जा सकती हैं। लेकिन शिवसेना को डर था कि ऐसा होने पर यदि भाजपा की सीटें अधिक आईं, तो सीएम पद पर दावा भाजपा कर सकती है। इसलिए शिवसेना उसके लिए तैयार नहीं हुई और भाजपा के साथ उसका 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। इसके बाद ढाई दशक में भाजपा पहली बार उन सीटों पर भी चुनाव लड़ी, जहां शिवसेना ने उसे कभी स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ने दिया था।

चुनाव परिणाम आने पर भाजपा को 122 सीटें मिलीं और शिवसेना 63 सीटों पर ही सिमट गई। अर्थात अपनी-अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने के बाद आए परिणामों ने शिवसेना की वास्तविक ताकत को दर्शा दिया। जो शिवसेना दावा करती आई थी (अभी भी करती है) कि भाजपा उसके कंधों पर सवार होकर केंद्र की सत्ता तक पहुंची, महाराष्ट्र में ही वह भाजपा से आधे पर सिमटकर रह गई। लेकिन भाजपा ने चुनाव के एक माह बाद ही शिवसेना से अपने 25 वर्ष पुराने संबंधों का मान रखते हुए उसे सरकार में शामिल होने का न्यौता दे दिया, और शिवसेना राजी भी हो गई। परंतु शिवसेना सरकार में छोटे भाई की भूमिका को हजम नहीं कर पा रही थी। कई बार प्रदेश नेतृत्व द्वारा उसे समझाने की कोशिशें की गईं, चेतावनियां दी गईं। लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला।

वर्ष 2019 में चुनाव से ठीक पहले शिवसेना चाहती थी कि लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनावों की शर्तें एक साथ तय हो जाएं। भाजपा ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री पद पर वह कोई समझौता नहीं करेगी। शिवसेना इस पर मान भी गई। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा के चुनाव साथ लड़े गए। दोनों चुनावों पर मोदी लहर का असर था। लोकसभा में भाजपा-शिवसेना ने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराया। छह माह बाद हुए विधानसभा चुनाव भी दोनों दल मिलकर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में लड़े। भाजपा 164 सीटों पर लड़कर 105 सीटें जीती और शिवसेना 124 सीटों पर लड़कर 56 सीटें जीती। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस-राकांपा के साथ ऊपरी स्तर पर हुआ यह समझौता शिवसेना के ज्यादातर सांसदों और विधायकों को भी हजम नहीं हुआ। क्योंकि वे भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही जीतकर आए थे। उन्हें भाजपा के परंपरागत मतदाताओं ने भी वोट दिए थे। साथ ही, यह भी अकाट्य सत्य था कि 2019 में भी उन्हें 'मोदी लहर' का लाभ मिला था। वह जानते थे कि अगले चुनाव में यदि वह कांग्रेस और राकांपा से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरे, तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जवाब देना पड़ेगा।

वहीं भाजपा से मिले उसके लाभ को देखें तो उस समय अयोध्या में श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी। न ही राम लहर जैसी कोई चीज दिख रही थी। बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव होने तक न तो अयोध्या के राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, न कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की घोषणा हुई थी, न ही कोविड के दौरान शुरू हुई 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना शुरू हुई थी, और न देश में एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हो सका था। संभवत: यही कारण है कि चुनाव के दौरान इन सांसदों ने महसूस किया था कि उन्हें मिलने वाले मतों में एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी की उस छवि का है, जिस कारण लोग उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें वोट दे रहे हैं। मतदाताओं का यह दबाव ही उन्हें उद्धव से छिटककर मोदी की ओर जाने को मजबूर कर रहा था।

निश्चित रूप से बिहार में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़नेवाले जदयू के सांसद और विधायक भी इसी प्रकार का दबाव अपने मतदाताओं की ओर से महसूस करते रहे होंगे। नीतीश की घरवापसी में अन्य कारणों के अलावा यह दबाव भी एक बड़ा कारण रहा होगा, जिसे नीतीश कुमार ने तो समय रहते महसूस कर लिया, परंतु उद्धव ठाकरे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वह आज भी 2014 से पहले की ही भाजपा को देख पा रहे हैं। जबकि 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी के उदय से पहले की भाजपा और उसके बाद धीरे-धीरे खड़ी हो रही मोदी-शाह की भाजपा में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है। कुछ भी हो, नीतीश कुमार एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वह अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं। वहीं उद्धव ठाकरे अपने निर्णयों के लिए अपने सिपहसालारों पर निर्भर हैं। उनका दुर्भाग्य है कि उनके सिपहसालार उन्हें देश में हो रहे बदलावों की वास्तविकता से दूर रखने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं।

राजनीतिक पाला बदल के निहितार्थ

लोकमित्र

बिहार की राजनीति में दो मजबूत धड़े हैं- एक भाजपा और दूसरा राजद। ये दोनों लगभग बराबर के हैं। जदयू इनमें से जिसकी ओर चला जाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है। इस स्थिति का नीतीश कुमार ने भरपूर लाभ लिया है। विधानसभा में बहुत कम सीटें होने के बावजूद वह निरंतर सीएम बनने में सफल रहे हैं। इस कामयाबी के बावजूद विधानसभा में जदयू की सीटों में कमी ही आई है, जबकि कभी वह भाजपा के साथ गठबंधन में होते हुए भी राज्य में सीनियर पार्टनर थी, आज जूनियर पार्टनर है, लेकिन बिहार की 'संतुलन की राजनीति' के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जदयू के विधायकों की संख्या में निरंतर कमी आने का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना बिहार की जनता को पसंद नहीं आया है। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की अवसरवादी राजनीति का लिटमस टेस्ट होगा जो उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा।

वैसे इस बार ऐसा महसूस होता है कि भाजपा ने अपनी शर्तों पर नीतीश कुमार से समझौता किया है, जिससे नीतीश की राजनीतिक स्थिति कमजोर ही हुई है। कहा जाता है कि नवंबर 2020 में विधानसभा के पश्चात नई सरकार बनने पर नीतीश कुमार इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि भाजपा ने तारकेश्वर प्रसाद व रेनू देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया था। वह सुशील मोदी को पसंद करते थे, जो उनके साथ तीन बार उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। भाजपा ने इस बार भी नीतीश कुमार की पसंद की परवाह नहीं की है। उसने विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, जो हमेशा ही नीतीश कुमार की नाक में दम करते रहे हैं। वर्ष 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए सिन्हा ने उनके कामकाज में काफी दखलंदाजी की थी। सिन्हा व चौधरी की नियुक्ति इस तथ्य का संकेत है कि इस बार भाजपा अधिक संख्या के बावजूद दब्बू व दोयम दर्जे का साझेदार बनकर नहीं रहेगी। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

खरी-खरी

बड़े लोगों की बड़ी बातें

रेखा शाह आरबी

कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े कि हर छोटी बात में उनका बड़प्पन खतरे में आ जाता है। उन्हें अपने बड़प्पन को सुरक्षित रखने के लिए हर वक्त अपने बड़प्पन को जेड श्रेणी की सुरक्षा घेरे में रखना पड़ता है। जरा सी ऊंच-नीच क्या हो जाए, उन्हें अपना बड़प्पन खतरे में होने की घंटी सुनाई देने लगती है। जहां पद और कद में छोटे लोग नजर आते हैं, उनके सिस्टम का अलार्म अपने आप एक्टिव हो जाता है। वह उन्हें बताने लगता है कि यहां पर पद और कद में छोटे लोग हैं। थोड़ा बचकर ही रहना, यहां पर खतरा है। उनके बड़प्पन को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है छोटे-मोटे लोगों के साथ बैठने उठने पर। वह इतने बड़े होते हैं कि सारी सुविधाओं पर सबसे पहले अपना ही हक समझते हैं। भले ही चाहे वह किसी और के हिस्से की हो, लेकिन वह सबसे पहले स्वयं को रखते हैं। छोटे लोगों की मदद करने से तो उनका बड़प्पन डांवाडोल ही हो जाता है। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं।

ऐसे लोगों का एक स्वाभाविक गुण है, इन्हें अपने हाथ में पड़ा हुआ रसगुल्ला ज्यादा खुशी नहीं देता है, बल्कि छोटे लोगों के हाथ का लड्डू इन्हें नागवार गुजरता है। ये लोग उसे भी छीन कर खा लेते हैं। या किसी अपने ऐसे प्रिय को खिला देते हैं, जिससे उनके हजार काम निकल सकें। ये बड़े-बड़े लोग अन्य लोगों से काम करवाना तो अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन कभी इनसे किसी काम के लिए कह दीजिए तो इसे अपना अपमान समझते हैं।

ऐसे ही एक पकौड़ी लाल के इंटरनेट मीडिया के एक मित्र हैं। एक दिन एक काम लेकर पकौड़ी जी के पास आ गए। साहित्य के क्षेत्र में बड़े उनके नाम के झंडे गड़े हैं, ऐसा वह स्वयं बताते हैं। वरना उससे पहले वह साहित्य के कौन से तोप हैं पकौड़ी जी को नहीं पता था। पकौड़ी जी ने उनका काम बिना हीलाहवाली के कर दिया। अभी कुछ दिन पहले उनसे एक काम पकौड़ी जी का निकल आया तो पता चला कि वह बहुत ही व्यस्त हैं। तब जाकर पकौड़ी लाल को व्यस्तता की असली परिभाषा समझ में आई। अब पकौड़ी लाल भी सीख गए हैं कि व्यस्तता असल में व्यस्त रहने में नहीं होती है।

X पोस्ट

रामविलास पासवान बदलते मौसम को भांप लेते थे। वहीं नीतीश कुमार तो मौसम ही बदल देते हैं।
कमलेश सिंह@kamleshksingh

नीतीश के राजग में आने के बाद आम चुनाव के लिए शायद ही कोई मुकाबला बचा है। मेरे लिए बस इतनी दिलचस्पी रह गई है कि भाजपा एवं राजग 2019 की अपनी सीटों में और कितनी बढ़ोतरी करेंगे और क्या कांग्रेस उतनी सीटें भी जीत पाएगी, जितनी उसे 2014 में मिली थीं।
संजय कुमार@sanjaycsds

तनावमुक्त और सहज मन एक विचलित मन से उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। इसलिए, माता-पिता को परीक्षा को भी एक 'पर्व' की तरह मनाना चाहिए और छात्रों पर दबाव डालने के बजाय उन्हें केंद्रित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनमें आत्मविश्वास भरना चाहिए।
श्रीश्री रविशंकर@SriSri

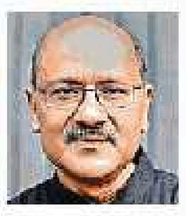

इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद दूसरी पारी में भारतीय स्पिनरों की नाकामी पर वाजिब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हमें यह सवाल भी करना होगा कि क्या शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर इस स्तर पर खेलने के योग्य हैं भी या नहीं?
शेखर गुप्ता@ShekharGupta

जागरण जनमत — कल का परिणाम

आपको लगता है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम की क्षमता आंकने में भारत ने बड़ी भूल की?

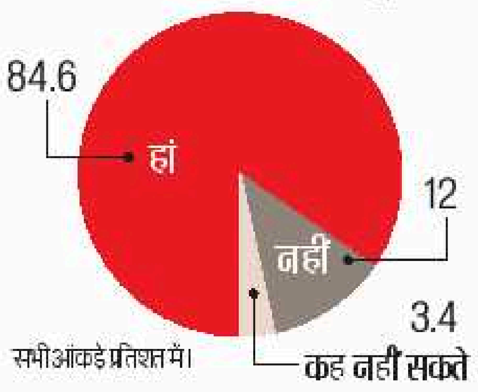

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में सरफराज खान का चयन उचित है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बैटर थे वह ओपनर किंतु हो गए कैच,
सकते में हैं टीम अब कैसे खेले मैच।
कैसे खेले मैच गई अब पलट कहानी,
राहुल जी के हाथ संभलती ना कप्तानी।
दिखना चाहें आप सदा मोदी से बेटर,
किंतु न पाएं ढूंढ़ कायदे का इक बैटर।
– ओमप्रकाश तिवारी

ममता की शर्तों के जाल में उलझी कांग्रेस

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनसे बात की। इसके बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीट बंटवारे से जुड़े गतिरोध पर तृणमूल के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। आइएनडीआइए में ममता की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि इसके अगले ही दिन ममता की ओर साफ कर दिया गया कि उनकी कांग्रेस अध्यक्ष से कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन को लेकर भले नरम रुख अपनाने की बातें कहे, लेकिन तृणमूल सुप्रीमो फिलहाल तैयार नहीं हैं। कहा जा रहा है कि तृणमूल की ओर से कांग्रेस हाईकमान के समक्ष तीन शर्तें रखी गई थीं। ये शर्तें ऐसी हैं कि कांग्रेस उनमें पूरी तरह उलझ गई है।

तृणमूल नेतृत्व ने कांग्रेस हाईकमान के समक्ष तीन शर्तें रखी हैं, जिनमें पहली है, बंगाल में कांग्रेस को अधिकतम तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। इसके बदले असम और मेघालय में तृणमूल को तीन सीटें देनी होंगी। दूसरी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी को हटाना होगा, क्योंकि वे ममता पर हमलावर रहते हैं। अभी पिछले गुरुवार को ही तृणमूल के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा था कि आइएनडीआइए के बंगाल में आकार नहीं लेने के कारण अधीर हैं। वहीं, तीसरी शर्त है कि कांग्रेस को बंगाल में माकपा का साथ छोड़ना होगा। ये ऐसी शर्तें हैं, जिन्हें कांग्रेस के लिए पूरा करना मुश्किल होगा। अगर कांग्रेस बंगाल में माकपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती है तो केरल, त्रिपुरा और बिहार में उसे नुकसान हो सकता है। ममता शुरू से ही बंगाल में आइएनडीआइए में वामपंथी, विशेषकर माकपा को साथ रखने को राजी नहीं हैं। ममता ने कांग्रेस को इस बारे में दो बार आगाह किया था। पहले स्वयं ममता के भतीजे व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मिलकर माकपा को बाहर करने की मांग की थी, फिर सोनिया गांधी से मुलाकात में ममता ने इसे दोहराया था। वहीं माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी से लेकर बंगाल के माकपा नेतृत्व भी तृणमूल के साथ गठबंधन को खारिज करते आ रहे हैं।

ममता बनर्जी। फाइल

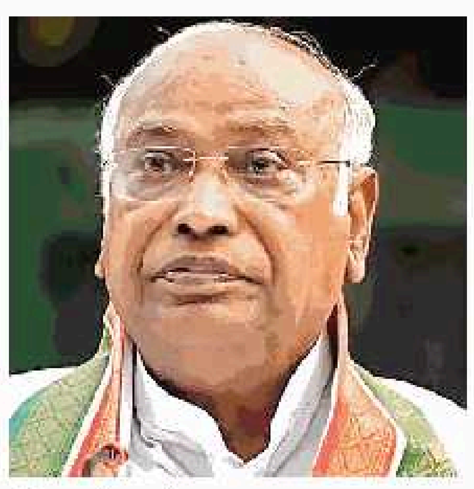

मल्लिकार्जुन खरगे। फाइल

इस बीच जब ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की तो माकपा ममता पर और आक्रामक हो गई। बंगाल माकपा के सचिव मोहम्मद सलीम ने नीतीश कुमार के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी की 'बिन पेंदी के लोटे' से तुलना कर दी और दावा किया कि भाजपा और संघ के इशारे पर तृणमूल बनी, ताकि कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी राजग में जा सकें। सलीम के इस बयान में कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है, न ही उनके रुख में किसी तरह का बदलाव नजर आ रहा है। माकपा नेता आइएनडीआइए की बैठकों में कहते आए हैं कि बंगाल में तृणमूल से गठबंधन नहीं होगा। ममता ने भी पिछले दिनों यह आरोप लगाया था कि वामपंथी नेता गठबंधन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। माकपा का अड़ियल रुख और ममता की क्लियर लाइन से बंगाल की सियासत में कांग्रेस ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई है, जहां से एक रास्ता माकपा के साथ जाता है, जिस रास्ते पर वह पहले से ही है और दूसरा रास्ता ममता की पार्टी के साथ जाता है। माकपा और तृणमूल का साथ आना मुश्किल है और ऐसे में कांग्रेस इस सवाल में उलझ गई है कि माकपा को चुने या ममता की शर्तें मान उनके साथ चले। कांग्रेस को माकपा की कीमत पर ममता का साथ चुनना होगा या ममता की कीमत पर माकपा को। सवाल है कि कांग्रेस के लिए आखिर कहां लाभ है?

तृणमूल के साथ बंगाल की सत्ताधारी पार्टी होने का माइलेज है ही, पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी मजबूत है। सभी चुनाव अकेले लड़ते हुए तृणमूल का प्रदर्शन भी उसकी मजबूती दर्शाता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अगर बंगाल में सियासी जमीन बचाना चाहती है तो तृणमूल के साथ जाना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। दूसरी तरफ माकपा के साथ जाने से बंगाल में भले उसे अधिक फायदा न हो, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके सागरदीघी में माकपा-कांग्रेस गठबंधन ने तृणमूल को हरा दिया था। वैसे ममता के लिए भी कांग्रेस को साथ रखना मजबूरी है क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बंटने का डर सता रहा है। भाजपा के लिए दोनों ही परिस्थितियों में अनुकूल स्थिति है। अगर गठबंधन हुआ तो ममता विरोधी वोट एकजुट होकर भाजपा को मिलेगा और अगर नहीं हुआ तो मुस्लिम वोट का बंटना तय है क्योंकि माकपा-कांग्रेस के साथ-साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी इस गठबंधन में होगी। शनिवार को तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ममता ने कांग्रेस की 'अनुचित मांगों' के कारण बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तृणमूल विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए का हिस्सा नहीं है।

बजट

सबकी चिंता, सबका ध्यान

बजट में बहुसंख्यक जनसंख्या की चुनौतियों के समाधान की राह आसान की जानी चाहिए

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

वैश्विक आर्थिक प्रमुखता की दिशा में भारत की यात्रा में बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह खर्च, राजस्व सृजन तथा देश के विकास पथ की योजनाओं को चित्रित करता है। यह सभी क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से संसाधनों का आवंटन करके विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन और गरीबी को कम करने की क्षमता रखता है। बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए पर्याप्त धन का प्रविधान करना एवं प्राथमिकताओं को संतुलित करना अनिवार्य है। एक स्थिर व पूर्वानुमानित बजट निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और रोजगार सृजन एवं आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बजट हमारी अनेक चुनौतियों का समाधान कर सकता है। लिहाजा बजट से आमजन की व्यापक अपेक्षाएं रहती हैं।

कृषि क्षेत्र का उद्धार : कृषि क्षेत्र पर निरंतर ध्यान देना होगा। बजट को कम आय, बाजार में अस्थिरता और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का निरंतर सामना करना होगा। प्राथमिकता वाले उपायों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा निर्धारित करना, बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण कवच बनाना शामिल है। मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए पीएम-किसान जैसी योजनाओं का विस्तार करने से मौसमी आय अंतर पर ध्यान दिया जा सकेगा और किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। सिंचाई परियोजना, कोल्ड स्टोरेज सुविधा और ग्रामीण सड़कों सहित कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना, रसद को सुव्यवस्थित करना, बर्बादी को कम करना और किसानों की विपणन क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है।

समावेशी विकास : गरीबी आज भी देश की एक कड़वी सच्चाई बनी हुई है। लिहाजा बजट को एक ऐसा मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाने की जरूरत है, जो हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाए और उन्नति के लिए मार्ग तैयार करे। गरीबी की वास्तविकता का सामना करने के लिए कमजोर लोगों के लिए एक लचीला सुरक्षा तंत्र तैयार करना आवश्यक है। महिलाओं और बच्चों पर लक्षित फोकस के साथ विशिष्ट जिलों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआइ) योजनाओं को संचालित करने से, आर्थिक नुकसान से सम्मानजनक सुरक्षा की संभावना स्पष्ट हो जाती है। बढ़े हुए बजटीय आवंटन के माध्यम से मनरेगा और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने से ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए सुरक्षा जाल मजबूत होगा।

विकास को गति : मजबूत बुनियादी ढांचा एक संपन्न अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बजट में रोजगार सृजन, आर्थिक क्षमता को खोलने और संपर्क बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए। विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देता है, जिसका लक्ष्य रोजगार पैदा करना, आर्थिक क्षमता को अनलाक करना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

स्वास्थ्य सेवा : स्वास्थ्य सेवा हमारे देश के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। बजट में इसे सभी के लिए सुलभ व किफायती बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूरी आबादी को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने जैसी पहल आय स्तर की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए, उन्नत उपकरण और जनशक्ति के साथ-साथ ग्रामीण व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि आवश्यक है।

जनता के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं। फाइल

कर व्यवस्था : ऊंची आयकर दरें अक्सर आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहित करने वाली लगती हैं। बजट में कर ढांचे को सुव्यवस्थित करते हुए कुछ राहत दी जानी चाहिए। वेतनभोगी व्यक्तियों पर कर का बोझ कम किए जाने के उपाय तलाशने होंगे। इसी तरह से आर्थिक विकास के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। कई स्लैब वाली वर्तमान जटिल संरचना अनुपालन और प्रशासनिक लागत के मामले में व्यवसायों, विशेष रूप से एसएमई के लिए चुनौतियां पैदा करती है। जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने, स्लैब को कम करने और इस संबंध में स्पष्ट प्रविधान किए जाने से यह बोझ कम होगा एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। महामारी के बाद के सुधार चरण में, एक अच्छी तरह से संरचित जीएसटी प्रणाली आर्थिक पुनरुद्धार, निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और सतत विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रेरक बन जाती है। इसलिए बजट में जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के लिए एक केंद्रित और रणनीतिक दृष्टिकोण भारत के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण है।

****

तीसरी तिमाही में वोडाफोन को 6,986 करोड़ का घाटा

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6,986 करोड़ रुपये का घाटा रहा है। पिछले वर्ष की समान अवधि के 7,990 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें कमी रही है। बीती तिमाही में कंपनी का संचालन राजस्व 10,673.1 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा है। अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान औसत राजस्व प्रति ग्राहक (एआरपीयू) बढ़कर 145 रुपये रहा है। वार्षिक आधार पर इसमें 7.4 प्रतिशत की वृद्धि रही है। (प्रेट्र)

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार को आगामी बजट में इन पर जीएसटी में कमी लानी चाहिए। साथ ही इन्हें खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहन भी दिया जाए।
— कृष्णन रामचंद्रन, सीईओ, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस

सेंसेक्स	71,941.57	▲ 1,240.90
निफ्टी	21,737.60	▲ 385
सोना प्रति दस ग्राम	₹63,100	▲ ₹200
चांदी प्रति किलोग्राम	₹76,400	▲ ₹200
डालर	₹83.16	▲ ₹0.05
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$83.40	

एक नजर में

तीसरी तिमाही में बीपीसीएल का शुद्ध लाभ 82% बढ़ा

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वितरण कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 3,181.42 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। अक्टूबर-दिसंबर 2022 के 1,747.01 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें 82 प्रतिशत की वृद्धि रही है। उधर, सरकारी गैस कंपनी गेल का शुद्ध लाभ अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही में 10 गुना बढ़कर 2,842.62 करोड़ रुपये रहा है। (प्रेट्र)

2023 में आइफोन की बिक्री 28 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली : प्रीमियम स्मार्टफोन की बढ़ती मांग के चलते 2023 के दौरान भारत में आइफोन की बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इस तेजी की बदौलत आइफोन की बाजार हिस्सेदारी भी 2022 की चार प्रतिशत से बढ़कर पिछले वर्ष छह प्रतिशत से ज्यादा रही है। सीएमआर के अनुसार, 2023 की चौथी तिमाही में आइफोन की थोक बिक्री में सात प्रतिशत की वृद्धि रही है। (आइएएनएस)

फरवरी में भारत दौरे पर आएंगे सत्या नडेला

नई दिल्ली : माइक्रोसाफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला अपनी वार्षिक यात्रा के लिए सात और आठ फरवरी को भारत में रहेंगे। इस दौरान वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर एआइ में नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। कंपनी ने बताया कि सत्या नडेला डेवलपर्स और टेक्नीशियन को भी संबोधित करेंगे। (आइएएनएस)

नवंबर में रिलायंस जियो से 34.5 लाख सब्सक्राइबर जुड़े

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो से नवंबर 2023 में 34.5 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। इसके साथ जियो के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 45.58 करोड़ हो गई है। इसी तरह, समान अवधि में भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर की संख्या 17.5 लाख बढ़कर 37.98 करोड़ हो गई है। हालांकि, इस दौरान वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर की संख्या 10.7 लाख घटकर 22.44 करोड़ पर आ गई। (प्रेट्र)

अगले वित्त वर्ष भी सात प्रतिशत रह सकती है विकास दर

अंतरिम बजट से ठीक तीन दिन पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाती विस्तृत रिपोर्ट

राजीव कुमार • नई दिल्ली

1.9 ट्रिलियन डालर थी दस साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था

3.7 ट्रिलियन डालर के साथ अभी पांचवीं बड़ी इकोनमी है भारत

कोरोना महामारी और उसके ठीक बाद भू-राजनीतिक उथल-पुथल से जहां दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दो प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं वहीं भारतीय आर्थिकी आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है। इतना ही नहीं, अगले तीन साल में भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डालर की हो जाएगी और भारत आर्थिक आकार के लिहाज से अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार सात ट्रिलियन डालर हो जाएगा।

आगामी वित्त वर्ष के लिए एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से ठीक तीन दिन पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी विस्तृत रिपोर्ट में इन बातों की जानकारी दी गई है। अंतरिम बजट की वजह से अभी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 7.3 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है। अगर अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भी विकास दर अनुमान के मुताबिक सात प्रतिशत रहती है तो कोरोना काल के बाद लगातार चौथे साल सात प्रतिशत की विकास दर हासिल करने वाला एकमात्र देश भारत होगा। अच्छी बात यह है कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर में खुदरा महंगाई 5.5 प्रतिशत रही और आने वाले महीनों में इसमें कमी का अनुमान है।

मंत्रालय ने कहा- अगले तीन साल में पांच ट्रिलियन डालर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत

अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी कम नहीं

- वैश्विक स्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्यूफैक्चरिंग में वैश्विक निवेश संकुचित हो रहा है।
- लाल सागर का व्यवधान लंबा चला तो हमारा निर्यात प्रभावित होगा।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) सर्विस सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती है।
- ऊर्जा के परंपरागत माध्यम को छोड़ नए माध्यम को अपनाना भी एक कठिन काम है।

रिपोर्ट की खास बातें

- दिसंबर 2019 में घरों (हाउसहोल्ड) की शुद्ध वित्तीय संपदा जीडीपी के 52.8 प्रतिशत के बराबर थी, जो दिसंबर, 2023 में जीडीपी के 65.5 प्रतिशत के बराबर हो गई।
- जनधन योजना के तहत 51 करोड़ खाते हैं जिनमें 2.1 लाख करोड़ राशि जमा है। खाताधारकों में 55 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- वर्ष 2014 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के दो प्रतिशत के पास पहुंच गया था और महंगाई दहाई अंक में थी, अभी चालू खाते का घाटा जीडीपी के एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

सरकार की आर्थिक नीतियों ने हमारी बुनियाद को मजबूत किया

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 सालों में सरकार की आर्थिक नीतियों ने हमारी बुनियाद को मजबूत बना दिया है। कृषि से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग और डिजिटल सेवा की बदौलत सर्विस सेक्टर में मजबूती आई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में लगातार बढ़ोतरी से देश में बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट और सड़क से लेकर बिजली व्यवस्था चुस्त हुई। इससे कारोबार की लागत कम हो रही है और विदेशी व घरेलू दोनों ही निवेश में बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2015 से लेकर वित्त वर्ष 2024 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में 3.3 गुना बढ़ोतरी हुई। पिछले कई सालों से पर्सनल लोन व फूड लोन को छोड़ अन्य लोन में दहाई अंक में बढ़ोतरी जारी है।

कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बताया

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बताया है। चालू वित्त वर्ष में कृषि का भारत के जीवीए में 18 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2015 से 2023 के दौरान प्रति वर्ष औसत खाद्यान्न उत्पादन 28.9 करोड़ टन रहा जबकि वित्त वर्ष 2005-2014 तक यह 23.3 करोड़ टन था। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन सेक्टर में भविष्य में सुधार की आवश्यकता है, उसमें स्किल, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, एमएसएमई शामिल है।

तीसरी बड़ी इकोनमी बनने का मूल आधार होगा अदाणी समूह

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्तीय सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी कैंटर फिट्जगेराल्ड एंड कंपनी ने कहा है कि अदाणी समूह 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का मूल आधार है। देश के बुनियादी ढांचे के विकास में समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्लेषक ब्रेट नाब्लाउच और थामस सिंस्के द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड 50 प्रतिशत से अधिक का लाभ दे सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को अपने ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के अलावा, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे दोनों में निवेश करना होगा।

लाल सागर के हालात को लेकर दूसरे देशों के संपर्क में भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: लाल सागर क्षेत्र में हाउती विद्रोहियों की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत की जरूरत का 30 प्रतिशत क्रूड इसी रास्ते से आता है जबकि भारत अपने कुल पेट्रोलियम निर्यात का 50 प्रतिशत इस रास्ते से भेजता है। ऐसे में भारत चिंता में तो है लेकिन अभी तक लाल सागर में जहाजों के आवागमन के प्रभावित होने से देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई समस्या पैदा नहीं हुई है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि इस बारे में अगले हफ्ते आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के दौरान दुनिया के कई देशों के आमंत्रित मेहमानों और पेट्रोलियम मंत्रियों के साथ बातचीत होगी। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन छह से नौ फरवरी, 2024 के दौरान गोवा में होगा। इसमें 17 देशों के पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेक्टर की 900 कंपनियां हिस्सा लेंगी। पुरी का कहना है कि इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में ऊर्जा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। आगामी महीने इसकी बैठक मुख्य तौर पर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के तमाम मुद्दों के साथ ही भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने से जुड़े मुद्दों पर विमर्श से होगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि एनर्जी वीक से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक आयल व गैस कंपनियों के सीईओ के साथ एक बैठक करेंगे।

अप्रैल से दिसंबर के दौरान सोना आयात 26.7% बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर के दौरान सोने का आयात 26.7 प्रतिशत बढ़कर 35.95 अरब डालर हो गया। एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 28.4 अरब डालर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले साल दिसंबर में सोने का आयात 156.5 प्रतिशत बढ़कर तीन अरब डालर रहा।

इस साल भारत में लैपटाप बनाना शुरू कर देगी सैमसंग

गुरुग्राम, प्रेट्र: दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रानिक कंपनी सैमसंग इस साल भारत स्थित अपने नोएडा संयंत्र में लैपटाप बनाना शुरू कर देगी। भारत दौरे पर आए सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स के प्रेसिडेंट और मोबाइल एक्सपीरियंस (एमएक्स) बिजनेस के प्रमुख टीएम रोह ने कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग के लिहाज से कंपनी के लिए भारत एक प्रमुख स्थान है और लैपटाप बनाने के लिए तैयारियां पहले से ही चल रही हैं।

रोह ने कहा कि कंपनी को राज्य व केंद्र सरकार से हर समर्थन मिला है और कंपनी भारत में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार के साथ सहयोग जारी रखेगी। हाल में कंपनी ने अपना फ्लैगशिप गैलेक्सी एस24 स्मार्टफोन लांच किया है। कंपनी ने कहा है कि वह अपने नोएडा स्थित कारखाने में गैलेक्सी एस24 का भी निर्माण करेगी। इसी के साथ सैमसंग ने इस साल 'गैलेक्सी एआइ' को 10 करोड़ मोबाइल में उपलब्ध कराने का भी एलान किया है।

भारी खरीदारी से सेंसेक्स में 1,240 अंक का उछाल

- ऊर्जा, तेल व गैस सेक्टर में तेजी से 71,941 पर पहुंचा बीएसई का मानक सूचकांक, निफ्टी भी चढ़ा
- एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से पहले आशावादी माहौल का भी मिल रहा लाभ

मुंबई, प्रेट्र: रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मजबूत खरीदारी और एशियाई बाजारों में तेजी से प्रेरित घरेलू शेयर बाजार सोमवार को भारी बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,240.90 अंक की तेज वृद्धि के साथ 71,941.57 अंक के स्तर पर जाकर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान यह 72,020.22 अंक के उच्च स्तर तक पहुंचा था। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 385 अंक की तेजी के साथ 21,737.60 अंक के स्तर पर जाकर बंद हुआ।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि हालिया बिकवाली और एशिया बाजारों के सकारात्मक संकेतों के चलते निवेशकों को गुणवत्ता वाले स्टाक में निवेश का अवसर मिला है। इस कारण घरेलू बाजारों में तेजी आई है। उच्च मूल्यांकन के बावजूद अंतरिम बजट के आसपास का आशावादी माहौल और हाल के वित्तीय परिणाम अनुमान के अनुरूप रहने से भी निवेशकों का भरोसा बरकरार है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की आगामी नीति बाजारों के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगी। ब्याज दरों में कटौती नहीं होने की संभावना के बीच निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व की समिति की टिप्पणियों पर होगी। एशिया में सियोल, टोक्यो और हांगकांग बढ़त में बंद हुए, जबकि शंघाई बाजार गिरावट में रहे।

छह लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति: शेयर बाजारों में रही इस तेजी की बदौलत निवेशकों की संपत्ति में 6.08 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 377.20 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इन क्षेत्रों में रही तेजी

सेंसेक्स में ऊर्जा और तेल व गैस क्षेत्र में तेजी दर्ज की गई। ऊर्जा सूचकांक में सबसे ज्यादा 5.29 प्रतिशत की तेजी रही। इसके बाद 4.94 प्रतिशत की तेजी के साथ तेल व गैस सूचकांक रहा। पावर में 3.03 प्रतिशत, सर्विसेज में 2.82 प्रतिशत, कैपिटल गुड्स में 2.13 प्रतिशत, औद्योगिक में 2.17 प्रतिशत और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.93 प्रतिशत की तेजी रही।

19 लाख करोड़ के पार रिलायंस का बाजार पूंजीकरण

दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार को करीब सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इससे कंपनी के पूंजीकरण में एक ही दिन में 1,24,591.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अब कंपनी का कुल पूंजीकरण 19,59,444.03 करोड़ रुपये हो गया है। बीते तीन सत्रों में कंपनी ने शेयरों में नौ प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है, जबकि जनवरी में अब तक कंपनी के शेयर 12 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

2023 में नए फंड आफर के जरिये 63,854 करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली, प्रेट्र: एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) ने कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कुल 212 नए फंड आफर (एनएफओ) लांच किए और इनके जरिये 63,854 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। 2022 के दौरान एएमसी ने 228 एनएफओ के जरिये 62,197 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी। मार्निंगस्टार इंडिया के डाटा के अनुसार, एनएफओ के जरिये 2021 में 99,704 करोड़ और 2020 में 53,703 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई थी। फेयर्स रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, एएमसी की ओर से जनवरी-मार्च 2023 के दौरान सबसे ज्यादा 57 एनएफओ लांच किए गए।

राष्ट्रीय फलक

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर प्रति 50 किमी में ई-वाहन के लिए होंगे चार्जिंग प्वाइंट

जासं, बांदा

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। भरतकूप व बांदा से करीब पांच हजार छोटे-बड़े वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। इलेक्ट्रिक बसें और अन्य ई-वाहन भी भविष्य में चलेंगे, उसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंपों की तरह ही चार्जिंग प्वाइंट बनाने की तैयारी की है। यूपीडा के मुताबिक चार्जिंग प्वाइंट बनाने के लिए इंडियन आयल और भारत पेट्रोलियम से अनुबंध किया जा रहा है। चार्जिंग प्वाइंट को तीन माह में चालू भी कर दिया जाएगा।

भरतकूप (चित्रकूट) से इटावा तक एक्सप्रेसवे छह पैकेज में बंटा है। सभी पैकेज में एक-एक चार्जिंग प्वाइंट बनाने की योजना है। स्थल चयन का कार्य चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पहले एक्सप्रेसवे के कट पर नीचे चार्जिंग प्वाइंट बनाने की तैयारी थी, लेकिन शासन ने अब एक्सप्रेसवे पर ही इसे बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए टोल प्लाजा पर स्थान देखा जा रहा है। यहां प्रसाधन ब्लाक में यात्री रुकते हैं। ऐसे में वह अपने वाहन चार्ज कर पाएंगे।

एक्सप्रेस वे में चार्जिंग प्वाइंट के लिए स्थल चयन के लिए सर्वे करते यूपीडा के अधिकारी।

इटावा से शुरू होकर औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट तक 296 किमी लंबे एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा संचालित राजमार्ग में बदलने के लिए यूपी सरकार ने 1700 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की है। फोरलेन एक्सप्रेसवे को एक डेडिकेटेड सर्विस लेन के अलावा दो भागों में विभाजित किया गया है। दो लेन के बीच करीब 20 मीटर के गैप में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

अजित गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर फैसले की समय सीमा 15 तक बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जुड़े राकांपा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर फैसला करने के लिए राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दी गई समयावधि सोमवार को 15 फरवरी तक बढ़ा दी। इससे पहले कोर्ट ने 30 अक्टूबर को राकांपा के शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल की ओर से दायर याचिका पर फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को 31 जनवरी तक का समय दिया था। पाटिल की याचिका में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का हिस्सा बनने के लिए पाला बदलने वाले राकांपा विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने उसी दिन नार्वेकर को निर्देश दिया था कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की की उन याचिकाओं पर भी 31 दिसंबर तक फैसला करें जिनमें दोनों ने एक-दूसरे के विधायकों को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है।

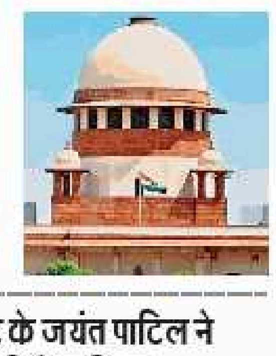

- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को पहले दिया था 31 जनवरी तक का समय
- शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने कोर्ट में दायर की है याचिका

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने विस अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों पर गौर किया कि याचिका पर आदेश पारित करने के लिए तीन और सप्ताह की जरूरत है। मेहता ने प्रतिद्वंद्वी शिवसेना गुटों द्वारा दायर याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा हाल में पारित आदेश का उल्लेख किया और कहा, प्रतिवादियों की जिरह 31 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। आदेश पारित करने के लिए उन्होंने और समय दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, स्पीकर प्रतिद्वंद्वी शिवसेना गुटों द्वारा दायर याचिकाओं के निपटारे में व्यस्त थे। राकांपा मामले में कार्यवाही वैसे समाप्त हो चुकी है। अध्यक्ष को आदेश लिखने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इस दौरान शरद पवार गुट की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अध्यक्ष को प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनके द्वारा मांगे गए तीन हफ्ते के बजाय एक सप्ताह का और समय दिया जा सकता है। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, हम विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आदेश सुनाए जाने का काम पूरा करने के लिए 15 फरवरी तक का समय देते हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को अजित पवार और उनके प्रति वफादार विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

मप्र में नामिनी नहीं बनाया तो एसडीएम पत्नी की ले ली जान

नईदुनिया, डिंडौरी

मध्य प्रदेश में डिंडौरी जिले के शहपुरा अनुविभाग में पदस्थ एसडीएम निशा नापित की रविवार को संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने बताया कि निशा की हत्या ग्वालियर निवासी उनके पति मनीष शर्मा ने की है।

दरअसल, निशा ने अपनी सर्विस बुक, बीमा व बैंक खाते में मनीष का नाम नामिनी के रूप में दर्ज नहीं कराया था, जिससे वह नाराज था। दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था। रविवार को उसने पत्नी की तकिया से मुंह व नाक दबाकर हत्या कर दी और फिर उन्हें अस्पताल लेकर पहुंच गया था। अस्पताल में उसने कहा था कि निशा के फेफड़े खराब हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच की तो मामला हत्या का निकला।

2020 में हुई थी शादी: छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर की चोपड़ा कालोनी निवासी एसडीएम निशा की 2020 में मनीष से शादी डाट काम के माध्यम से पहचान हुई थी। मंडला में पदस्थापना के दौरान तीन अक्टूबर, 2020 को गायत्री मंदिर में दोनों की शादी हुई थी।

पैसे के लिए डालता था दबाव: बड़ी बहन नीलिमा ने बताया कि शादी के बाद मनीष बीच-बीच में आता था और निशा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। कहता था कि वह बेरोजगार है और उसे पैसा चाहिए। वह नामिनी बनाने के लिए भी दबाव डालता था। परिवार वालों के समझाने के कारण निशा ऐसा नहीं कर रही थी। परेशान होकर निशा ने मंडला एसपी से शिकायत भी की थी।

- पुलिस ने शहपुरा में पदस्थ एसडीएम निशा की हत्या का किया पर्दाफाश

मनीष ने साक्ष्य छिपाने के लिए खून से सने कपड़ों को वाशिंग मशीन में धो दिया था। इसके बाद कुर्ती व अन्य कपड़ों को बंगले के परिसर में सुखा दिया था।
–मुकेश श्रीवास्तव, पुलिस उप महानिरीक्षक (बालाघाट रेंज)

अकबर को महान बताने वाले अंश पाठ्यक्रम से हटेंगे

जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाएगा। अकबर को महान बताने वाले तथ्य पाठ्यक्रम से हटाए जाएंगे। देश का आक्रांता अकबर महान कैसे हो सकता है। दिलावर ने कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में जहां भी आपत्तिजनक अंश हैं, वे हटाए जाएंगे। जैसे अकबर को महान बताना, शिवाजी को पहाड़ी चूहा बताना, चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह को आतंकी बताना। पाठ्यक्रम की समीक्षा को लेकर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार ने चुनाव से कुछ समय पहले वोट लेने के लिए कई ऐसे स्कूल खोले, जहां संसाधन ही नहीं थे।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

राजस्थान के सूरतगढ़ में महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सदा तनसीक' के दौरान भारतीय सेना और रायल सऊदी लैंड फोर्सेज के जवान। इस अभ्यास में सऊदी अरब की रायल साऊदी के 45 जवान शामिल हैं, जबकि भारत की ब्रिगेड आफ गार्डस की बटालियन हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। प्रेट्र

गुजरात में साइबर पुलिस ने फर्जी शिकायत दर्ज कर करोड़ों वसूले

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

आनलाइन गेम खेलने के मामले में ईडी का भय दिखाकर गुजरात के जूनागढ़ की साइबर पुलिस के तीन अफसरों ने केरल के व्यापारी से बैंक खाता अनफ्रीज करने के बदले में 20 से 25 लाख रुपये मांग लिए। इस मामले में इन पुलिस अधिकारियों को आरोपित बनाया गया है। इन पुलिसकर्मियों ने 335 खाते अनफ्रीज कर रखे थे। प्रत्येक खाते को अनफ्रीज करने के बदले में 20 से 25 लाख रुपये की मांग की थी। फरार आरोपितों द्वारा करोड़ों रुपयों की वसूली की आशंका है। दो के विदेश भागने की आशंका है। पुलिस विभाग ने तीनों आरोपितों को निलंबित कर दिया है।

- साइबर सेल के तीन अधिकारी निलंबित, एफआइआर दर्ज होने के बाद हुए फरार

पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने इसकी जांच एटीएस को सौंप दी है। साइबर सेल में कार्यरत पुलिस निरीक्षक तरल भट्ट, अरविंद गोहिल व उपनिरीक्षक दीपक जानी के खिलाफ जूनागढ़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के पीआइ एसएन गोहिल ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। साइबर सेल ने अकाउंट अनफ्रीज होने के मामले में शिकायत व पूछताछ के लिए हेल्पलाइन शुरू की है।

केरल निवासी कार्तिक भंडारी को 17 नवंबर 2023 को बैंक से पता चला कि उसका खाता गुजरात साइबर सेल ने फ्रीज किया है। भंडारी अपने रिश्तेदार के साथ जूनागढ़ में साइबर सेल के दफ्तर पहुंचे। यहां उपनिरीक्षक जानी ने अपने अधिकारी भट्ट व गोहिल के नाराज होने की बात बताते हुए कहा, आनलाइन गेम खेलने व खाते से अवैध लेन-देन के कारण ऐसा किया गया है। फर्जी इनपुट के आधार पर फ्रीज हुआ खाता अनफ्रीज करने के बदले में 20 से 25 लाख रुपये चाहिए। भंडारी चार लाख रुपये देने को तैयार हो गए पर आरोपित पुलिसकर्मी ईडी व दिल्ली पुलिस का डर बताते हुए मोटी रकम देने का दबाव बनाने लगे। भंडारी ने इसकी शिकायत जूनागढ़ रेंज पुलिस महानिरीक्षक नीलेश जाजडिया से की तो उन्होंने विभागीय जांच कराई।

****

बंधक समझौते पर हमास से वार्ता सकारात्मक : अमेरिका

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जान किर्बी बोले, अभी काम बाकी, एक और समझौते की बन रही रूपरेखा

इजरायल ने रचनात्मक बताया, लेकिन कहा कि महत्वपूर्ण अंतर बने हुए हैं

वाशिंगटन, रायटर : व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वार्ता सकारात्मक व आशाजनक थी। हालांकि, अब भी बहुत काम बाकी है। सीआइए निदेशक विलियम बर्न्स और अमेरिका के पश्चिम एशिया के दूत ब्रेट मैकगर्क की बातचीत बंधकों की रिहाई के साथ-साथ गाजा में हो रहे युद्ध के बीच मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए विराम सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। बर्न्स ने रविवार को मोसाद खुफिया सेवा के प्रमुख और कतर के प्रधानमंत्री के साथ-साथ मिस्र के खुफिया प्रमुख से मुलाकात की।

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जान किर्बी ने कहा,मुझे लगता है कि वार्ता को सकारात्मक बताना उचित है। हमें लगता है कि एक और बंधक समझौते के लिए रूपरेखा तैयार हो रही है। यह वास्तव में अधिक बंधकों को बाहर निकालने व हिंसा को कम करने में सहायक हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हमास की ओर से बंदी बनाए गए 100 से अधिक बंधकों की रिहाई को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर, मिस्र व इजरायलियों के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हम अभी अंतिम पड़ाव पर नहीं हैं, लेकिन चर्चाओं के बारे में अच्छा महसूस करते हैं।

इजरायल बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमत : इजरायल ने कहा है कि युद्धविराम व बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर अभी भी कमियां हैं। इस बातचीत को इसी सप्ताह फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। हमास ने बंधकों की रिहाई की शर्त के रूप में युद्ध को समाप्त करने और सभी आइडीएफ बलों की वापसी की मांग की है। इजरायल ने इन मांगों को खारिज कर दिया है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जुहरी ने कहा,पेरिस बैठक की सफलता गाजा पट्टी पर आक्रामकता समाप्त करने पर इजरायल की सहमति पर निर्भर है।

इजरायल के केरम शालोम में सोमवार को हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों व समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बंधकों की रिहाई होने तक गाजा पट्टी इलाके में मानवीय आधार पर दी जाने वाली सहायता सामग्री की आपूर्ति पर रोक लगाई जाए। रायटर

हाउती विद्रोहियों का दावा, अमेरिकी युद्धपोत पर किया हमला किया

यरुशलम, एपी : यमन के हाउती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने सोमवार को अदन की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के मोबाइल बेस पर हमला किया। ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा, उसने यूएसएस लुईस बी पुलर पर मिसाइल दागी। इस दावे को अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने खारिज कर दिया है। हाउती विद्रोहियों ने दावे में कहा कि हमला पुलर को निशाना बनाकर किया गया, यह जहाज फ्लोटिंग लैंडिंग बेस के रूप में कार्य करता है। लाल सागर व अदन की खाड़ी के माध्यम से वाणिज्यिक शिपिंग पर हाउती हमलों को कम करने के अमेरिकी प्रयासों के तहत पुलर को पहले अरब सागर में तैनात किया गया था।

गाजा के मुख्य उत्तरी शहर पर दोबारा हमला : इजरायल ने रविवार रात गाजा के मुख्य उत्तरी शहर पर फिर से कार्रवाई की। गाजा के आसपास के इलाकों में हवाई हमलों में कई लोग मारे गए और घायल हो गए। टैंकों ने शहर के पूर्वी क्षेत्रों में गोलाबारी की, नौसेना ने पश्चिम में समुद्र तट के इलाकों में गोले दागे गए हैं। वहीं, गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों को रोकने के बाद इजरायल व मिस्र के बीच नित्जाना सीमा पर चार लोगों को हिरासत में लिया गया।

इजरायल का दावा, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में 190 कर्मचारी हमास के थे : इजरायल के दावे के बाद कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र फलस्तीनी सहायता एजेंसी की फंडिंग रोक दी है। इन पर सात अक्टूबर को इजरायल पर हमले का आरोप है। हालांकि अब यह आरोप लगाया गया है कि शिक्षकों सहित लगभग 190 यूएनआरडब्ल्यूए एजेंसी के कर्मचारी हमास या इस्लामिक आतंकियों के रूप में कार्य कर रहे थे। यूएनआरडब्ल्यूए के यहां 13,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वह इस बात की समीक्षा करेगा कि शरणार्थी एजेंसी को सहायता जारी रखी जाए या नहीं।

जेनिन शरणार्थी शिविर में विस्फोटकों से भरी सुरंग का पता चला : इजरायली सुरक्षा बलों ने जेनिन शरणार्थी शिविर में विस्फोटकों से भरी सुरंग का पता लगाया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में 19 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है।

ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े चार लोगों को फांसी

तेहरान, एपी : ईरान ने सोमवार को चार व्यक्तियों को फांसी दे दी। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चारों को तोड़फोड़ की योजना बनाने और इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ संबंधों का दोषी करार दिया गया था।सरकारी आइआरएनए समाचार एजेंसी ने कहा है कि चारों व्यक्तियों को 2022 में ईरान के रक्षा मंत्रालय से संबंधित सेंट्रल सिटी इसफहान में मिसाइल और रक्षा उपकरण कारखाने को निशाना बनाने के षड्यंत्र में संलिप्त रहने का दोषी ठहराया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह षड्यंत्र कथित तौर पर मोसाद द्वारा तैयार किया गया था और ईरान आने से पहले चारों को एक अफ्रीकी देश में इजरायली एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। चारों व्यक्तियों की पहचान ईरानी नागरिक मोहम्मद फरामरजी, मोसिन मजलूम, वफा अजरबार और पेजमान फतेही के रूप में की गई है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने चारों को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा जिसके बाद उन्हें फांसी दी गई। मौत की सजा कैसे दी गई यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ईरान में ऐसे दोषियों को आम तौर पर फांसी दी जाती है।

भारतीयों के लिए अमेरिका ने रिकार्ड वीजा जारी किए

- पिछले साल भारत में 14 लाख अमेरिकी वीजा जारी किए गए
- विश्व में हर दस अमेरिकी वीजा आवेदनों में एक भारतीय का

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत में अमेरिकी काउंसलर टीम ने पिछले साल 2023 में रिकार्ड 14 लाख अमेरिकी वीजा जारी कराए हैं। भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा जारी करने की यह अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। साथ ही, विजिटर वीजा अप्वाइंटमेंट के लिए इंतजार करने के समय में भी 75 प्रतिशत की कमी आई है। भारत में अमेरिकी दूतावास और कांसुलेट का कहना है कि विश्व भर में हर दस अमेरिकी वीजा आवेदनों में से एक भारतीय का होता है।

बयान जारी कर कहा गया कि वर्ष 2023 में भारत में अमेरिकी दूतावास और कांसुलेट ने रिकार्ड तोड़ 14 लाख अमेरिकी वीजा जारी किए हैं। सभी वर्गों में वीजा की मांग अप्रत्याशित रही। 2022 के मुकाबले पिछले साल 60 प्रतिशत अधिक आवेदन आए। अब विश्व भर में हर दस अमेरिकी वीजा के आवेदन में एक भारतीय का होता है। विजिटर वीजा (बी-1/बी-2) बढ़कर अमेरिकी मिशन के इतिहास में दूसरा सबसे अधिक आवेदन हो गया है। यानी पिछले साल भारतीयों के सात लाख से अधिक विजिटर वीजा आवेदन आए थे। वीजा प्रक्रिया में सुधार और स्टाफ बढ़ाए जाने से विजिटर वीजा के इंटरव्यू का इंतजार भी एक हजार से दिन से घटकर 250 दिन ही रह गया है। यह देश में वीजा एप्वाइंटमेंट के लिए सभी विधाओं में सबसे कम समय है। इसके अलावा, भारत में काउंसलर टीम ने चेन्नई और हैदराबाद में वीजा प्रक्रिया को विशेष रूप से गति प्रदान की है। इससे पिछले साल भारतीयों और उनके स्वजनों को 3,80,000 रोजगार वीजा जारी किए गए।

एक अन्य घटनाक्रम में, स साल एच1बी वीजा धारकों को अमेरिका में ही अपने वीजा को रिन्यू कराने की छूट दी जाएगी। वहीं, मुंबई कांसुलेट जनरल ने महामारी के समय से लंबित 31 हजार आव्रजन वीजा के मामलों का भी निपटारा किया है। वीजा प्रक्रिया की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हैदराबाद में 340 मिलियन डालर की लागत से एक नया केंद्र पिछले साल मार्च में खोला गया है।

सूडान और दक्षिण सूडान के विवादित सीमा पर हिंसा में 54 की मौत

जूबा, रायटर : सूडान के साथ लगे दक्षिण सूडान की सीमा पर हुए हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 54 लोग मारे गए। इसे 2021 के बाद से सीमा विवाद से संबंधित हमलों की सबसे घातक घटना मानी जा रही है।

अबेई के सूचना मंत्री बुलिस कोच ने कहा, दक्षिण सूडान के वॉरैप राज्य के सशस्त्र युवाओं ने पड़ोसी अबेई क्षेत्र में छापे मारे। अबेई एक तेल समृद्ध क्षेत्र है, जिसे दक्षिण सूडान व सूडान द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है, दोनों ने इस पर अपना दावा जताया है। कोच ने कहा, शनिवार को हुए हमलों में महिलाओं, बच्चों व पुलिस कर्मियों सहित 52 लोग मारे गए और 64 घायल हो गए। उन्होंने कहा, मौजूदा गंभीर सुरक्षा स्थिति के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। अबेई ने रविवार को कहा, हिंसा के बीच एगोक शहर में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (यूनिस्फा) के अड्डे पर हुए हमले में घाना के एक शांतिरक्षक की मौत हो गई, एक अन्य शांतिरक्षक भी मारा गया है।

अमेरिका में हरियाणा के छात्र की बेरहमी से हत्या

- नशेड़ी ने सिर पर किए हथौड़े से 50 वार, कैमरे में कैद हुई घटना
- बीटेक करने के बाद एमबीए की पढ़ाई करने अमेरिका पहुंचा था विवेक

न्यूयार्क, प्रेट्र : अमेरिका के जार्जिया राज्य के लिथोनिया शहर में एक बेघर नशेड़ी ने एमबीए के भारतीय छात्र विवेक सैनी की हत्या कर दी। बीटेक की पढ़ाई कर अमेरिका गए विवेक हरियाणा में पंचकुला के भगवानपुर गांव के रहने वाले थे। हत्यारे ने अपने मददगार 25 वर्षीय विवेक के सिर पर हथौड़े से 50 बार वार किए। कैमरे में कैद हो गई इस दिल दहला देने वाली घटना में हमलावर जूलियन फाकनर को एमबीए के छात्र विवेक के सिर पर वार करते देखा जा सकता है।

विवेक एक स्टोर में पार्ट टाइम क्लर्क था। विवेक ने फाकनर को इसी स्टोर में शरण दी थी। एम9 न्यूज चैनल ने रविवार को रिपोर्ट में बताया कि विवेक ने फाकनर के प्रति करीब दो दिन तक दया दिखाई और उसे चिप्स, कोक, पानी और ठंड से बचने के लिए जैकेट भी दी थी। 16 जनवरी को विवेक ने फाकनर को मुफ्त में खाने की चीजें देने से मना कर दिया। उसने फाकनर से जाने और ऐसा नहीं करने पर पुलिस की मदद लेने की बात कही। इस पर वह भड़क गया और हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फाकनर को विवेक के शव के पास खड़ा पाया। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दो वर्ष पहले अमेरिका आए विवेक ने हाल ही में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वदेश लौटने से 10 पहले उसकी हत्या हो गई। उसके पिता गुरजीत सिंह और मां ललिता सैनी इस त्रासद घटना के बारे में किसी के साथ बात करने की स्थिति में नहीं हैं।

ईरान से व्यापक युद्ध नहीं चाहता अमेरिका : व्हाइट हाउस

- राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, अमेरिका इस हमले का जवाब देगा
- सात अक्टूबर के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 150 हमले हो चुके

वाशिंगटन, रायटर : व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ या क्षेत्र में व्यापक युद्ध नहीं चाहता। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि जार्डन में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए एक ड्रोन जिम्मेदार था। वहीं, जार्डन मामले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। बाइडन ने साउथ कैरोलिना में कहा कि पश्चिम एशिया में हमारे लिए पिछली रात काफी कठिन गुजरी। हमने अपने तीन बहादुर सैनिकों को खो दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने चुने गए तरीके और समय के हिसाब से उन्हें जवाबदेह ठहराएगा।

इस बीच पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से अपने ठिकानों को खाली कर दूसरी जगह जाने की बात सामने आ रही है। उन्हें भय है कि अमेरिका हवाई हमले कर उन्हें निशाना बनाएगा। ये क्षेत्र मयादीन और बौकामल के गढ़ हैं। उल्लेखनीय है कि सात अक्टूबर के बाद गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से अमेरिकी सेना पर हमले बढ़ गए हैं।

ये समूह इजरायल सेना द्वारा गाजा परि किए जा रहे हमलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सैनिकों पर 150 से अधिक हमले किए हैं। पहला बड़ा हमला 18 अक्टूबर को इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर बोला गया था। इसके बाद लगातार हमले जारी हैं।

आतंकी समूह ने रविवार को किए गए घातक हमले से पहले 20 जनवरी को बड़ा हमला बोला था। इसमें ईरान के मिलिशिया समूह ने इराक में मौजूद अमेरिकी हवाई बेस पर कई मिसाइलें दागी थीं।

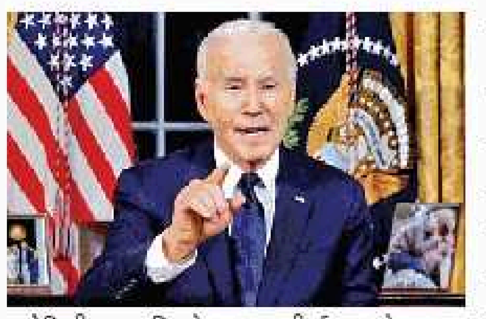

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ईरान को चेतावनी। रायटर

सुनक ने ईरान से पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील की

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को कहा कि वह पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सीरिया सीमा के पास पूर्वोत्तर जार्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के बाद ईरान से तनाव कम करने का आग्रह किया है। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन ड्रोन हमलों की निंदा करता है। सुनक ने कहा कि हम क्षेत्र में स्थिरता और शांति के लिए अपने सहयोगियों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं।

जार्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले में हमारा हाथ नहीं : ईरान

तेहरान, एएनआइ : जार्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय का कहना है कि हमले में तेहरान का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि संघर्षरत समूह अपने खुद के सिद्धांत और प्राथमिकता के आधार पर फैसला लेते हैं। वह फलस्तीन और वहां के लोगों का किस तरह समर्थन करेंगे यह फैसला उनका अपना है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे लेकर चेताया है कि कुछ पश्चिमी अधिकारियों की ओर से दिए गए बयान और उठाए गए कदम क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समूह की कार्रवाई युद्ध अपराध के खिलाफ जवाब है। वह ईरान सरकार की ओर से आदेश प्राप्त नहीं करते, बल्कि अपने खुद निर्णय लेते हैं।

भारतीय युद्धपोत ने अपहृत जहाज व चालक दल को सुरक्षित छुड़वाया

- ईरानी झंडे लगे मछली पकड़ने वाले जहाज पर चढ़ गए थे समुद्री लुटेरे
- चालक दल को बंधक बना लिया था, आइएनएस सुमित्रा ने की कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने ईरान के झंडे वाले एक जहाज की ओर से मिली अपहरण की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहृत जहाज और उसके चालक दल के सभी 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़वा लिया।

नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि सोमालिया के पूर्वी तटों और अदन की खाड़ी में जलदस्यु रोधी अभियानों के लिए तैनात भारतीय युद्धपोत आइएनएस सुमित्रा ने ईरान के झंडे लगे मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान के अपहरण के संबंध में सूचना पर तत्काल कार्रवाई की। जहाज पर समुद्री लुटेरे चढ़ गए थे और उन्होंने चालक दल को बंधक बना लिया गया था। उन्होंने बताया कि आइएनएस सुमित्रा ने जहाज को रोका और समुद्री लुटेरों को चालक दल तथा जहाज की सुरक्षित रिहाई के लिए बाध्य किया। इस दौरान निर्धारित एसओपी का पालन किया गया। मधवाल ने बताया कि जहाज और चालक दल के सभी 17 सदस्यों को सफलतापूर्वक मुक्त कराया गया। इस दौरान समुद्री लुटेरों को निहत्था कर दिया गया और उन्हें सोमालिया की ओर जाने को कहा गया। इसके बाद जहाज की सफाई की गई और फिर वह अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया। प्रवक्ता ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में जलदस्यु रोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती समुद्र में सभी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना के दृढ़संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में अग्रिम पंक्ति के और पोत तैनात करके अपने निगरानी तंत्र को काफी बढ़ा दिया है।

सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में ईरान का झंडा लगा मछली पकड़ने वाला जहाज ईमान, जिसे भारतीय नौसेना ने अपहर्ताओं से छुड़वाया। एएफपी

ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में तलवारें लहराकर श्रद्धालुओं को दी गई धमकी

ओटावा, प्रेट्र : कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के पेंटिक्टन शहर में सोमवार शाम एक गुरुद्वारे में तलवारें लहराकर श्रद्धालुओं को धमकी दी गई। कनाडा के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

रायल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 वर्षीय व्यक्ति ने आक्रामक तरीके से दो बड़े हथियार लहराते हुए कथित तौर पर श्रद्धालुओं को धमकी दी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। मामले की जांच जारी है।

गुरुद्वारे ने घटना के बारे में बयान जारी कर कहा कि आरोपित उस समूह के सदस्य है जिस पर हाल ही में निर्वाचित समिति ने प्रतिबंध लगा दिया था। पेंटिक्टन गुरुद्वारा सोसाइटी के जेसी गार्चा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो।

पाकिस्तान-ईरान सीमा पर आतंकियों को है तीसरे देश का समर्थन : ईरान

- इसी महीने सैन्य हमले से उत्पन्न तनाव कम करने इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री
- दोनों देश अपने क्षेत्रों में आतंकवाद का मुकाबला करने को परस्पर सुरक्षा सहयोग को राजी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : तालिबान शासित अफगानिस्तान की ओर इशारा करते हुए ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सोमवार को कहा, इसमें 'संदेह नहीं' कि पाकिस्तान व ईरान के सीमांत क्षेत्रों में मौजूद आतंकियों को तीसरे देशों का समर्थन प्राप्त है। कुछ दिन पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। अब्दुल्लाहियान इस माह के शुरू में किए गए मिसाइल हमले के बाद उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए रविवार देर रात पाकिस्तान पहुंचे।

पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अब्दुल्लाहियान ने किसी देश का नाम नहीं लेते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान के साझा सीमावर्ती क्षेत्रों एवं उनके अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद आतंकियों को तीसरे देशों का नेतृत्व एवं समर्थन प्राप्त है। जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों देश विदेश मंत्रियों के स्तर पर उच्च स्तरीय सकारात्मक प्रणाली की स्थापना पर सहमत हुए हैं। दोनों देश अपने क्षेत्रों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए परस्पर सुरक्षा सहयोग करेंगे।

अब्दुल्लाहियान की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब ईरान और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष होते-होते रह गया। ईरान ने पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र पंजगुर में आतंकियों के कथित ठिकानों पर एकतरफा हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसी ही कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद ईरान ने दोबारा ऐसा नहीं किया और स्थिति संभल गई।

इस्लामाबाद में सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी। रायटर

मालदीव : 56 वोटों के साथ लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग

प्रथम पृष्ठ से आगे

मालदीव में विपक्षी एमडीपी के पास 45 सांसद व सहयोगी दल डेमोक्रेट के पास 13 सांसद हैं। मालदीव के संविधान के अनुसार, 56 वोटों के साथ राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने स्पीकर मोहम्मद असलाम और डिप्टी स्पीकर अहमद सलीम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अर्जी लगाई है।

केवल एक मंत्री को मंजूरी : सोमवार को संसद ने आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामी मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और अटर्नी जनरल अहमद उशाम की नियुक्ति को नकार दिया और वित्त मंत्री मोहम्मद सईद को मामूली अंतर से मंजूरी दे दी है। मतदान में विपक्षी एमडीपी- डेमोक्रेट के सदस्यों ने व्हिप जारी कर हैदर को 46-24, उशाम को 44-24 व शहीम को 31-30 वोटों से खारिज किया। हालांकि सईद को 37-32 मतों से मंजूरी मिल गई। कैबिनेट के 18 अन्य सदस्यों को भी मंजूरी मिल गई है जिसमें चीन समर्थक रक्षा मंत्री मोहम्मद घास्सन मौमून व गृह मंत्री अली हुसान भी शामिल हैं।

विदेश सचिव क्वात्रा ने भूटान के नए पीएम से भेंट की; द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

- नई सरकार गठन के बाद भारतीय की पहली उच्च स्तरीय यात्रा
- विकास साझेदारी, अंतरिक्ष, ऊर्जा और व्यापार पर हुई बातचीत

थिंपू, प्रेट्र: विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को भूटान के नए प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। इस दौरान भूटान के साथ भारत के संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक हित और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता तोब्गे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा पर क्वात्रा भूटान पहुंचे हैं। क्वात्रा ने ग्यालयोंग त्शोगखांग में प्रधानमंत्री कार्यालय में तोब्गे से भेंट की।

द भूटानी अखबार के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर विदेश सचिव और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए रात्रिभोज का भी आयोजन किया। क्वात्रा ने भूटान के विदेश सचिव औम पेमा चोडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी किया। यहां भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया कि विकास साझेदारी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंधों और लोगों से लोगों के संबंधों में भारत और भूटान के बीच सहयोग पर व्यापक चर्चा हुई। क्वात्रा की यात्रा उस समय में हो रही है जब चीन और भूटान अपने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान पर विचार कर रहे हैं, जिसका भारत के सुरक्षा हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है। इससे दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान, क्वात्रा भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे।

त्शेरिंग तोब्गे को भूटान का पीएम बनने पर बधाई : भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भूटान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की और प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए भारतीय नेतृत्व की ओर से उन्हें बधाई दी।

भारतीय नागरिक ने अमेरिका में ड्रग कारोबार का दोष स्वीकार किया

न्यूयार्क, प्रेट्र : ब्रिटेन से प्रत्यर्पित 40 वर्षीय भारतीय बनमीत सिंह ने अमेरिका में ड्रग्स बेचने का दोष स्वीकार किया है। साथ ही 15 करोड़ क्रिप्टोकरेंसी की धोखाधड़ी का आरोप भी स्वीकार किया है। उत्तराखंड के हलद्वानी निवासी बनमीत ने फेंटेनाइल, एलएसडी, जैनेक्स, केटामाइन व ट्रामाडोल जैसे प्रतिबंधित मादक पदार्थों को बेचने के लिए डार्क वेब पर मार्केटिंग वेबसाइटें बनाईं। इनके माध्यम से उपभोक्ता बनमीत को आर्डर देते थे। उसके बाद बनमीत उसे व्यक्तिगत या यूएस मेल या अन्य शिपिंग सेवाओं के माध्यम से यूरोप से अमेरिका भेजने की व्यवस्था करता था।

न्याय विभाग के अटार्नी जनरल निकोल एम अर्जेंटीना ने कहा, 'बनमीत व उसके जैसे तस्कर सोचते हैं कि वे डार्क वेब पर गुमनाम तरीके से काम कर सकते हैं।' अप्रैल 2019 में बनमीत को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और 2023 में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। उसे आठ वर्ष जेल की सजा भुगतनी होगी।

****

पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले कराची में चुनावी हिंसा बढ़ी

कराची में आम चुनाव से पहले रैली के दौरान पुलिस और इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ (पीटीआइ) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कार्यकताओं के हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। रायटर

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले देश के सबसे बड़े शहर कराची में चुनावी हिंसा बढ़ गई है। सोमवार को नाजिमानाड में हुई हिंसक झड़प के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कार्यकर्ताओं के साथ हुई गोलीबारी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम पाकिस्तान) के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

क्लिफ्टन इलाके में रविवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की एक चुनावी रैली के दौरान संघर्ष में कुछ पुलिसकर्मियों समेत 25 लोग घायल हो गए।

आयोग ने 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया : पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने देश में 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों को संवेदनशील या अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, आठ फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 90,675 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 10 और लोगों का किया अपहरण

बलूचिस्तान, एएनआइ : पाकिस्तानी उत्पीड़न के विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहने के दौरान बलूचिस्तान के डेरा बुगती क्षेत्र से 10 लोग लापता हो गए हैं। बलूचिस्तान पोस्ट ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने डेरा बुगती के सुइ कस्बे में घरों में तलाशी अभियान चलाया और 10 लोगों का अपहरण कर लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी) मेंगल के अध्यक्ष सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, वे (सरकार) कहते हैं कि लापता लोग अफगानिस्तान में हैं, पर सरकारी मशीनरी अपहरण के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

जफर कालोनी में पाकिस्तानी बलों की छापेमारी के बाद जीटीए के जिला अध्यक्ष व जम्हूरी वतन पार्टी के कार्यकर्ता मास्टर गौस बख्श लापता हैं। मास्टर गौस मिरान बख्श बुगती के बेटे हैं। इसी तरह हाजी बुगती के बेटे रहीम दाद, स्वाली बुगती के बेटे रहीम दाद का भी अपहरण कर लिया गया। दोनों सुइ तहसील बाजार के मुसा होटल में बैठे थे।

दैनिक जागरण
इंग्लिश चुनौती
मंगलवार 30 जनवरी, 2024 www.jagran.com

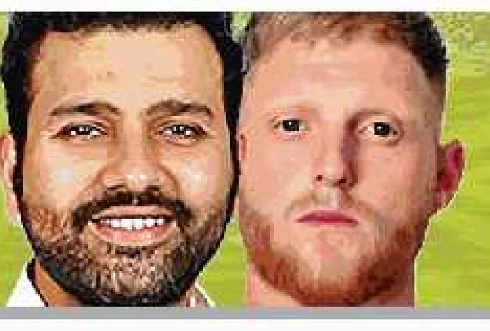

पहले टेस्ट में हार भारत के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि इंग्लैंड ने दिखा दिया है कि बैजबाल यहां भी असरदार है। इससे साबित होता है कि इंग्लैंड के पास गजब का आत्मविश्वास है। उन्हें अपने खेलने के तरीके पर भरोसा है।
- नासिर हुसैन, पूर्व कप्तान, इंग्लैंड

जडेजा-राहुल बाहर, सरफराज और सौरभ को बुलावा

वाशिंगटन सुंदर भी भारतीय टीम में, पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दो फरवरी से विशाखापत्तनम में खेला जाएगा

नई दिल्ली, जेएनएन : हैदराबाद में इंग्लैंड के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा है। बल्लेबाज केएल राहुल और आलराउंडर रवींद्र जडेजा विशाखापत्तनम में दो फरवरी से होने वाले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। जडेजा को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जबकि राहुल की दाईं जांघ में दर्द है। चयन समिति ने दूसरे टेस्ट के लिए भारत 'ए' के लिए खेल रहे मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान और बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार के साथ आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को टीम में सम्मिलित किया है।

बीसीसीआइ ने सोमवार को बताया, रवींद्र जडेजा और लोकेश राहुल इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाले दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआइ की मेडिकल टीम दोनों खिलाड़ियों की प्रगति पर नजर रख रही है। पहले टेस्ट में 28 रन की हार के बाद भारत पांच मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रहा है। विराट कोहली के पहले दो टेस्ट में उपलब्ध नहीं होने के बाद अब केएल और जडेजा का बाहर होना टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। पहले टेस्ट में केएल राहुल और जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जडेजा ने पहली पारी में पांच विकेट लेने के साथ ही 87 रन भी बनाए थे, जबकि राहुल ने 86 रन बनाए थे। बतौर आलराउंडर जडेजा भारतीय टीम के लिए काफी महत्व रखते हैं। अब उनकी अनुपस्थिति में वाशिंगटन सुंदर को अंतिम एकादश में उतारा जा सकता है, जिन्होंने इंग्लैंड लायंस के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं, चोट से उबरकर एशिया कप में वापसी करने के बाद से राहुल ने भी वनडे और टेस्ट में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है।

सरफराज को टीम में शामिल करना अच्छा निर्णय है क्योंकि लंबे समय से उन्हें इस अवसर का इंतजार था। वह मुंबई के लिए पिछले तीन सत्र में लगातार रन बना रहे हैं। इंग्लैंड लायंस के विरुद्ध भी उन्होंने 161 रन बनाए थे। यह मैच भारत 'ए' पारी और 16 रन से जीता था।

विशाखापत्तनम में रजत पाटीदार को टेस्ट पदार्पण का अवसर मिल सकता है, जो विराट के विकल्प के तौर पर टीम के साथ हैं। बीसीसीआइ के अनुसार, तेज गेंदबाज आवेश खान अभी मध्य प्रदेश रणजी टीम के साथ बने रहेंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें टीम में सम्मिलित किया जाएगा।

रवींद्र जडेजा और केएल राहुल • फाइल फोटो, एपी

डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में पाचवें स्थान पर खिसका भारत

दुबई, प्रेट्र : इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में मिली हार के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) रैंकिंग में खिसककर पांचवें स्थान पर खिसक गया है। द. अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रहने के बाद भारत इस तालिका में शीर्ष पर था, लेकिन पाकिस्तान को हराकर आस्ट्रेलिया शिखर पर पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद भारत के 54.16 रैंकिंग अंक थे जो अब घटकर 43.33 हो गए हैं। आस्ट्रेलिया 55 अंक के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज के हाथों रविवार को आठ रन से मिली हार का भी उसकी रैंकिंग पर असर नहीं हुआ है।

दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम : रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन, यशस्वी, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, ध्रुव जुरैल, अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, रजत पाटीदार, सरफराज खान, सुंदर, सौरभ कुमार।

डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	ड्रा	अंक	पीसीटी
आस्ट्रेलिया	10	6	3	1	66	55
द. अफ्रीका	2	1	1	0	12	50
न्यूजीलैंड	2	1	1	0	12	50
बांग्लादेश	2	1	1	0	12	50
भारत	5	2	2	1	26	43.33
पाकिस्तान	5	2	3	0	22	36.66
वेस्टइंडीज	4	1	2	1	16	33.33
इंग्लैंड	6	3	2	1	21	29.16
श्रीलंका	2	0	2	0	0	0

ओली पोप का रास्ता रोकने पर बुमराह को फटकार

दुबई : तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हैदराबाद टेस्ट के दौरान रन लेते समय इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप के रास्ते में आने और उसकी वजह से अनुचित शारीरिक संपर्क के कारण फटकार और एक डिमेरिट अंक लगाया गया है। बुमराह का अपराध आइसीसी आचार संहिता के तहत लेवल एक का अपराध है। 24 महीने में यह उनका पहला अपराध है। यह घटना इंग्लैंड की दूसरी पारी के 81वें ओवर की है जब बुमराह जानबूझकर पोप के रास्ते में आ गए जब वह रन ले रहे थे जिससे अनुचित शारीरिक संपर्क भी हुआ। बुमराह ने सजा स्वीकार कर ली जिससे मामले की औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

घरेलू क्रिकेट की 'रन मशीन' को आखिरकार मिला मौका

नई दिल्ली, जेएनएन : घरेलू क्रिकेट में मुंबई की 'रन मशीन' कहे जाने वाले सरफराज खान को चयनकर्ताओं ने लंबे समय तक नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार मौका देना ही पड़ा। विराट कोहली ने जब शुरुआत दो टेस्ट मैचों से हटने का निर्णय लिया था तो उनके विकल्प के तौर पर सरफराज और रजत पाटीदार का नाम सबसे पहले आया था, लेकिन चयनकर्ताओं ने पाटीदार को चुना। इसके बाद सरफराज ने इंग्लैंड लायंस के विरुद्ध भारत ए की ओर से शतक ठोकते हुए 161 रन की पारी खेली और एक बार फिर चयनकर्ताओं के सामने दावा ठोका। अब केएल राहुल के चोटिल होने पर उन्हें टीम में जगह मिली है।

सरफराज खान • फाइल फोटो, एक्स

सरफराज काफी वक्त से मुंबई टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। रणजी ट्राफी में उनके नाम तिहरा शतक भी है। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 45 मैचों की 66 पारियों में 3912 रन बना चुके हैं। इसमें 14 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका औसत 69.85 का है। इसके अलावा लिस्ट ए में 37 मैचों में उनके नाम 629 रन हैं। एक वक्त फिटनेस के कारण आलोचना झेलने वाले सरफराज खान ने लगातार बल्ले से दमदार प्रदर्शन जारी रखा और हार नहीं मानी। 2022-23 के सीजन में सरफराज ने छह मैच में 92.66 की औसत से 556 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। 2021-22 के सीजन में छह मैच में उन्होंने 122.75 की औसत से 982 रन बनाए, जिसमें चार शतक शामिल हैं। 2019-20 के सीजन में मुंबई के लिए सरफराज ने छह मैच में 154.66 की शानदार औसत से 928 रन बनाए जिसमें तीन शतक थे। तीन घरेलू सीजन में उनके 2466 रन हैं, जो शानदार रिकार्ड है। पिछले तीन सीजन में उनके अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जिसने ऐसा कुछ कारनामा किया हो।

2021 में भारत के नेट गेंदबाज थे सौरभ : वहीं, उत्तर प्रदेश के स्पिनर सौरभ को भी टीम में जगह दी गई। 2021 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी तो सौरभ भारत के नेट गेंदबाज थे। अपने चयन पर सौरभ ने कहा कि मैंने हमेशा ही भारत टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा है।

एक नजर में

भारतीय पुरुष हाकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची

मस्कट : मनिंदर सिंह के चार गोल की मदद से भारतीय पुरुष हाकी टीम ने सोमवार को जमैका को 13-0 से रौंदकर एफआइएच हाकी-5 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मनिंदर के अलावा मंजीत ने दो, रहील मोहम्मद ने दो, मंदीप मोर ने दो जबकि उत्तम सिंह, राजभर पवन और गुरजोत सिंह ने एक-एक गोल दागा। भारत ने इससे पहले पूल बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड को हराया था, जबकि मिस्र के विरुद्ध उसे हार मिली थी। (प्रेट्र)

विश्व कप में निशानेबाज सोनम ने जीता रजत पदक

काहिरा : आइएसएसएफ विश्व कप में पदार्पण कर रही युवा निशानेबाज सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। फाइनल में सोनम ने 252.1 अंक अर्जित किए और जर्मनी की एना जानसेन के बाद दूसरे स्थान पर रहीं। स्पर्धा का कांस्य पदक पोलैंड की एनेता स्टाकिविज ने जीता। इससे पहले, दिग्विजय सिंह पंवार ने विश्व रिकार्ड के साथ पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। (प्रेट्र)

प्राइम वालीबाल लीग का तीसरा सीजन 15 से

नई दिल्ली : रुपे प्राइम वालीबाल लीग का तीसरा सीजन की शुरुआत चेन्नई में 15 फरवरी से होगी। पहला मैच गत चैंपियन अहमदाबाद डिफेंडर्स और चेन्नई ब्लिट्ज के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 21 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में अहमदाबाद और चेन्नई के अलावा अन्य टीमें बेंगलुरु टारपीडो, कालीकट हीरोज, दिल्ली तूफान, हैदराबाद ब्लैक हाक्स, कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स, कोलकाता थंडरबोल्ट्स और मुंबई मेटियर्स हैं। लीग का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। (जेएनएन)

तीक्ष्णा-सैम्स के दम पर जीता शारजाह वारियर्स

क्रिकेट डायरी

नई दिल्ली, जेएनएन : महेश तीक्ष्णा और डेनियल सैम्स की अद्भुत गेंदबाजी के दम पर शारजाह वारियर्स ने दुबई कैपिटल्स के विरुद्ध एकतरफा जीत प्राप्त की। आइएलटी-20 के मैच में दुबई कैपिटल्स की टीम टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 104 रन पर ही सिमट गई। जवाब में, शारजाह वारियर्स की टीम ने केवल 13.1 ओवर में एक विकेट पर 105 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। टीम के लिए जानसन चार्ल्स ने अविजित 43 रन और डिकवेला ने 37 रन बनाए।

तीक्ष्णा को मिला सैम्स का साथ : इससे पहले, बल्लेबाजी करते हुए दुबई कैपिटल्स की टीम कोई भी साझेदारी नहीं बना सकी। टीम के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। वहीं, गेंदबाजी में तीक्ष्णा ने चार और डेनियल सैम्स ने तीन विकेट झटके। महेश तीक्ष्णा ने अपनी अद्भुत गेंदबाजी से दुबई कैपिटल्स के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। सैम बिलिंग्स से लेकर होल्डर तक तीक्ष्णा ने चार बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। सैम्स ने भी खतरनाक दिख रहे रजा और मेरवे को आउट कर दुबई को बड़ा स्कोर खड़ा करने से वंचित कर दिया।

पंत ने दुर्घटना पर कहा, लगा था कि समय पूरा हो गया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को दिसंबर 2022 में भयानक कार दुर्घटना के दौरान लगा था कि 'इस दुनिया में उनका समय' समाप्त हो गया है। अपने गृहनगर रुड़की के पास जानलेवा दुर्घटना पर पहली बार खुलकर बात करते हुए पंत ने कहा कि 30 दिसंबर 2022 की सुबह एक डिवाइडर से टकराने के बाद अपनी गाड़ी में आग लगने के बाद उन्हें लगा था कि वह लगभग मर ही जाएंगे। दुर्घटना में पंत के दाहिने घुटने का लिगामेंट फट गया था और उनके माथे पर दो चोटें आईं। विकेटकीपर बल्लेबाज तब से क्रिकेट से दूर है। पंत ने कहा, 'जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में मेरा समय पूरा हो गया है। दुर्घटना के दौरान मुझे घावों के बारे में पता था लेकिन मैं भाग्यशाली था क्योंकि यह और भी गंभीर हो सकता था।'

अंडर-23 क्रिकेटरों के पास शराब मिलने की जांच कराएगा एससीए

नई दिल्ली, प्रेट्र : सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) ने चंडीगढ़ से राजकोट वापस जाते हुए अपने अंडर-23 क्रिकेटरों के पास से शराब की बोतलें बरामद होने के बाद सोमवार को अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का फैसला किया। एससीए सूत्रों के अनुसार यह घटना 25 जनवरी को सीके नायुडू ट्राफी में चंडीगढ़ पर सौराष्ट्र की जीत के बाद हुई।

एससीए ने कहा, 'चंडीगढ़ में एक कथित घटना हुई है जिसे सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के संज्ञान में लाया गया है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ की नैतिक/अनुशासनात्मक समिति और शीर्ष परिषद घटना की गहराई से जांच करेगी और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।'

कोहली ने पहले थूका, फिर माफी मांगी : एल्गर

केपटाउन, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने दावा किया है कि भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक टेस्ट मैच के दौरान उन पर थूका था और रायल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के साथी एबी डिविलियर्स के कहने पर दो साल बाद उन्होंने माफी मांगी थी।

एल्गर ने दिसंबर में घरेलू मैदान पर भारत के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका की दो टेस्ट मैचों की सीरीज के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने हालांकि उस सीरीज का उल्लेख नहीं किया जिसमें यह घटना घटी थी लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वाक्या 2015 में दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा हो सकता है। एल्गर ने एक पाडकास्ट पर यह भी कहा कि उनकी कोहली और रविचंद्रन अश्विन के साथ झड़प हुई थी। एल्गर ने कहा, 'मैं बल्लेबाजी करने आया और मैं वास्तव में अश्विन तथा जडेजा के विरुद्ध अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था और तभी कोहली ने मेरे ऊपर थूक दिया।' एल्गर ने दावा किया कि उन्होंने पलटवार करते हुए कोहली को गंदी गाली दी। पाडकास्ट के मेजबान ने जब एल्गर से पूछा कि क्या कोहली उनकी बातों का मतलब समझ सके, तो उन्होंने कहा, 'हां, वह समझ गया होगा। मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बल्ले से मारूंगा।' दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि जब डिविलियर्स को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने दोस्त और आरसीबी टीम के साथी के सामने यह मामला उठाया।

विराट कोहली • फाइल फोटो, प्रेट्र

एल्गर ने कहा, 'डिविलियर्स को पता चला कि उसने क्या किया है और वह कोहली के पास गए और पूछा कि तुम मेरे टीम के खिलाड़ी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह अच्छा नहीं है और दो साल बाद कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में मैच के दौरान मुझे एक तरफ बुला कर कहा कि क्या हम सीरीज के अंत में ड्रिंक करने जा सकते हैं? मैं अपनी हरकत के लिए माफी मांगना चाहता हूं।'

उप्र की जीत में चमके करन

रणजी ट्राफी

नई दिल्ली, जेएनएन : आर्यन जुयाल (76) और करन शर्मा (अविजित 67) की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्राफी के एलीट ग्रुप-बी मैच में 41 बार की चैंपियन मुंबई को दो विकेट से हराया। मुंबई ने चौथे दिन आठ विकेट पर 303 रन से शुरुआत की, लेकिन उसकी दूसरी पारी 320 रन पर ही सिमट गई। 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तर प्रदेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इसके बाद आर्यन और करन ने तीसरे विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। इसके बाद लगातार विकेट गिरने से मैच रोमांचक हो गया, लेकिन करन टिके रहे और टीम ने आठ विकेट 195 रन बनाकर जीत दर्ज की।

हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच मैच ड्रा पर समाप्त: हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच रणजी ट्राफी के एलीट ग्रुप-ए का मुकाबला चौथे दिन ड्रा पर समाप्त हुआ। हरियाणा ने महाराष्ट्र के सामने जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य रखा। खेल की समाप्ति तक महाराष्ट्र ने 96 रन बनाए थे।

दिल्ली ने चखा जीत का स्वाद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : तेज गेंदबाज हिमांशु चौहान (पांच विकेट) और ऋतिक शौकीन (तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी से दिल्ली ने रणजी ट्राफी के एलीट ग्रुप-डी मैच में उत्तराखंड को सात रन से हराकर जीत का स्वाद चखा। आइएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच के चौथे दिन उत्तराखंड को जीत के लिए मात्र 78 रन शेष चाहिए थे, जबकि चार विकेट टीम के हाथ में थे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड की दूसरी पारी 165 रन पर आलआउट कर टीम को रणजी ट्राफी के मौजूदा सत्र की पहली जीत दिलाई।

गुकेश मास्टर्स में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे

खेल डायरी

विज्क आन जी, प्रेट्र : ग्रैंडमास्टर डी गुकेश चीन के वेई यी के विरुद्ध अंतिम टाई ब्रेकर में हार का सामना करने के बाद यहां टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय ग्रैंडमास्टर लियोन ल्यूक मेंडोंका ने हालांकि 13वें और अंतिम दौर में हमवतन दिव्या देशमुख को हराकर चैलेंजर्स वर्ग का खिताब जीता।

यह गुकेश के लिए मुश्किल दिन रहा। फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए उन्हें 13वें गेम में ईरान के परहम माघसूदलू के विरुद्ध काले मोहरों से खेलते हुए जीत दर्ज करने के बाद पिछले साल के विजेता अनीश गिरी के विरुद्ध तीन टाईब्रेक गेम में बेहतर साबित होना था। उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को शिकस्त देने के बाद खिताबी मैच में वेई यी के साथ पहला मुकाबला ड्रा खेला। चीन के खिलाड़ी ने हालांकि अगले मुकाबले को जीतकर खिताब अपने नाम किया।

डी गुकेश • फाइल फोटो, एक्स

खेल मंत्रालय ने साबले और पारुल के अमेरिका में प्रशिक्षण को मंजूरी दी: खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के पदक विजेता लंबी दूरी के धावक अविनाश साबले और पारुल चौधरी के अमेरिका के कोलोराडो में प्रशिक्षण के अनुरोध को सोमवार को मंजूरी दे दी।

मंदीप जांगड़ा बने विजेता

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के टाप्पेनिश सिटी में गेरार्डो एसक्विवेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बाक्सिंग एसोसिएशन (एनबीए) का इंटरकांटिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता। अपने पेशेवर करियर में अब तक अपराजित रहने वाले 30 साल के जांगड़ा ओलिंपिक के पूर्व रजत पदक विजेता राय जोंस जूनियर के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। उन्हें अमेरिका के मुक्केबाज के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने पिछले 75 किग्रा भार वर्ग को छोड़कर कम भार वर्ग में उतरना पड़ा। जांगड़ा ने 2021 में पेशेवर मुक्केबाजी में पदार्पण किया था।

भारतीय अंडर-19 टीम के सामने अब होगी न्यूजीलैंड की चुनौती

ब्लोमफोंटेन, प्रेट्र : लगातार तीन जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत गत चैंपियन भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप में सुपर सिक्स चरण के मुकाबले में मंगलवार को न्यूजीलैंड की चुनौती का सामना करने उतरेगी तो नजरें जीत की लय कायम रखने पर लगी होंगी। ग्रुप-ए में शीर्ष पर रहकर सुपर सिक्स में पहुंची भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इसी मैदान पर अगला मैच खेलना है जहां उसने तीनों मैच जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम ईस्ट लंदन से आई है और उसे हालात के अनुरूप ढलना होगा।

भारत ने बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका को हराया है। पहले मैच में बांग्लादेश के विरुद्ध परेशानी आई लेकिन बाकी दोनों मैचों में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। भारत के लिए हर मौके पर एक या दो बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी लेकर रन बनाए हैं। तीसरे नंबर के बल्लेबाज मुशीर खान ने लगातार अच्छी पारियां खेली है। सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर एक शतक और एक अर्धशतक समेत सर्वोच्च रन बनाने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। आदर्श सिंह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में नहीं बदल पाए और अब उनका इरादा बड़ा स्कोर बनाने का होगा। सलामी बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी का आत्मविश्वास शतक के बाद बढ़ा होगा। कप्तान उदय सहारन ने भी अच्छी पारियां खेली हैं और वह इसे कायम रखना चाहेंगे। गेंदबाजी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नमन तिवारी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पिछले दो मैचों में उन्होंने चार विकेट लिए।

राष्ट्रीय फलक

मोदी के दृष्टिकोण से स्टैच्यू आफ यूनिटी अब प्रमुख पर्यटन स्थल : जयशंकर

एकता नगर, (गुजरात) : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयास से ही गुजरात में स्टैच्यू आफ यूनिटी एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। इसके चलते आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।

उन्होंने नर्मदा जिले में स्टैच्यू आफ यूनिटी के पास एकता नगर के आतिथ्य क्षेत्र में आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित एक कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया।

राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, टाटा समूह की कंपनी आइएचसीएल द्वारा शुरू किए गए इस आतिथ्य कौशल केंद्र में सालाना 120 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। एकता नगर में खोला गया यह इस तरह का दूसरा कौशल विकास केंद्र है। ज्ञात हो, गुजरात से राज्यसभा सदस्य जयशंकर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत नर्मदा जिले के चार गांवों को गोद लिया है। जयशंकर ने कहा, एकता नगर में आइएचसीएल आतिथ्य कौशल केंद्र के उद्घाटन में भाग लेने पर खुशी हुई।

बच्चों के साथ होने वाले अपराध छिपाये नहीं जाते : एनसीपीसीआर

- वाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस के सवाल पर दिया जवाब
- कहा, अपराधों से निपटने के लिए सशक्त प्रणाली वनायी गयी है

नई दिल्ली, प्रेट्र : बच्चों के साथ होने वाले अपराध छिपाये नहीं जाते बल्कि अपराधियों को दंडित किया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सोमवार को कहा कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सशक्त प्रणाली विकसित की गयी है। आयोग की यह प्रतिक्रिया क्राई नामक एक एनजीओ की रिपोर्ट के बाद आयी है कि 2016 और 2022 के बीच बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयोग ने कहा कि जनजागरूकता बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप बच्चियों के साथ यौन अपराधों के दर्ज होने वाले इतने मामले सामने आये।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एनजीओ की इस रिपोर्ट को लेकर सोमवार को केंद्र पर हमला किया और आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार के अन्याय काल में बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सशक्त प्रणाली बनायी गयी है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर लिखा लिखा कि पिछले कुछ सालों में एनसीआरबी ने प्राथमिकी के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित की है, जिसके माध्यम से देशभर के थानों से आंकड़ों को रिपोर्ट में रखा जा रहा है। भारत सरकार ने देशभर में वन स्टाप सेंटर का एक नेटवर्क बना रखा है जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा जिनके खिलाफ हाल में पाक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। कानूनगो ने कहा कि इन सूचनाओं में आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ पीड़िता की पहचान उजागर करने के संबंध में पाक्सो का एक मामला तथा प्रयागराज में उनके घर में अनाथालय में बच्चों के खिलाफ क्रूरता को लेकर मामला भी है। उन्होंने कहा कि देशभर में राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग भी तेजी से मामले दर्ज कर रहे हैं, जिसके कारण रिपोर्टिंग बढ़ी है।

बिहार में अनियंत्रित ट्रक ने छह लोगों को कुचला, चार की मौत

जासं, पटना : बिहार के पटना जिले में स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक ने सोमवार को अपराह्न तीन बजे छह लोगों को कुचल दिया। इसमें चार लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

स्टेट हाइवे पर महाबलीपुर से पटना की ओर जा रहे ट्रक ने थाना क्षेत्र के धरहरा जयप्रकाश आश्रम के समीप एक ई-रिक्शा में ठोकर मार दिया। इसके बाद कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे बाजार से लौट रहे राधा चौहान और श्याम सुंदरी देवी को कुचल दिया। बाजार के लोगों के शोर मचाने पर चालक ने ट्रक की गति बढ़ा दी। कुछ ही दूर अनुमंडल कार्यालय के समीप साइकिल से घर लौट रहे बालीपाकड़ निवासी अर्जुन कुमार एवं मैकनिक का काम कर रहे बिक्रम के जनपरा निवासी उपेंद्र मिस्त्री को भी कुचल दिया। इससे बाजार में भगदड़ मच गई। सड़क किनारे रखी छड़-गिट्टी में फंसकर ट्रक रुक गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक को दबोच कर जमकर पीटा तथा ट्रक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

****

'आरोपित की गैर-हाजिरी जमानत रद करने का आधार नहीं हो सकता'

- आरोपित को जमानत देने और खारिज करने के पैमाने अलग-अलग हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले में अदालत के समक्ष आरोपित की गैर-हाजिरी को जमानत रद करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने छह सितंबर, 2023 के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कृष्णा शर्मा की जमानत इस आधार पर रद कर दी थी कि वह अदालत के निर्देश के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं हुआ। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल इस आधार पर जमानत याचिका खारिज करना गलत है कि अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ। जमानत देने और याचिका खारिज करने के पैमाने अलग-अलग हैं। 24 जनवरी को सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर यह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को जमानत का लाभ मिला है, उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है या गवाहों को प्रभावित किया है या

साक्ष्यों से छेड़छाड़ करके जमानत का दुरुपयोग किया है, तो पहले से दी गई जमानत रद की जा सकती है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। पीठ ने कृष्णा शर्मा के वकील की इस दलील पर गौर किया कि वह अपीलकर्ता हाई कोर्ट के समक्ष इसलिए पेश नहीं हो सका क्योंकि वीआइवी मूवमेंट के कारण ट्रैफिक जाम था। कृष्ण शर्मा के वकील हाई कोर्ट में इसलिए पेश नहीं हुए थे, क्योंकि उनका वकालतनामा वापस ले लिया गया था। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुनवाई की तारीख पर न तो आरोपित और न उनके वकील अदालत में मौजूद रहे।

आतंकी पन्नू के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी करेगा यूपीएटीएस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फार जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध यूपीएटीएस लुकआउट नोटिस जारी करेगा। इसके लिए पंजाब पुलिस व केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों से भी मदद ली जा रही है। पन्नू ने 18 जनवरी को अयोध्या में तीन खालिस्तानी समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी।

एटीएस नोटिस जारी करने से पहले पन्नू के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के पुख्ता प्रमाण जुटा रहा है। इसी सिलसिले में अयोध्या में हमले की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किए गए राजस्थान निवासी गैंगस्टर शंकर लाल दुसाद, अजीत कुमार शर्मा तथा प्रदीप पुनिया को एटीएस की टीमें सोमवार रात को राजस्थान व हरियाणा लेकर गई हैं। ये किसकी मदद से पन्नू के संपर्क में आए और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या की रेकी किसलिए कर रहे थे, इसकी जांच एटीएस कर रहा है। कई वर्षों से कनाडा में रहकर पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा है।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
अंतस और अध्यात्म का
मंगलवार, 30 जनवरी, 2024

चिंतन धरोहर
स्वामी विवेकानंद

भारत के आदर्श हैं श्रीराम और सीता जी

आदिकवि वाल्मीकि रचित रामायण भारत का महान प्राचीन महाकाव्य है। इसके चरित्र श्रीराम और सीता जी भारतीय राष्ट्र के आदर्श हैं। सभी लोग, विशेषकर महिलाएं, सीता की पूजा करती हैं। जब आप इन चरित्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का आदर्श पश्चिम के आदर्श से कितना भिन्न है। पश्चिम कहता है, 'करके दिखाओ अपनी शक्ति।' भारत कहता है, 'सहकर दिखाओ अपनी शक्ति।' पश्चिम ने यह सिद्ध किया है कि एक आदमी के पास कितना अधिक हो सकता है, भारत ने सिद्ध किया है कि एक आदमी के पास कितना कम हो सकता है। दो चरम सीमाएं, आप देखिए। प्राचीन वीर युगों के आदर्श स्वरूप, सत्य परायणता और समग्र नैतिकता के आधार मूर्तिस्वरूप, आदर्श तनय, आदर्श पति, आदर्श पिता और सर्वोपरि आदर्श राजा राम का चरित्र हमारे सम्मुख महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और, सीता के विषय में क्या कहा जाए, तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो, किंतु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकते हो। सीता का चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित अनेक हो गए हैं, किंतु सीता और नहीं हुईं। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श हैं। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं। समस्त आर्यावर्त भूमि में सहस्रों वर्षों से वे स्त्री-पुरुष-बालक सभी की पूज्य हैं। महामहिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध हैं, धैर्य तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव में पूजी जाएंगी। सीता ने अविचल भाव से महादुख का जीवन व्यतीत किया। वही नित्य साध्वी, सदा शुद्ध स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्य लोक की आदर्श, देवलोक की भी आदर्श नारी, पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेंगी। भारतीय स्त्रियों से सीता के चरण चिह्नों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी। यही एकमात्र उपाय है।

अगले मंगलवार को पढ़ें श्री श्री रविशंकर का चिंतन

सप्ताह के व्रत उत्सव

2 फरवरी, शुक्रवार : रामानंदाचार्य जयंती, विवेकानंद जयंती (तिथि अनुसार)

जीवन दर्शन
ब्रह्मा कुमारी शिवानी
प्रेरक वक्ता

संकल्प से सिद्धि की ओर

जो दिख रहा है, हमें वह नहीं सोचना है। हमें वह सोचना है, जो होना चाहिए या जो हम देखना चाहते हैं। इसे आप जीवन की किसी भी स्थिति-परिस्थिति में उपयोग कर देख सकते हैं। आप स्वयं को, अपने परिवार को, देश को और पूरे विश्व को कैसा देखना चाहते हैं, यह बात सोचनी है। तभी जीवन और स्थितियों में बदलाव आएगा...

सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण से स्नेह, प्रेम व अपनत्व के भाव उत्पन्न होते हैं। चित्र: अवधेश

कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। समस्याएं ही हमें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। हर एक के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। यदि हम यही सोचते रहेंगे कि समस्या इतनी बड़ी है, यह कभी ठीक होगी भी कि नहीं। हम जितना इस प्रकार सोचते जाएंगे, समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। अगर आपके निजी संबंधों में थोड़ी-सी समस्या है तो आप अक्सर नकारात्मक सोचना आरंभ कर देते हैं। पता नहीं इनको मुझसे क्या समस्या है। मैं कितना भी प्रयास करूं, यह संबंध तो ठीक होता ही नहीं है। पता नहीं, ठीक होगा भी या नहीं। ये सब हमारे विचार हैं और हम कहते हैं यह समस्या है। हम ऐसा सोच-सोचकर संबंधों में और टकराव पैदा कर रहे हैं, जबकि जो दिख रहा है, हमें वह नहीं सोचना है। हमें वह सोचना है, जो होना चाहिए या जो हम देखना चाहते हैं। इसे आप जीवन की किसी भी स्थिति-परिस्थिति में उपयोग कर देख सकते हैं। आप स्वयं को, अपने परिवार को, देश को और पूरे विश्व को कैसा देखना चाहते हैं? यह बात सोचनी है। क्योंकि, हमारे विचार से हमारा सोच बनता है और उस सोच से हम जो कर्म करेंगे, उससे हमारी नियति बदलती है। सारा विश्व जिस प्रकार सोचेगा, उस प्रकार उसकी नियति बदलेगी। इस समय हमारे पास शक्ति है, हम अपने सोच को सही मार्ग पर लाकर अपनी नियति, अपने परिवार की नियति तथा अनेक लोगों की नियति को बदल सकते हैं। यह सच है कि हम सब स्वयं को सदा स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि कहीं मुझे यह रोग न हो जाए। मैं इस वस्तु को हाथ लगाऊं तो मुझे संक्रमण ना हो जाए। यह ठीक है, क्योंकि यह तो स्वास्थ्य का नियम है, लेकिन हाथ नहीं लगाते समय यह नहीं सोचना है कि मैं संक्रमित न हो जाऊं। जब आप बाहर से आते हैं तो संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोते हैं, लेकिन हाथ धोते समय यह नहीं सोचना है कि कहीं मुझे संक्रमण ना हो जाए। हमें यह सोचना है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और स्वच्छता के लिए हाथ धो रहा हूं।

इसी प्रकार यदि आप ध्यान करने जाते हैं, तो यह न सोचें कि पता नहीं ध्यान सधेगा या नहीं।

हमें कैसे सोचना चाहिए, यह कोई नहीं बताएगा। इसे तो हमें स्वयं तय करना होगा। सबसे पहले तो हम अपनी शब्दावली की जांच करें। शब्दावली सकारात्मक है या नकारात्मक। जब अपने विचारों को बदलना आसान न लगे, तो अपने शब्दों को बदल देना चाहिए। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए पहले हमें बाहर बदलाव करना होगा। कई बार हम अपने सकारात्मक और मीठे बोल द्वारा दूसरों के विचार और व्यवहार को बदल देते हैं। मधुर शब्दों एवं हंसमुख चेहरे से आपसी संबंधों में भी सुधार व मधुरता आती है। आपसी संबंधों तथा समाज और प्रकृति के साथ संबंधों में सुधार लाने हेतु सही शब्दों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। यह तब होगा, जब हमारे सोच, भावना, दृष्टि, वृत्ति, विचार व दृष्टिकोण सकारात्मक होंगे। सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण से स्नेह, प्रेम व अपनत्व के भाव उत्पन्न होते हैं और वातावरण शुद्ध, स्वच्छ और प्रसन्नचित्त बन जाता है। जीवन और समाज समृद्ध व सुखमय होता है।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

आध्यात्मिक योद्धा बन करें भीतर के कौरवों से युद्ध

स्वामी चिदानन्द गिरि ने अपनी भारत यात्रा में विभिन्न स्थानों पर क्रियायोग शिक्षाओं पर प्रेरणादायक व्याख्यान दिए थे। प्रत्येक मास के अंतिम मंगलवार को प्रकाशित इस स्तंभ के अंतर्गत पढ़ें उनके चिंतन का प्रमुख अंश :

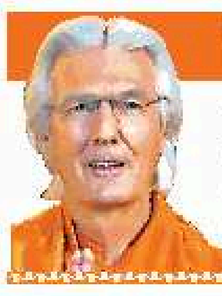

क्रियायोग
स्वामी चिदानन्द गिरि
योगदा सत्संग सोसाइटी आफ इंडिया, सेल्फ-रियलाइजेशन फेलोशिप के अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख

सांसारिक आदतों और तौर-तरीकों में हम इतने डूबे हुए हैं कि एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हुए यह सोचकर हतोत्साहित अनुभव कर सकता है कि यहां सब संत हैं और मैं एक पापी हूं, जो उनके मध्य बैठा हुआ हूं। वस्तुतः आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग एक ब्रह्मांडीय भ्रम के अधीन हैं। हम सबमें थोड़ी-बहुत विनम्रता है और उस विनम्रता का अनुचित संचालन स्वाभिमान की कमी या स्वयं को दोषी मानने के रूप में अभिव्यक्त होता है। परंतु याद रखें, एक बार किसी ने योगानंद जी से पूछा था कि योगी कथामृत में सबसे अधिक प्रेरणादायक क्या है, तो उन्होंने कहा था, मेरे गुरुदेव श्रीयुक्तेश्वरजी के शब्द कि, 'अतीत को भूल जाओ। सभी मनुष्यों के जीवन अनेक दोषों से कलुषित हैं। यदि तुम इस समय आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हो, तो भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा।' अपने मन को केंद्रित रखने का यह सकारात्मक उपाय है। सुनने में यह थोड़ा कठोर प्रतीत हो सकता है, किंतु जब कभी लोग दृढ़तापूर्वक स्वयं से यह कहते रहते हैं कि, 'मेरे अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति मुझसे अधिक उन्नत है और इस कमरे में अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं, जो पूर्ण रूप से असफल है,' तब यह प्रयास न करने का एक बहाना बन जाता है। आपको अपनी उस प्रवृत्ति का विरोध करना होगा और उसे यह आदेश देना होगा, 'रुको! मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। यहां से दूर भागो।' क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है, उसकी तुलना आप किसी ऐसे पागल आदमी से कर सकते हैं, जो आपके द्वार पर खड़ा है और आपसे कह रहा है, 'अरे, तुम तो एक बेकार आदमी हो, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो।'

आपके मन के ऐसे भ्रम अहंकार से जुड़े होते हैं। उनका पहला उद्देश्य होता है आपको आध्यात्मिक प्रयास करने से रोकना। प्रायः स्वयं के प्रति निराशाजनक प्रवृत्ति आपको सबसे अधिक आध्यात्मिक प्रयास करने से रोकती है। इसलिए, आपको उसका सामना करना होगा। आपको एक 'आध्यात्मिक योद्धा' बनना होगा। ये वे कौरव हैं, जिनके बारे में परमहंस योगानंद जी ने श्रीमद्भगवद्गीता की अपनी व्याख्या (ईश्वर-अर्जुन संवाद) के प्रथम अध्याय में उल्लेख किया है। वे कौरव आपकी विचार प्रक्रिया से जुड़ने तथा आपकी विजेता आध्यात्मिक प्रकृति पर दृढ़ रहने के मार्ग से आपको विचलित करते और रोकते हैं। इनसे बचने के लिए इच्छाशक्ति और दृढ़संकल्प की आवश्यकता है, परंतु सबसे बुरा कार्य बार-बार स्वयं से यह कहते रहना है कि, 'मैं किसी काम का व्यक्ति नहीं हूं, दूसरा हर व्यक्ति मुझसे अच्छा है।' इस प्रकार सोचना बंद कर दें और किसी सकारात्मक विचार को चुनें। इसीलिए गुरुजी परमहंस योगानंद जी ने कहा है, 'मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर के प्रतिबिंब स्वरूप में निर्मित हूं।' अपने बारे में मिथ्या धारणाओं के भ्रम समाप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह प्रयास ध्यान और सकारात्मक प्रतिज्ञा द्वारा किया जाता है।

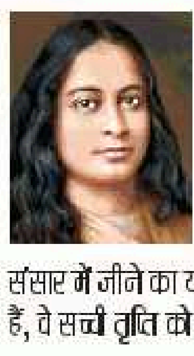

किसी से भयभीत न हों। किसी से घृणा ना करें। सभी से प्रेम करें। प्रत्येक में ईश्वर की विद्यमानता को देखें। केवल एक इच्छा रखें कि अपनी चेतना के मंदिर में निरंतर उनकी विद्यमानता हो। इस संसार में जीने का यही एक ढंग है। जो अन्य इच्छाएं रखते हैं, वे सच्ची तृप्ति को नहीं जानेंगे।
– श्री श्री परमहंस योगानंद

वर्ग पहेली-2529

बाएं से दाएं
2. जांच, इम्तिहान, परीक्षा (3)। 4. सज्जनता (4)। 5. खाने-पीने की सामग्री (3)। 8. शिष्टाचार (3)। 10. लचकने का भाव (3)। 12. विषम (3)। 13. प्रेमचंद का एक उपन्यास (3)। 14. मृत और घायल (4)। 15. रचना का महान पुरुष (3)। 17. सृजन या रचना करना (3)। 19. दर्द से आहें भरना (4)। 20. उपार्जन करना (3)।

ऊपर से नीचे
1. व्यायाम, वर्जिश (4)। 3. समाचार, संदेश (3)। 4. मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया खाद्य, मधु (3)। 6. समान या बराबर होने का भाव (4)। 7. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े (3)। 9. ईर्ष्या, द्वेष (3)। 11. कहा जाना (4)। 12. गुजरना, व्यतीत होना (3)। 13. निर्धन, कंगाल (3)। 16. जलजला, प्रलय (4)। 17. किसी जगह पर रुक कर स्थायी रूप से रहना (3)। 18. नाम का (3)।

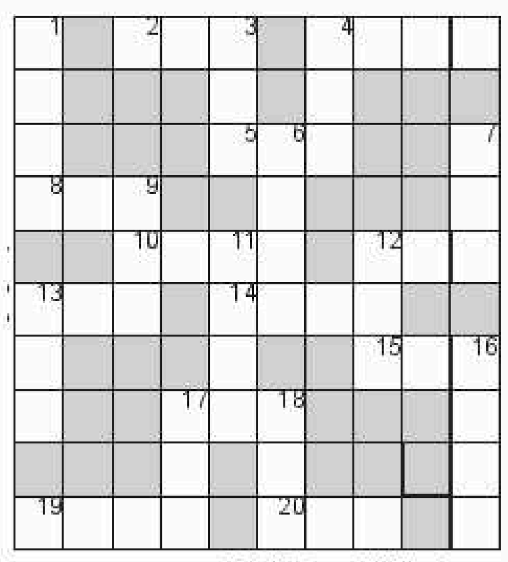

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

च	रि	त्र	वा	न		त	र	क	श
प				सी			ज		ह
ल	की	र		ब	ल		नी		र
ता					प				या
		आ	चा	न	क		बा	ह	र
फा	य	दा		का	ना	फू	सी		
य				र					न
दे		स		ना	श		सा	ह	स
मं		न			म				बं
द	म	क	ल		न	ज	र	बं	दी

जागरण सुडोकू-2529

		4		9		8		1
1	8	3		2			9	
9			1		3		4	
8			6			1		4
	3	1		5	8		7	
6			7	1			8	3
	9		2				6	
	4	2			9	7		
3			8		5		2	9

कल का हल

1	7	2	8	9	5	3	6	4
3	4	9	2	1	6	7	8	5
6	8	5	4	3	7	9	2	1
4	9	1	7	5	2	6	3	8
2	6	3	1	8	9	5	4	7
7	5	8	6	4	3	2	1	9
8	2	6	5	7	1	4	9	3
5	3	4	9	6	8	1	7	2
9	1	7	3	2	4	8	5	6

आज का भविष्यफल- 30 जनवरी, 2024 मंगलवार
के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी।
आज का राहुकाल : अपराह्न 03 बजे से 04 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : उत्तर। विशेष : महात्मा गांधी निर्वाण दिवस, चतुर्थी तिथि वृद्धि

कल 31 जनवरी, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : उत्तर
विक्रम संवत 2080, शके 1945, उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु माघ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी 11 घण्टे 37 मिनट तक, तत्पश्चात षष्ठी, हस्त नक्षत्र 25 घंटे 8 मिनट तक, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र, सुकर्मा योग 11 घंटे 41 मिनट तक, तत्पश्चात धृति योग। कन्या में चंद्रमा।

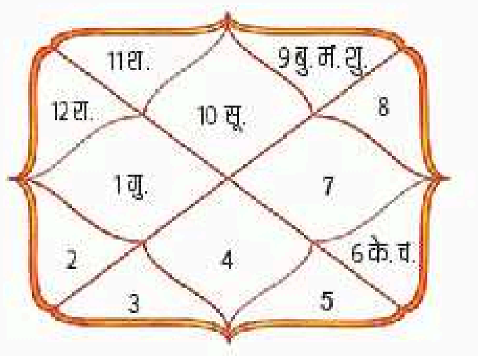

मेष : व्यस्तता बढ़ेगी। रुपये-पैसे के लेनदेन में सावधानी रखें।
वृष : गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे।
मिथुन : धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
कर्क : जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है।
सिंह : शिक्षा-प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
कन्या : पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी।
तुला : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
वृश्चिक : जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य मिलेगा।
धनु : व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
मकर : किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। संतान से तनाव मिल सकता है।
कुंभ : भौतिक सुख में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
मीन : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय फलक

गंगा आरती के साथ राष्ट्रभक्ति का भी पाठ

राज्य ब्यूरो, देहरादून : आस्था, स्वच्छता व आर्थिकी के साथ राष्ट्रभक्ति का भी पाठ। राष्ट्रीय नदी गंगा की निर्मलता के लिए संचालित नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर आरती के दृष्टिगत दिए जा रहे प्रशिक्षण के मूल में यही भाव समाहित है। घाटों में जब मां गंगा की आरती होगी तो लोग जुटेंगे और मेले जैसा वातावरण होगा। आस्था से लोग जुड़ेंगे तो नदियों व घाटों की साफ-सफाई भी होगी। गंगा आरती के बाद वितरित होने वाला प्रसाद स्थानीय उत्पाद से बना होगा। आरती के पश्चात राष्ट्रगान भी होगा।

इस सब को केंद्र में रख चयनित प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण की श्रृंखला चल रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व बंगाल के 30 प्रतिभागी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे पहले चार राज्यों के 90 व्यक्तियों को गंगा आरती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नमामि गंगे में गंगा आरती प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी पूरन कापड़ी के अनुसार इन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड व बिहार में 26 स्थानों पर प्रशिक्षण लेने वाले लोग साप्ताहिक या प्रतिदिन गंगा आरती करा रहे हैं।

मतांतरण रोकने को छत्तीसगढ़ में कानून को और सख्त बनाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार मतांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2006 के प्रविधानों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। विधि विभाग ने अन्य राज्यों में लागू मतांतरण विरोधी कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार संशोधित कानून में 10 साल तक की सजा का प्रविधान किया जा सकता है। मौजूदा अधिनियम में मतांतरण के दोषी पाए लोगों को तीन साल की जेल की सजा और 20 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रविधान है।

संविधान में कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं : संविधान में मतांतरण रोकने का स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इससे पहले राजनीतिक दलों, धार्मिक समुदायों व सामाजिक संगठनों ने संविधान संशोधन व राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई थी। इन सब के बीच राज्यों ने अपने-अपने कानून लागू किए हैं।

किस राज्य में कौन सा कानून

ओडिशा : मतांतरण पर कानून बनाने वाला पहला राज्य, जहां वर्ष 1967 में कानून लागू हुआ। अधिकतम दो वर्ष की जेल और अधिकतम 10 हजार रुपये तक जुर्माना तय किया गया।

मध्य प्रदेश : वर्ष 1968 में मतांतरण पर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना। वर्ष 2020 में शिवराज सरकार ने कानून में संशोधन किया। अधिकतम 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया।

अरुणाचल प्रदेश : मतांतरण पर रोक लगाने के लिए 1978 में कानून बना। दो वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

गुजरात : 2003 के कानून में अप्रैल 2021 में संशोधन हुआ। इसे गुजरात फ्रीडम आफ रिलीजन (अमेंडमेंट) एक्ट 2021 नाम दिया गया। इसमें अधिकतम सात वर्ष की कैद और अधिकतम तीन लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रविधान है।

हिमाचल प्रदेश : 2006 में कानून बना, 2019 में संशोधन हुआ। वर्ष 2022 के अगस्त में 'द फ्रीडम आफ रिलीजन (संशोधित)' बिल पारित। इसमें 10 वर्ष कैद व दो लाख रुपये के जुर्माना का प्रविधान है।

झारखंड : 2017 में कानून बना। एक लाख तक जुर्माना व चार वर्ष सजा का प्रविधान।

उत्तराखंड : 2018 में कानून बना। 10 वर्ष जेल व 50 हजार जुर्माने का प्रविधान। साथ ही पीड़ित को अलग से मुआवजा देना होगा।

उत्तर प्रदेश : 2020 को 'उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून' लागू हुआ। इसमें दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष की जेल और 15 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना प्रविधान।

कर्नाटक : 2022 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कानून के उल्लंघन पर तीन से 10 साल तक जेल व 50 हजार रुपये जुर्माना का प्रविधान।

> मतांतरण रोकने के लिए जितने कड़े प्रविधानों की आवश्यकता होगी, हम वह सब करेंगे। हम कानून में संशोधन करते हुए इसे और कड़ा करने की योजना बना रहे हैं।
> **-अरुण साव, उप मुख्यमंत्री व विधि मंत्री, छत्तीसगढ़**

मतांतरण की कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना किया गया विवाह अमान्य

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू-मुस्लिम जोड़ों द्वारा सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका पर राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, मतांतरण की कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना किया गया विवाह मान्य नहीं है। जोड़ों ने परिवार से जीवन को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा, ये विपरीत धर्म के जोड़ों के विवाह के मामले हैं। इन विवाहों में धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा, यदि याचियों द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद विवाह किया जाता है तो वह नए सिरे से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा, 2021 में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून गलतबयानी, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती व प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण पर रोक लगाता है। आठ याची गण में पांच मुस्लिम युवकों ने हिंदू महिलाओं से और तीन हिंदू युवकों ने मुस्लिम महिलाओं से बिना विधिक तौर पर मतांतरण (धर्म परिवर्तन) किए हुए शादी की है। कई राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

यूजीसी का नया मसौदा आरक्षण खत्म करने की साजिश : राहुल

- कहा, वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहते हैं भाजपा-आरएसएस
- पार्टी ने की यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई मसौदा गाइडलाइंस को उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश करार दिया है। पार्टी ने इस मामले में यूजीसी के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है।

कांग्रेस ने रविवार को यूजीसी की इस नई मसौदा गाइडलाइंस को वापस लिए जाने की मांग की थी जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त पद को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है अगर इन वर्गों से पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं।

राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, 'यूजीसी के नए मसौदे में उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं और जिनमें सिर्फ 7.1 प्रतिशत दलित, 1.6 प्रतिशत आदिवासी और 4.5 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं। भाजपा-आरएसएस अब ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहते हैं। यह सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी खत्म करने का प्रयास है। यही सांकेतिक राजनीति और वास्तविक न्याय के बीच का फर्क है और यही भाजपा का चरित्र है।' 'कांग्रेस ये कभी नहीं होने देगी। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और इन रिक्त पदों पर भर्ती आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवारों से ही करवाएंगे।'

कांग्रेस के एससी विभाग के प्रमुख राजेश लिलोथिया व असंगठित श्रमिक एवं कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष उदित राज ने कहा, इस जनविरोधी कदम का कांग्रेस द्वारा विरोध के बाद यूजीसी को यह बयान जारी करने पर मजबूर होना पड़ा कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया है। उदित राज ने कहा, 'यह नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पूर्व में अपनी आरक्षण विरोधी मानसिकता प्रकट कर चुके हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है। यूजीसी का कदम मोहन भागवत और आरएसएस पर हमारी आशंकाओं की पुष्टि करता है। 2014 के बाद से शिक्षण संस्थानों में ज्यादातर नियुक्तियां आरएसएस पृष्ठभूमि से की जा रही हैं।

प्रधान का पलटवार, राहुल की राजनीति झूठ पर आधारित

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी राजनीति पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। उन्हें या तो अपने दावे के समर्थन में ठोस सुबूत देना चाहिए या सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। प्रधान ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'राहुल गांधी की राजनीति पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। जैसे ही एक झूठ उजागर होता है, वह दूसरा झूठ लेकर खड़े हो जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए झूठे बयानों की सूची अंतहीन है। अब राहुल और कांग्रेस उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति को लेकर नया झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनका यह झूठ भी बेनकाब हो गया है।' उन्होंने बताया कि 6,080 नियुक्तियां की गईं, जिनमें एससी की भागीदारी 14.3 प्रतिशत, एसटी की सात प्रतिशत और ओबीसी की 23.42 प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों पर सबसे अधिक नियुक्तियां नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत की गई हैं। उन्होंने कहा, 'इसलिए राहुल गांधी बेबुनियाद बात कर रहे हैं। झूठ फैलाकर समाज को बांटना और अस्थिरता पैदा करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस का मूल चरित्र एससी-एसटी-ओबीसी विरोधी है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने सदैव वंचित वर्गों के हितों का खुलकर विरोध किया है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं का एससी-एसटी-ओबीसी विरोधी चेहरा एक बार फिर उस समय सामने आ गया है, जब नरेन्द्र मोदी नीत सरकार वंचित वर्गों का सशक्तीकरण सुनिश्चित कर रही है।

हत्या का अपराध स्वीकारने का दबाव बनाने का आरोप, युवक ने दी जान

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

- फतेहपुर में घटना, आत्महत्या से पहले बनाए वीडियो में पुलिस प्रताड़ना की बात कही

उप्र के फतेहपुर जिले में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने रविवार सुबह जान दे दी। खेत में नीम के पेड़ से अंगोछे के फंदे से उसका शव लटका मिला था। अंतिम संस्कार के बाद सोमवार को उसका मोबाइल फोन मिला। इसमें एक वीडियो था जिसमें उसने थरियांव थाना पुलिस पर हत्याकांड का जुर्म कुबूल करने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पिता व भाई ने एसपी उदयशंकर सिंह से मिलकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने एएसपी को जांच सौंपी है।

सीओ अरुण राय ने बताया कि शारीरिक प्रताड़ना का आरोप निराधार है। श्याम सिंह प्रयागराज में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, जबकि उससे छोटा 20 वर्षीय पुत्र रामरूप गांव में रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। सेमरा में हुए रामरतन रैदास हत्याकांड में पूछताछ के लिए बीती 27 जनवरी को पुलिस रामरूप को थरियांव थाने ले गई थी। 29 जनवरी को फिर आने की बात कहकर उसे छोड़ दिया। 28 जनवरी की सुबह रामरूप ने आत्महत्या कर ली। पिता अनोखेलाल ने आरोप लगाया कि बेटे ने थाने से लौटकर बताया था कि सेमरा हत्याकांड का जुर्म कुबूल कराने के लिए पुलिस ने बुरी तरह से मारापीटा।

बंदूक तानकर बोल रहे थे मार देंगे... : इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो में रामरूप कह रहा है कि पुलिस वाले उसे गांव से उठाकर ले गए। इसके बाद थाने में उसे बुरी तरह से पीटा। बंदूक कान में लगाकर बोल रहे थे मार दूंगा, आंख के पास सूजा दिखाकर पैसा मांग रहे थे और हत्या में फंसाकर जेल भेजने की बात कह रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए फांसी लगाने जा रहा हूं।

पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- दिल्ली में हुआ केंद्र, राजस्थान व मप्र के बीच एमओयू

राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का रविवार को पटाक्षेप हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक की। इसके बाद दोनों दिल्ली पहुंचे। वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय के श्रम शक्ति भवन स्थित कार्यालय में दोनों राज्य और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हो गया। इसके अंतर्गत अब एकीकृत पार्वती, कालीसिंध व चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया जाएगा। मप्र में सात सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होगा। इससे 13 जिलों में 3.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा, पार्वती, कालीसिंध व चंबल नदी के जल बंटवारे को लेकर लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णय से दोनों राज्यों के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। इससे रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे। परियोजना दोनों राज्यों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय जल शक्ति सचिव देबाश्री मुखर्जी, मप्र के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा व राजस्थान के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने हस्ताक्षर किए।

इन सात सिंचाई परियोजनाओं का होगा निर्माण : समझौते के अनुसार पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना में कुंभराज काम्प्लेक्स, सीएमआरएस काम्प्लेक्स, लखुंदर बैराज, रणजीत सागर परियोजना तथा ऊपरी चंबल कछार में सात सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होगा।

यह था विवाद : पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) के लिए बांध बनाने व पानी बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच विवाद था। राजस्थान का आरोप था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बनना था, लेकिन मप्र सरकार ने ईआरसीपी के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में राजस्थान सरकार ने स्वयं के खर्च पर ईआरसीपी को पूरा करने का निर्णय लिया और बांध बनना शुरू हुआ तो मप्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी।

संघीय संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह दिन मप्र व राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। परियोजना से 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही बांधों और बड़े तालाबों की मदद से जल-स्तर उठाने में सफलता प्राप्त होगी। यह परियोजना संघीय संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण है।

****

शोधकर्ताओं ने मनुष्यों के सबसे पुराने ज्ञात पूर्वज की खोज की

2017 में आज ही के दिन विज्ञानियों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने चीन में एक आदिम समुद्री जीव सैकोरहाइटस के संरक्षित जीवाश्म की खोज की थी। इसे लेकर उन्होंने दावा किया कि यह मनुष्यों का सबसे पुराना ज्ञात पूर्वज है। जीवाश्म लगभग 54 करोड़ साल पुराना था।

इतिहास के सबसे घातक समुद्री हमले में गई नौ हजार से ज्यादा जानें

1945 में आज ही के दिन सोवियत पनडुब्बी एस-13 ने जर्मन सैन्य जहाज एमवी विल्हेम गुस्टलाफ को बाल्टिक सागर में टारपीडो से मारकर डुबो दिया था। हमले में 9,400 जर्मन सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई थी। इसे इतिहास का अब तक का सबसे घातक समुद्री हमला कहा जाता है।

हिंदी साहित्य के अग्रदूतों में गिने जाते हैं जयशंकर प्रसाद

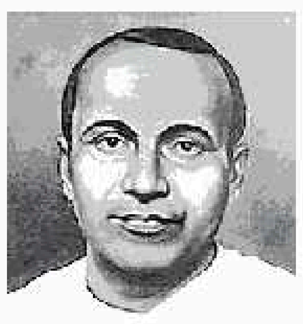

प्रख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में आज ही के दिन काशी में हुआ था। आठ वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। 1913 में उनके पहले काव्य-संग्रह 'कानन-कुसुम' का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। 1935 में प्रकाशित कामायनी उनकी कालजयी रचनाओं में गिनी जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटक भी लिखे। इसके अलावा आंसू, प्रेम-पथिक, झरना, लहर और छाया उनकी प्रमुख कृतियां हैं। 15 नवंबर, 1937 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

जागरण विशेष

सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर जहरीली गैस को निष्क्रिय करेगा पाउडर

भोपाल स्थित आइसर के विज्ञानियों का नवोन्मेष, रासायनिक हमलों में होगा काफी उपयोगी

प्रवीण मालवीय ● भोपाल

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइसर) भोपाल के विज्ञानियों ने बेहद जहरीली मस्टर्ड गैस को निष्क्रिय करने की स्वदेशी विधि विकसित की है। इसके लिए विज्ञानियों ने लंबे शोध के बाद नैनो पदार्थ (पाउडर) तैयार किया है, जो सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रतिक्रिया कर मस्टर्ड गैस को निष्क्रिय करने के साथ ही इसे हानिरहित रसायन में बदल देता है।

अभी सूर्य के पूरे प्रकाश का नहीं होता उपयोग: विश्व में अब तक खतरनाक गैसों को निष्क्रिय करने के लिए विकसित किए गए नैनो कंपोजिट पदार्थ सूर्य की पराबैंगनी किरणों (यूवी रेज) के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन यह नया पदार्थ सूर्य के प्रकाश में मौजूद सभी तत्वों से प्रतिक्रिया करता है। शोध को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका एजवेंटे केमी में प्रकाशित किया गया है।

ऐसे काम करता है : शोध टीम के आइसर के रसायनशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अभिजीत पात्रा बताते हैं कि अभी तक के नैनो कंपोजिट पदार्थ यूवी किरणों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, पर इसकी एक कमी यह है कि सूर्य के प्रकाश में यूवी किरणों की हिस्सेदारी सीमित होती है। इसके विपरीत नया पदार्थ वास्तव में फोटोकैटेलिस्ट है, जो धूप में मौजूद यूवी, विजुअल और नियर इन्फ्रारेड प्रकाश किरणों के साथ भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। ऐसे में इस नए पदार्थ का उपयोग खुले वातावरण में सूर्य के प्रकाश के साथ किया जा सकता है, जिससे यह खतरनाक गैस को बेअसर करने में अधिक कारगर साबित होगा।

प्रतिक्रिया को और तेज करने आगे बढ़ा शोध

मस्टर्ड बेहद जहरीली गैस होती है। इसके संपर्क में आने पर त्वचा लाल हो जाती है, फिर गलकर शरीर से छिलके की तरह उतरने लगती है। चूंकि, यह गैस उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसे में डा. अभिजीत पात्रा और उनकी टीम (शोधार्थी शिल्पी जायसवाल, मधुरिमा सरकार, डा. अर्कप्रभा गिरी) ने मस्टर्ड गैस का सिमुलेंट (प्रारूप) तैयार किया और फिर फोटोकैटेलिस्ट विकसित कर इस गैस के सिमुलेंट को निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की। इस पदार्थ का उपयोग रासायनिक सुरक्षा कवच या ऐसे अन्य उपकरण बनाने के साथ रासायनिक उद्योगों में भी किया जा सकता है। प्रोफेसर पात्रा बताते हैं वर्तमान में इस प्रक्रिया में करीब चार घंटे लग रहे हैं। अब हम इस कंपोजिट की प्रतिक्रिया को और तेज करने सहित अन्य रसायनों को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ बनाने पर कार्य कर रहे हैं।

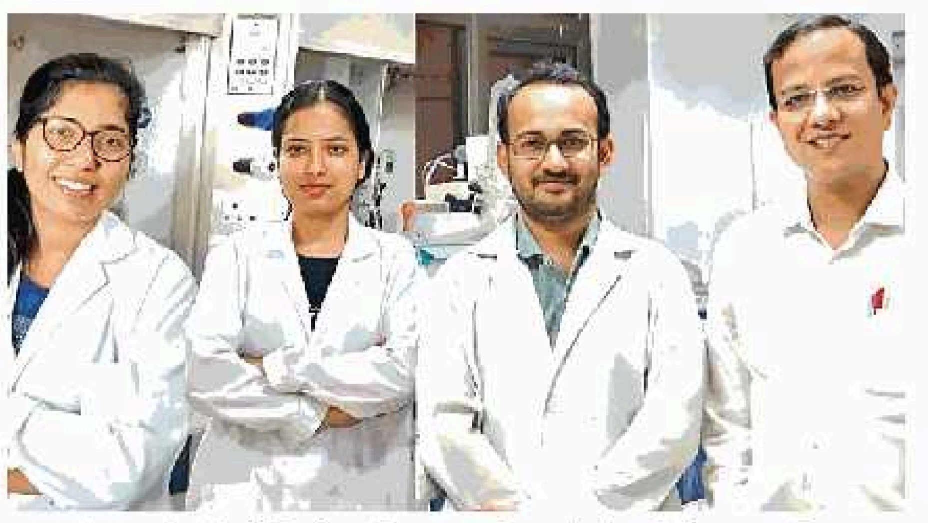

आइसर में (बाएं से) शोधार्थी शिल्पी, मधुरिमा, डा. अर्कप्रभा और प्रो. अभिजीत ● नवदुनिया

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

कुकेरी नृत्य

बुल्गारिया में बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए लोग अजीबो-गरीब पोशाक पहनकर और कमर में घंटियां बांधकर 'कुकेरी नृत्य' करते हैं। पार्निक शहर में अंतरराष्ट्रीय मसक्यूरेड महोत्सव पर यह आयोजन होता है। एएफपी

इधर-उधर की

एवरेस्ट की चढ़ाई कर दो वर्षीय बच्चे ने बनाया रिकार्ड

लंदन, एजेंसी: ब्रिटेन का रहने वाला दो वर्षीय बच्चा कार्टर डलास एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार कार्टर नेपाल में समुद्र तल से 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिणी स्थल पर चढ़ा। उसने पिता रास की पीठ पर मां जेड के साथ ट्रेक पूरा किया। तीनों एक साल की एशिया यात्रा पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार बेस कैंप का पिछला रिकार्ड चेक गणराज्य के एक चार वर्षीय बच्चे के पास था। रास ने कहा कि यात्रा के दौरान कार्टर को किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई। तीनों ने सांस लेने की तकनीक का अभ्यास किया। इस रिकार्ड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

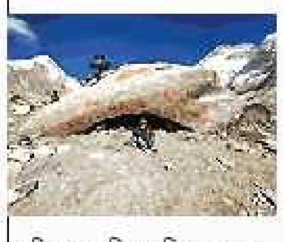

परिवार सहित एशिया यात्रा पर है कार्टर डलास ● इंटरनेट मीडिया

अल्सरेटिव कोलाइटिस में फायदेमंद है नारियल पानी

शोध ▶ एम्स में 121 मरीजों पर किए गए क्लीनिकल ट्रायल में साबित हुआ फायदा

नारियल पानी में सूजन कम करने व गट माइक्रोबायोम में बदलाव करने की है क्षमता

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

पेट की बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस यदि किसी को हो जाए तो जीवन भर परेशान करती है। इस बीच एम्स में हुए एक क्लीनिकल ट्रायल में पाया गया है कि नारियल का पानी इसके इलाज में मददगार है। यदि दवा के साथ-साथ मरीज को प्रतिदिन नारियल पानी दिया जाए तो इससे आराम मिल सकता है। एम्स का यह शोध हाल ही में अमेरिका के क्लीनिकल गैस्ट्रोइंटेरोलाजी एवं हेपेटोलाजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल ने भी इस शोध को महत्व दिया है।

एम्स ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के साथ मिलकर अल्सरेटिव कोलाइटिस के मध्यम स्तर के गंभीर व हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज में इसका ट्रायल किया। 121 मरीजों को दो वर्गों में बांटकर यह ट्रायल किया गया। जिसमें 54 पुरुष प्रतिशत और 46 प्रतिशत महिला मरीज शामिल थीं। मरीजों की औसत उम्र 37 वर्ष थी। वे दो से साढ़े सात वर्ष से अल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे थे।

एम्स के गैस्ट्रोलाजी विभाग के प्रोफेसर डा. विनीत आहूजा ने बताया कि इस क्लीनिकल ट्रायल में आधे मरीजों को अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ-साथ आठ सप्ताह तक प्रतिदिन 400 मिलीलीटर नारियल पानी दिया गया। वहीं दूसरे वर्ग के मरीजों को दवाओं के साथ-साथ बोतलबंद फ्लेवरयुक्त पानी दिया गया। ट्रायल में नारियल पानी का इस्तेमाल करने वाले 57.1 प्रतिशत मरीजों पर इलाज का अच्छा असर देखा गया, जबकि दूसरे वर्ग के सिर्फ 28.3 प्रतिशत मरीजों पर ही इलाज का असर अच्छा पाया गया।

नारियल पानी का इस्तेमाल करने वाले 53.1 प्रतिशत मरीजों की बीमारी कम हुई और उन्हें आराम मिला। दूसरे वर्ग के सिर्फ 28.3 प्रतिशत मरीजों की बीमारी कम हो पाई। ट्रायल में यह भी पाया गया कि नारियल पानी के इस्तेमाल से मरीजों के शरीर में मौजूद गट माइक्रोबायोम (आंत में मौजूद रहने वाले बैक्टीरिया) में भी बदलाव होता है। इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज में दवा के साथ नारियल पानी का इस्तेमाल फायदेमंद है।

गुणकारी है नारियल पानी। फाइल

नारियल पानी में होता है पोटैशियम

अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी में आंतों में सूजन हो जाती है और अल्सर जैसे जख्म बन जाते हैं। इस वजह से मरीजों को पेट दर्द, दस्त के साथ खून आने की समस्या होती है। इसके अलावा बुखार होता है और शरीर का वजन कम होने लगता है। डा. विनीत आहूजा ने बताया कि यह आजीवन चलने वाली बीमारी है। इलाज के लिए मरीज को इम्युनिटी नियंत्रित करने वाली दवाएं भी देनी पड़ती हैं। नारियल पानी में पोटैशियम होता है। पोटैशियम में सूजन कम करने (एंटी इंफ्लेमेटरी) का गुण होता है। यही सोचकर इसका ट्रायल किया गया और परिणाम उत्साहजनक पाए गए। इसे बतौर इलाज उपयोग करने के लिए भविष्य में और शोध की आवश्यकता है।

इम्यूनोथेरेपी का सभी कैंसर मरीजों पर काम न करने का कारण पता चला

अनुसंधान

कैंसर कोशिकाएं। फाइल

कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी बेहद अहम रोल निभाती है। लेकिन यह हमेशा और हर किसी पर कार्य नहीं करती। इसके पीछे का कारण विज्ञानियों ने पता लगा लिया है। विज्ञानियों ने शोध के दौरान उस मेकेनिज्म से पर्दा उठाया है, जो इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को खत्म करने से रोकता है। यह शोध जर्नल सेल रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कोलोन, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट और ब्रेन कैंसर में इम्यूनोथेरेपी अधिक कारगर साबित नहीं होती है, जबकि ब्रेस्ट, ग्रासनली और सिर और गर्दन के कैंसर के मामलों में यह अक्सर सफलतापूर्वक काम करती है। शोध से जुड़े सौरीश गफरी ने कहा कि इम्यून सिस्टम में एक प्रमुख जांच बिंदु जिसे एनकेजी2ए कहा जाता है उचित संकेत प्राप्त न होने तक कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ कार्य नहीं कर पाता है। एनकेजी2ए रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए मोनोथेरेपी एजेंट तब तक लाभ नहीं पहुंचा पाते जब तक सूजन जैसी स्थिति पैदा न हो। इससे पता चलता है कि एनकेजी2ए रिसेप्टर को लक्षित करने के लिए सूजन संकेत उत्पन्न करने वाली दवाओं के साथ संयोजन जरूरी है। इस अध्ययन के दौरान यह भी पता चला है कि कैसे कुछ कैंसर प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके मैक्रोफेज को सक्रिय करने से रोक सकते हैं, जो विशेष इम्यून सेल हैं और जो रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त सेल को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शोध आने वाले समय में इम्यूनोथेरेपी की मदद से अधिक कैंसर रोगियों के इलाज में मदद कर सकती है। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

पात्र को लेकर मन में एक डर होना चाहिए : आदित्य

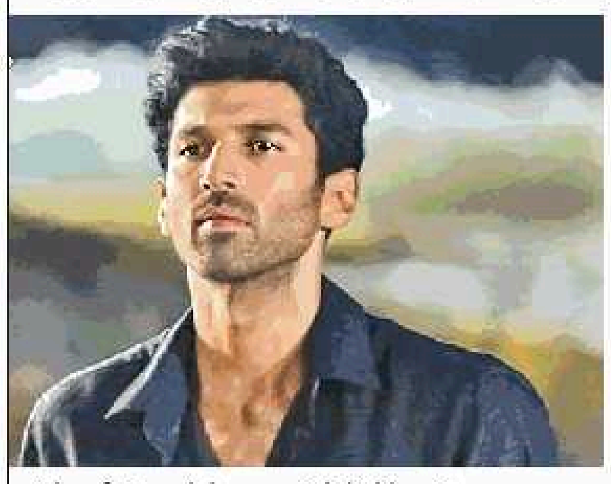

एंथोलाजी फिल्म मेट्रो... इन दिनों में होंगे आदित्य। (इंस्टाग्राम)@adityaroykapur

फिल्म इंडस्ट्री में खुद के लिए काम तलाशना ही कठिन नहीं है, बल्कि हर बार अलग तरह का काम तलाशना ज्यादा कठिन है। दूसरी बात यह कि यहां टाइपकास्ट भी बड़ी जल्दी कर दिया जाता है कि अगर एक रोल में दर्शकों ने पसंद कर लिया है, तो आगे के दर्जन भर रोल उसी तरह के आफर हो जाते हैं। इन मुश्किलों के बीच अभिनेता आदित्य राय कपूर इसलिए केवल वही काम चुनते हैं, जिसमें वह पिछले काम से कुछ अलग कर पाए। द नाइट मैनेजर वेब सीरीज के बाद आदित्य अब आगामी दिनों में अनुराग बासु निर्देशित फिल्म मेट्रो... इन दिनों में नजर आएंगे। इस बारे में बात करते हुए आदित्य दैनिक जागरण से बातचीत में कहते हैं कि मुझे रिपीट परफार्मर बनना पसंद नहीं है। मैं अलग-अलग चीजें नहीं कर सकता हूं। मुझे कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। अगर मुझे लगता है कि जो कहानी और पात्र मेरे पास आए हैं, उसे मैं आसानी से कर लूंगा, तो मैं फिर वह काम नहीं करता हूं। अपने पात्र को लेकर मन में एक डर होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि एक जानर में जाना है, तो कैसे उसमें जाऊंगा, कैसे उस पात्र को वास्तविक दिखा पाऊंगा। हर प्रोजेक्ट में वह अहसास नहीं मिलेगा कि यह तो मेरे लिए लिखा गया है।

फाइटर फिल्म की सीक्वल को लेकर सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि सीक्वल उन्हें कंफर्ट जोन लगता है और उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर काम करना पसंद है।

फाइटर 2 को लेकर अब तक सोचा नहीं

फिल्म हिट होती है, तो उसके सीक्वल को लेकर या कहानी की फ्रेंचाइज के तौर पर आगे बढ़ाने की बातें शुरू हो जाती हैं। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म फाइटर की सीक्वल को लेकर भी खबरें आ रही थीं। हालांकि खुद फिल्मकार सिद्धार्थ आनंद ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि वह फिलहाल इसकी सीक्वल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बल्कि वह अपनी आगामी फिल्मों को लेकर व्यस्त हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में सिद्धार्थ कहते हैं, 'मैंने फिलहाल सोचा नहीं है कि इस कहानी या फिर किरदारों के साथ फाइटर 2 बनाऊंगा। फिल्म को मिली प्रतिक्रिया के बाद यह तय होगा। दरअसल, मैं उन निर्देशकों में से ही नहीं हूं, जो अपनी कहानियां का सीक्वल या प्रीक्वल बनाते हों। मैं अपनी फिल्मों का पार्ट 2 बनाने वाला आखिरी इंसान होऊंगा। मैंने अब तक अपनी किसी फिल्म की सीक्वल नहीं बनाई है। मुझे नए किरदार, नई कहानियां बनाने में दिलचस्पी है। मैं अगर वह काम करूंगा, तो एक ही जगह रुक जाऊंगा। मैं खुद को रोज चुनौती देना चाहता हूं।' सिद्धार्थ ने आगे बताया कि वह डिजिटल प्लेटफार्म के लिए सैफ अली खान और जयदीप अहलावत के साथ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो एक मजेदार एक्शन फिल्म होगी। इसके साथ ही वह टाइगर श्राफ के साथ रैम्बो फिल्म बना रहे हैं, जिसका निर्देशन रोहित धवन करेंगे। यह भी एक विशुद्ध एक्शन फिल्म होगी।

अपने प्रोडक्शन हाउस तले टाइगर के साथ एक्शन फिल्म बना रहे हैं सिद्धार्थ ● मिडडे आर्काइव »

रोहित शेट्टी को मिली हरी डंडी

डिजिटल प्लेटफार्म पर ज्यादातर कहानियों के सीजन का अंत इस तरह से किया जाता है कि उनके अगले सीजन को बनाने की संभावनाएं बनी रहें। हाल ही में प्रदर्शित फिल्मकार रोहित शेट्टी की पहली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही देखा गया। हालांकि, इस शो को लेकर समीक्षकों और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। रोहित शेट्टी जैसे फिल्मकार के निर्देशन में बनने के पश्चात भी यह वेब सीरीज अपेक्षित चर्चा बटोरने में सफल नहीं दिखी। हालांकि, इन चीजों से परे अब खबर है कि इस शो के दूसरे सीजन के लिए अमेजन प्राइम वीडियो की तरफ से रोहित को हरी झंडी मिल गई है। शो से जुड़े सूत्रों के अनुसार, निर्माताओं का दावा है कि रिलीज होने के एक सप्ताह के भीतर ही शो को लगभग एक करोड़ व्यू मिले। जिसे देखते हुए निर्माताओं ने इसके अगले सीजन को हरी झंडी दे दी है। रोहित की सिंघम, सिंबा और सूर्यवंशी फिल्मों की तरह यह शो भी पुलिस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हालांकि, रोहित इस शो की दुनिया को अपनी फिल्मों की दुनिया बिल्कुल अलग रखेंगे। अगले कुछ दिनों में शो के निर्माता इस पर निर्णय लेंगे कि अगले सीजन का कथानक क्या होगा और किन चीजों में उन्हें बदलाव करने की जरूरत है। इस शो के अगले सीजन की आधिकारिक घोषणा का इंतजार होगा, क्योंकि इससे पहले अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन जैसे सितारों के शो के दूसरे सीजन ठंडे बस्ते में डाले जा चुके हैं।

फिलहाल सिंघम अगेन को समय पर पूरा करने में जुटे हैं रोहित। फाइल

शूटिंग से चंद घंटों पहले करण को आया था शो के लिए बुलावा

किसी फिल्म या शो में कलाकारों की कास्टिंग प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। सही कलाकारों को चुनने में अक्सर महीनों लग जाते हैं। वही परिस्थितियां कई बार ऐसी भी बनती हैं कि निर्माताओं को आखिरी घंटों में कलाकार को चुनना पड़ता है। सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक मेहंदी वाला घर में मनोज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता करण मेहरा का शो से जुड़ना ऐसा ही रहा। धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण दैनिक जागरण से बातचीत में बताते हैं, 'इस शो की कास्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी, अगले दिन प्रोमो शूट होना था। शूटिंग शुरू होने में 24 घंटे भी नहीं बचे थे कि मेरे पास निर्माताओं का फोन आया। मैं इस शो के निर्माताओं शशि मित्तल और सुमित मित्तल से पहले से परिचित था। जब उनका फोन आया और उन्होंने मेरी भूमिका के बारे में बताया तो मेरे लिए उन्हें इन्कार करना मुश्किल हो गया। मैंने देखा कि मनोज की भूमिका बहुत अच्छी है और शो की सारी कहानी उसी के कंधों पर आगे बढ़ती है। शो में मेरी भूमिका के वर्तमान के साथ-साथ उसका अतीत भी दिखाया जाएगा, तो इसमें मेरा लुक भी उम्रदराज और युवा दोनों ही है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं प्रोजेक्ट से सबसे आखिरी पलों में ही जुड़ता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है के समय भी मैं शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले ही शो से जुड़ा था।'

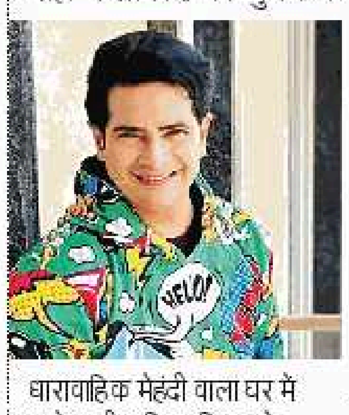

धारावाहिक मेहंदी वाला घर में मनोज की भूमिका निभा रहे हैं करण। (इंस्टाग्राम)@realkaranmehra

खानजादी से कैसा रिश्ता होगा, मिलकर पता चलेगा : अभिषेक

बिग बास 17 के पहले रनरअप हैं अभिषेक। (इंस्टाग्राम)@aebyborntoshine

कई बार मंजिल के नजदीक पहुंचकर भी वह नहीं मिल पाती है। यही हाल टीवी अभिनेता अभिषेक कुमार का रहा, जो बिग बास 17 के फिनाले में टाप 2 तक तो पहुंच गए, लेकिन ट्राफी नहीं जीत पाए। खैर, अभिषेक इस हार से दुखी नहीं हैं। उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि इस हार-जीत से मेरा लक्ष्य कभी हिला नहीं। मैं जब नौवीं कक्षा में था, तब से करियर में क्या करना है, उसको लेकर केंद्रित था। जब फिल्मों में भीड़ में खड़े होकर काम करता था, तब भी पता था क्या करना है। यही वजह है कि यहां तक पहुंच गया हूं। बिग बास के घर में अभिषेक के साथ उनकी पूर्व प्रेमिका ईशा मालवीय भी थीं। जिसके साथ वह कई बार भावनात्मक तौर पर टूटे भी थे। इसी बीच उनकी दोस्ती घर की एक और प्रतिभागी फिरोजा खान उर्फ खानजादी के साथ हुई। अब अभिषेक प्यार और रिश्तों पर भरोसा करने के लिए कितने तैयार हैं? इस पर वह कहते हैं कि दर्शकों को जो प्यार मिला उससे खुश हूं। जहां तक मेरे प्यार की बात है, तो उसके बारे में बाद में सोचूंगा। खानजादी मुझे पसंद हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में उनके साथ रिश्ता कैसे बनेगा, वह तो मिलकर पता चलेगा।

...इसलिए अटकी थी फिल्म स्वातंत्र्यवीर सावरकर

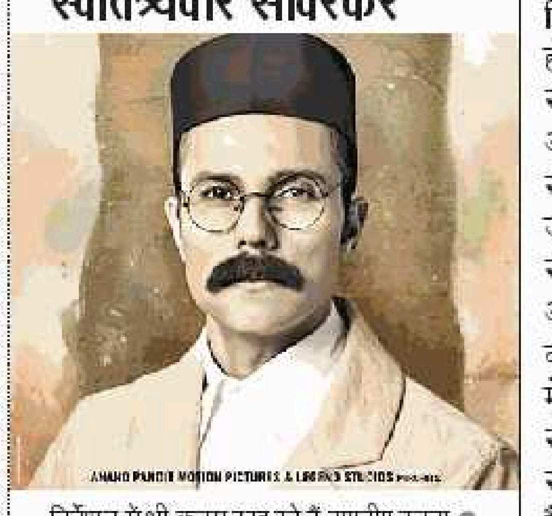

निर्देशन में भी कदम रख रहे हैं रणदीप हुड्डा ● मिडडे आर्काइव

साल 2022 में फिल्म निर्माता आनंद पंडित और संदीप सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की बायोपिक फिल्म स्वातंत्र्यवीर सावरकर की घोषणा की थी। अभिनय के साथ-साथ अभिनेता रणदीप हुड्डा ने फिल्म के निर्देशन की बागडोर भी अपने हाथों में ली। इस फिल्म को पिछले साल वीर सावरकर की जन्मतिथि यानी कि 26 मई को रिलीज करने की योजना थी। लेकिन फिर रिलीज से पहले रणदीप और निर्माताओं के आपसी मतभेदों के कारण फिल्म की रिलीज टल गई। जिसके बाद रणदीप ने फिल्म के जुड़े सारे इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी पर अपना अधिकार बताते हुए निर्माताओं को कानूनी नोटिस भी भेज दिया था। हालांकि, अब फिल्म की रिलीज के सारे रास्ते साफ हैं। इस बारे दैनिक जागरण से बातचीत में फिल्म के निर्माता संदीप सिंह बताते हैं, 'उस समस्या का समाधान हो चुका है। फिल्म इस साल की पहली छमाही में ही रिलीज हो जाएगी।'

फिल्म 'मैं' में खलनायक की भूमिका में होंगे मिलिंद

सिनेमा जगत में एक बार किसी भूमिका में लोकप्रिय हो जाने बाद कलाकारों की छवि भी उसी अनुसार स्थापित होने लगती है। माडल से अभिनेता बने मिलिंद गुनाजी के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। सिनेमा जगत में उनके हिस्से ज्यादातर स्याह भूमिकाएं ही आई है। हालांकि, अब वह अपनी भूमिकाओं और कहानियों को लेकर नए प्रयोग करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में इस साल उनके आगामी प्रोजेक्ट्स की सूची काफी लंबी है। इस बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में मिलिंद बताते है, 'एक फिल्म है फैसला, उसके बारे में मैं ज्यादा बोल तो नहीं सकता हूं, बस इतना बता सकता हूं कि वो एक बड़े राजनेता की बायोपिक फिल्म है। वह बहुत बड़े स्तर की फिल्म है। दूसरी फिल्म का नाम मैं है, इसमें अमित साध मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। इसमें मैं मुख्य खलनायक की भूमिका में हूं। फिल्म में सीमा बिस्वास, तिग्मांशु धूलिया जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। तीसरी फिल्म का नाम लव करूं या शादी है। मैंने हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर शूट किया है। इसके अलावा मेरे बेटे अभिषेक गुनाजी एक मराठी फिल्म रावण कालिंग निर्देशित कर रहे हैं। इसमें मराठी सिनेमा के कई बड़े सितारे हैं, मेरी इसमें बहुत दिलचस्प भूमिका है। इसकी शूटिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा फिल्म वेलमक टू जंगल और कुछ वेब सीरीज भी कतार में हैं।'

इस साल काफी लंबी है मिलिंद के आगामी प्रोजेक्ट्स की कतार ● @milindgunaji

एनिमल पार्क के पात्र होंगे और जटिल : रणबीर

पिछले साल अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल से दर्शकों को चौंका दिया था। यकीनन उन्होंने जो काम किया, उसके पीछे निर्देशक और लेखक संदीप रेड्डी वांगा की सोच और मार्गदर्शन था। संदीप ने कई मौकों पर कहा था कि वह ऐसा फिल्म लेकर आएंगे, जिसमें हिंसा खूब होगी। एनिमल में उसका नजारा देखने को मिला। अब एनिमल की कहानी को एनिमल पार्क में आगे बढ़ाने के लिए संदीप खासा आश्वस्त हैं। यह आत्मविश्वास उन्हें एनिमल की सफलता ने दिया है। रणबीर कपूर ने एनिमल पार्क के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'पहले पार्ट की कहानी कम ही लोगों को पता थी। कई ऐसी चीजें फिल्म में थीं, जिसे संदीप ने किसी को नहीं बताया था। उन्होंने एनिमल पार्क फिल्म के एक या दो सीन मुझे सुनाए थे। लेकिन अब एनिमल की सफलता के बाद उनमें हिम्मत आ गई है कि वह अब फिल्म के पात्रों की गहराइ में जाएं, उन्हें और स्याह व जटिल बनाएं।' रणबीर ने आगे कहा, 'एनिमल को लेकर कई टिप्पणियां मैंने पढ़ी जिसमें कहा गया था कि टाक्सिक मैस्क्युलिनिटी (विषाक्त पुरुषत्व) दिखाया गया है। लेकिन इसी बहाने इस मुद्दे पर बातचीत तो शुरू हुई। अगर फिल्मों के जरिये यह चीजें नहीं दिखाएंगे, तो उस पर बातचीत कैसे शुरू होगी।'

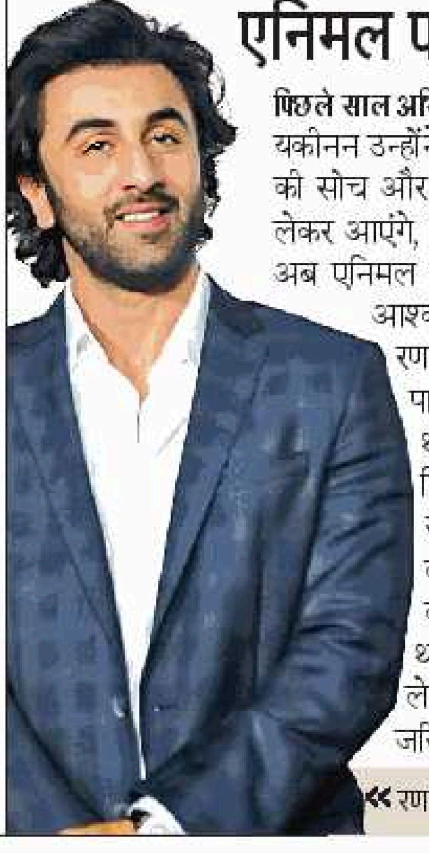

« रणबीर के साथ एनिमल पार्क के एक दो सीन ही शूट हुए थे ● मिडडे आर्काइव

****